चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

11 नवंबर–17 नवंबर 2013

यह तीसरा मोर्चा नहीं है

जब 14 पार्टियों के 17 नेताओं ने एक दूसरे का हाथ उठाकर यह फोटो खिंचवाई तो वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा की याद ताज़ा हो गई. ऐसी ही तस्वीरें उन दिनों अख़बारों में छपा करती थीं. वो अलग वक्त था. आज का दौर अलग है. वी पी सिंह कई राजनीतिक दलों को एकजुट करने में सफल हुए थे. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सफल आंदोलन किया और कांग्रेस विरोध की लहर पैदा की थी. वह तीसरे मोर्चे का एक सफल प्रयास साबित हुआ. कांग्रेस हारी और वी पी सिंह प्रधानमंत्री बने. इस तस्वीर में नेता तो साथ दिख रहे हैं, लेकिन इनमें न कोई प्रतिबद्धता है, न दूरदर्शिता है, न योजना है और न ही एकता है. यह तस्वीर अपने आप में कई विरोधाभास लिए है, इसलिए तीसरा मोर्चा बनने से पहले ही टूटता नज़र आ रहा है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

30 अक्टूबर को देश की राजनीति में एक हलचल हुई. इस हलचल के केंद्र में दिल्ली का तालकटोरा इनडोर स्टेडियम था. सवेरे से ही पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था. स्टेडियम के अंदर खड़े होने की जगह नहीं थी. कई भूतपूर्व मंत्री व वर्तमान सासंद खड़े थे, क्योंकि उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली. जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे, उतने ही बाहर थे. देश भर का मीडिया यहां मौजूद था. क़रीब पचास टीवी चैनलों के कैमरे लगातार वहां की गतिविधियों को टीवी स्टूडियो में लाइव भेज रहे थे. स्टेज पर देश की राजनीति को बदलने का माद्दा रखने वाले नेता भी मौजूद थे. लगा कि आज कोई बड़ी ख़बर आने वाली है. लेकिन जैसे-जैसे नेताओं ने एक के बाद एक भाषण देना शुरू किया, वैसे-वैसे इस मीटिंग की छटा व महिमा धूमिल होती चली गई. शाम साढ़े पांच बजे के क़रीब जब प्रस्ताव पारित करने का समय आया, तब कई नेता जा चुके थे. स्टेडियम ख़ाली पड़ा था. लोगों का जैसा रिस्पॉन्स स्टेडियम के अंदर था, वही बाहर भी था. शाम ढलते-ढलते मीडिया ने भी इस मीटिंग को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि इस मीटिंग से जो उम्मीद थी वह हो न सका. तीसरा मोर्चा न तो बन सका और न ही ऐसा संदेश मिला कि भविष्य में कोई तीसरा मोर्चा बन सकता है. यह सम्मेलन दरअसल दिशाहीनता का शिकार हो गया.

यह सम्मेलन वाममोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन का नाम था पीपुल्स युनिटी अगेंस्ट कम्युनलिज़्म. इसकी अध्यक्षता अलीगढ़ विश्वविद्यालय व वामपंथी विचारधारा के समर्थक प्रोफेसर इरफान हबीब ने की. इसमें कुल 14 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और स्टेज पर कुल 17 नेता मौजूद थे. इसमें कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, लेकिन इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने एक सिप-हसालर को ज़रूर भेजा. उसी तरह से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अपने प्रतिनिधि को इस सम्मेलन में भेजा था. सबसे पहले सीताराम येचुरी ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य देश को सांप्रदायिकता से बचाना है, क्योंकि इस बार ख़तरा बड़ा है. उनका इशारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था. इस सम्मेलन में एक मसौदा भी पास होना था. उसे पहले अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ा गया, जिससे कई सवाल उठते हैं.

इस मसौदे में लोगों को सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ एकजुट होने की अपील की गई. लेकिन लोग कैसे एकजुट होंगे, यह इस मसौदे में नहीं था. सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग कौन हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो इस ज़हर को फैला रही हैं वो भी ग़ायब था. सांप्रदायिकता से कैसे लड़ा जाए, उसका भी कोई नक्शा इस मसौदे में नहीं था. वैसे यह माना जा रहा था कि यह कोई तीसरे मोर्चे की पहल है. इसे एक गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा गुट की तैयारी के रूप में देखा जा रहा था. इसमें बातें सिर्फ़ सांप्रदायिकता की थीं, लेकिन मसौदे में न तो नरेंद्र मोदी का नाम था और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम था. इसका क्या मतलब है? साधारण तौर पर होता यह है कि मसौदे को लेकर पहले चर्चा होती है. अनुमान यही लगाना चाहिए कि इसमें शामिल होने वाली पार्टियों से मसौदे पर बातचीत हुई होगी और यह फ़ैसला लिया गया होगा कि किसी संगठन या नेता का नाम मसौदे में नहीं होना चाहिए. अब यह सवाल तो बनता ही है कि जिन शक्तियों के ख़िलाफ़ आप लड़ने के लिए एकजुट हुए, अगर उसका नाम लेने से भी बचेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा. राजनीति में अंधेरे में तीर चलाने से काम नहीं चलता. हैरानी तो इस बात की है कि इनमें से कई नेता वीपी सिंह के तीसरे मोर्चे में शामिल थे. उन्हें मालूम है कि उस वक्त नेता स्टेज से किस तरह से राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ आग उलगते थे.

बड़े नेताओं में सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माइक संभाला. उन्होंने तीसरे मोर्चे की ज़रूरत को ही नकार दिया. उन्होंने सिर्फ़ इसे नकारा ही नहीं, बल्कि मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह को ज्ञान भी देने लग गए कि सांप्रदायिकता से कैसे लड़ा जाता है. उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों की तुलना भागलपुर दंगों से की और अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुट गए. तीसरे मोर्चे के शुरुआती भाषण में ही उन्होंने तीसरे मोर्चे का टायर पंचर कर दिया. इसकी वजह साफ है कि नीतीश कुमार ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनना चाहते होंगे, जिसके वो सर्वसम्मत नेता नहीं हैं. नीतीश कुमार ने पूरे भाषण में यह बताने की कोशिश की कि वो स्टेज पर बैठे बाकी सभी नेताओं से ज्यादा सेकुलर हैं. मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, बस इशारों में बात की.

जब मुलायम सिंह की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि यहां तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो भी किसी का नाम नहीं लेंगे. उनके कहने का मतलब यह था कि इस सम्मेलन में कोई न तो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है और न ही कोई सांप्रदायिकता फैलाने वाले हिंदू संगठन का नाम ले रहा है. उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी पार्टी जमीन पर सांप्रदायिक ताकतों से 1987 से लड़ रही है. एक दिन पहले उन्होंने आजमगढ़ में बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया था, इसलिए उनके भाषण में जोश और विश्वास था. मुलायम सिंह यादव की राजनीति योजना भी साफ है. वो ख़ुद को एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं. नीतीश कुमार की तरह मुलायम सिंह भी ऐसे किसी मोर्चे के हिस्सा नहीं होंगे, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में न पेश किया जाए. इस सम्मेलन के दो दिन बाद लखनऊ में उन्होंने तो एक ऐसा बयान दिया जिससे इस सम्मेलन के औचित्य पर ही सवाल खड़ा हो गया. मुलायम सिंह ने यह कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि और कश्मीर के मुददे को छोड़ दे और मुसलमानों के खिलाफ बयान देना बंद कर दे तो उनके बीच की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी. समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बयान के बारे में यह कहा कि लोकसभा चुनाव

(शेष पृष्ठ 2 पर)

तीसरे मोर्चे के लिए हुए सम्मेलन में शामिल होने वाली पार्टियों के प्रतिनिधि

पार्टी	नेता
बीबीएम	श्री प्रकाश आंबेडकर
झाविमो	बाबू लाल मरांडी
अगप	प्रफुल्ल कुमार महंत
बीजू जनता दल	वैद्यनाथ पांडा
जदयू	शरद यादव, नीतीश कुमार, के सी त्यागी
सपा	मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव
जद (एस)	एच डी देवेगौड़ा
अन्नाद्रमुक	के एम थंबीदुरई
माकपा (एम)	सीताराम येचुरी, प्रकाश करात
राकांपा	डी पी त्रिपाठी
समाजवादी जनता पार्टी	कमल मोरारका
आरएसपी	क्षिति गोस्वामी
वेस्ट बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	विमान बोस
सीपीआई	एस सुधाकर रेड्डी
एजीपी	अतुल बोरा
फॉरवर्ड ब्लॉक	देबव्रत विश्वास

अभी होंगे कई और ख़ुलासे

03

विदेशी दौरे और असफल विदेश नीति

05

कैमूर की पहाड़ियों को बचाने की जंग

07

साई की महिमा

12

यह तीसरा मोर्चा नहीं है

पृष्ठ एक का शेष

में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, इसे लेकर मुलायम सिंह को संदेह है. उन्हें लगता है कि कई क्षेत्रीय पार्टियों की समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है और तीसरे मोर्चे के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं. नीतीश कुमार व नवीन पटनायक के साथ–साथ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के साथ शरद यादव भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. इसलिए अगर ज्यादा सीटें नहीं तो मुलायम सिंह तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं होंगे. वो भाजपा या कांग्रेस को समर्थन देकर खुद व अपने परिवार के लोगों के लिए मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे.

इस सम्मेलन में उनके अलावा भूतपूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के एच डी देवेगौड़ा, जेडीयू के शरद यादव व केसी त्यागी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री व असम गण परिषद के मुखिया प्रफुल्ल कुमार महंत, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विकास पार्टी के अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात, बीजेडी के बैद्यनाथ पांडा शामिल थे. इसके अलावा मंच पर कमल मोरारका, प्रकाश अंबेडकर, एम थंबीदुरई, रामगोपाल यादव, अमरजीत कौर, डीपी त्रिपाठी, क्षिति गोस्वामी, बिमान बोस, एस सुधाकर रेड्डी, देबव्रत विश्वास, अतुल बोटा मौजूद थे. इनमें से कई लोगों ने भाषण दिया और कई लोगों ने वक्त की कमी की वजह से भाषण नहीं दिया और जिन्होंने भाषण दिया वो राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता है. जैसे कि सीपीआई के नेता एबी वर्धन ने मुलायम सिंह की समाजवादी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर के दंगे में बेघर हुए लोगों को मुआवज़ा की बात उठा दी और शिविर में रह रहे लोगों को अपने घर वापस भेजने की व्यवस्था करने की मांग रख दी. बाबू लाल मरांडी ने तो विषय को मोड़ दिया. उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता से ज्यादा लोगों के सामने मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे लड़ने की ज़रूरत है. वहीं सीपीएम के जनरल सिक्रेटरी ने आरएसएस पर हमला किया, लेकिन असम के नेता प्रफुल्ल महंत ने असम की समस्याओं पर बात की. ओडिशा के बीजेडी के नेता बैद्यनाथ पांडा ने कहा कि इस देश को इस देश को सेकुलरवाद के साथ–साथ विकास की भी ज़रूरत है. कहने का मतलब यह है कि इस सम्मेलन ने सब नेताओं ने अपनी बात रखी किसी ने तीसरे मोर्चे के गठन, उसकी ज़रूरत और उद्देश्य पर साफ–साफ बातें नहीं की. जिन नेताओं ने सम्मेलन के बाद टीवी रिपोर्टरों से बात की, किसी ने तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर आशाजनक बयान नहीं दिए. सीताराम येचुरी ने टीवी रिपोर्टरों को जो जवाब दिया, उसने इस सम्मेलन की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने बताया कि जिस तरह क्रिकेट में दूसरा होता है, उसी तरह यह सम्मेलन राजनीति का दूसरा है. क्रिकेट में दूसरा गेंद का मतलब बल्लेबाज़ को धोखा देने वाली ऐसी गेंदबाज़ी, जिसमें गेंदबाज़ ऑफस्पिन करता है, लेकिन वो लेगस्पिन बन जाता है.

भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह सवाल हर उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कौंध रहा है, जिसकी रुचि राजनीति में है. क्या वो नरेंद्र मोदी होंगे? क्या राहुल गांधी होंगे? या फिर कोई और? यह तो तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो राहुल ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री होंगे. अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो नरेंद्र मोदी बनेंगे. हक़ीक़त यह है कि कांग्रेस पार्टी हताश है. उसकी साख़ ख़त्म हो चुकी है. रिकार्डतोड़ भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोज़गारी से लोग नाराज़ हैं. अब कोई चमत्कार ही हो जाए तो कांग्रेस 2014 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

आज के राजनीतिक हालात में किसी भी मोर्चे के लिए यह ज़रूरी है कि उसका एक नेता हो. वो भी सर्वमान्य, जो मोदी और राहुल गांधी को चुनौती दे सके. इस मोर्चे को कांग्रेस के भ्रष्टाचार व बीजेपी की सांप्रदियकता से मुक़ाबला करना होगा. इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले मोर्चे में शामिल पार्टियों के बीच के प्रतिद्वंद्व व विरोधाभास को चुनाव से पहले ख़त्म करना होगा. उस मोर्चे का एक आर्थिक एजेंडा होना भी ज़रूरी है. महंगाई ख़त्म करने के उपाय बताने होंगे. युवाओं को लुभाने के लिए प्रोग्राम भी ज़रूरी है. जल–जंगल–ज़मीन के मुद्दे पर भी वैचारिक एकजुटता ज़रूरी है. विकास का एक मॉडल पेश करना होगा. युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेगा और उनके हुनर का इस्तेमाल आने वाली सरकार कैसे करेगी, इसकी रूपरेखा भी सामने रखनी होगी. भ्रष्टाचार से कैसे लड़ना है, इसका उपाय बताना होगा. सांप्रदायिकता से कैसे लड़ना है, इसका ब्लुप्रिंट भी जनता के सामने रखना होगा. देश की जनता राजनीतिक दलों के उपदेश से थक चुकी है. 2013 का भारत एक्शन चाहता है. उसे इस बात का भरोसा होना ज़रूरी है कि आने वाली सरकार देश में आमूलचूल परिवर्तन करेगी. वर्ना सिर्फ़ सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ एकजुट होने से मोर्चा तो बनाया जा सकता है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं है.

भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह सवाल हर उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कौंध रहा है, जिसकी रुचि राजनीति में है. क्या वो नरेंद्र मोदी होंगे? क्या राहुल गांधी होंगे? या फिर कोई और? यह तो तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो राहुल ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री होंगे. अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो नरेंद्र मोदी बनेंगे. हक़ीक़त यह है कि कांग्रेस पार्टी हताश है. उसकी साख़ ख़त्म हो चुकी है. रिकार्डतोड़ भ्रष्टाचार, मंहगाई व बेरोज़गारी से लोग नाराज़ हैं. अब कोई चमत्कार ही हो जाए तो कांग्रेस 2014 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है. मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की समस्या अलग है. बीजेपी की देश के कई राज्यों में कोई मौजूदगी ही नहीं है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर गठबंधन बनाना भी मुश्किल हो गया है. अभी तक आई तमाम सर्वे रिपोर्ट यही बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी 160 सीटें और कांग्रेस पार्टी 100 सीटें जीत सकती है. तो अब सवाल है कि 280 सीटें कौन जीतेगा? साफ है ये सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाएंगी.

देश के लोगों के सामने दो मुख्य चुनौतियां हैं. एक तो सरकार को प्रभावशाली बनाने की चुनौती है और दूसरा सांप्रदायिकता के ख़तरे से भी लड़ना है. ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में एक गैरकांग्रेस–गैरभाजपा गठबंधन की जगह तो बनती है लेकिन उसका नेतृत्व कौन करेगा? गठबंधन की विचाधारा क्या होगी? आर्थिक नीति क्या होगी? विकास का नज़रिया क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका उत्तर वाममोर्चा द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में तो नहीं मिला है. भारत की राजनीति का चरित्र समंदर में उठने वाले साइक्ल–ोन यानी चक्रवात की तरह है. यह पता नहीं चलता कि ये कब कहां से उठ जाए और किस रास्ते चल पड़े और बवंडर मचा दे. क्या 2014 के पहले कोई राजनीतिक चक्रवात उठेगा? क्या भारत की राजनीति में कोई तूफानी फेरबदल होने की उम्मीद है? क्या कोई ईमानदार व लोकप्रिय नेता उभरेगा जो कांग्रेस व बीजेपी को चुनौती देने में कामयाब हो सके? शायद पूरब से कोई सूरज उगे और देश के राजनीतिक आकाश पर छा जाए. ■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 36
दिल्ली, 11 नवंबर–17 नवंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को झटका

कर्नाटक की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को तब झटका लगा, जब राज्य सरकार ने राज्य के लोकायुक्त को एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी पी बालीगर के विरुद्ध जमीन आवंटन की अधिसूचना रद्द करने के दो मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया. जबकि स्पष्ट तौर पर पूर्ववर्ती येदियुरप्पा सरकार के दौरान बालिगर के ऊपर बहुत से आरोप लगे थे लेकिन कर्नाटक में सरकार बदल जाने के बाद भी वह शक्तिशाली बने हुए हैं.

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जिन 17 लोगों के नाम पर प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के लिए विचार हो रहा है उनमें से एक नाम 1980 बैच के आईएएस अधिकारी बालिगर का भी नाम शामिल है. इस वजह से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके सहयोगियों ने कैबिनेट मीटिंग में लोकायुक्त को बालिगर के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया. इसके अलावा लोकायुक्त ने प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश नीरानी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन इस मामले में भी सरकार अनिर्णय की स्थिति में दिखी.■

ममता का नया फरमान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए एक पूर्णत: केंद्रीकृत प्रणाली की संकल्पना की है. सामान्यत: ममता जो चाहती हैं वह पा लेती हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक नया फरमान जारी किया है. सरकारी कार्यों के संबंध में विशेष सचिव स्तर के जो भी अधिकारी देश–विदेश यात्रा पर जाएंगे. उन्हें इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अंतिम मुहर लगवानी होगी. मुख्यमंत्री की मंशा बिलकुल साफ है. उन्होंने 1992 बैच के एक आईएएसस अधिकारी बरुण रॉय को स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक(सीएमडी) को पद से हटा दिया है वह भी इसलिए क्योंकि वह औपचारिकताएं पूरी किए बगैर छुट्टियां बिताने ऑस्ट्रेलिया चले गए थे. एक समय रॉय को ममता का करीबी माना जाता था. उन्हें ममता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्त से वापस बुला लिया था. क्या दूसरे नौकरशाहों को इससे सीख मिलेगी? ■

आगे मार्ग अवरुद्ध है

ऐसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय छिब्बर के द्वारा सफाई देने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण(एनएचएआई) द्वारा चलाए जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों के अनुबंधों को फिर से पुनर्गठित करने की अफवाहें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एनएचएआई इस कदम के खिलाफ है. सूत्रों के अनुसार मंत्रालय एनएचएआई में हुए स्थानांतरण और प्रोन्नति के मामलों में असहमति भी है. मंत्रालय का रुख है कि एनएचएआई ने केंद्रीय सेवा नियमों का उल्लंघन करके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियां की हैं. एनएचएआई के अध्यक्ष आर पी सिंह को आदेश दिया गया है कि वे संस्था से जुड़े नौकरशाहों के स्थानांतरण और प्रमोशन से जुड़े सभी मामलों को मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजें. जब मंत्रालय और एनएचएआई प्रशासनिक मुद्दों को लेकर तरकार हो रही है इसका असर सड़कों के निर्माण पर पड़ रहा है इस वजह से सरकार सड़क निर्माण के लक्ष्यों को समय से पूरा भी नहीं कर पा रही है. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

राघवन नए राजदूत नियुक्त

1979 के आईएफएस पीएस राघवन को रूस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है. वे अजय मलहोत्रा के उत्तराधिकरी के रूप में जल्द ही पदभार संभालेंगे. वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव हैं.

देवेंद्र भूषण यूपीएससी के सचिव बने

अमरजीत सिंह कि नियुक्ति रद्द होने के चलते आईएएस देवेंद्र भूषण गुप्ता को संघ लोक सेवा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है.

जेएन मिश्रा पुर्तगाल के राजदूत नियुक्त

1982 बैच के आईएफएस अधिकारी जितेंद्र नाथ मिश्रा को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है. वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

सिद्धार्थ अतिरिक्त सीईओ बने

1983 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस सिद्धार्थ को एक साल के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष न्यास के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह वर्तमान मेंवाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव हैं.

राजन अतिरिक्त मुख्य सचिव बने

चुनाव आयोग ने चुनाव तक के लिए राजस्थान के मुख्य सचिव को अतिरिक्त प्रभार देने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सी एस राजन के नाम को मंजूरी दी है. राजन वर्तमान में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

> नीरा राडिया देश के कई बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का कारोबारी और राजनीतिक प्रबंधन देखती रही हैं, जिसके लिए नीरा ने समय–समय पर सरकारी महकमों, केन्द्रीय मंत्रालयों में ज़रूरत और हितों के मुताबिक़ नीतियों और उनके कार्यान्वयन में मनमाफ़िक फेरबदल करवाया है.

नीरा राडिया टेपकांड

अभी होंगे कई और ख़ुलासे

नीरा राडिया की टेलीफोन से जुड़ी बातों की टैपिंग से जो बातें सामने आई हैं, उसे जानकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री तथा अनिल अंबानी के एडीएजी घराने पर सरकार की कृपादृष्टि, दलालों की कार्यशैली, टेलीकॉम सेक्टर, उड्डयन एवं अन्य क्षेत्रों में मंत्रियों व अधिकारियों को ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से दी गई रिश्वत की जानकारी नीरा के फोन टैपिंग से मिली. इस जानकारी से हतप्रभ सर्वोच्च न्यायालय ने उसी टैप को आधार बनाकर इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है.

रूबी अरुण

देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के शक में देश की शीर्ष औद्योगिक कम्पनियों की सबसे ताक़तवर लॉबीइस्ट रहीं नीरा राडिया के फोन की टैपिंग 16 नवम्बर, 2007 को वित्त मंत्रालय के हलफ़नामे के आधार पर शुरू की गई थी. तब किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि इस फोन टैपिंग की जांच से देश के कुछ मीडिया हाउसेज़, सत्ता और कोर्पोरेट लॉबी के गठजोड़ का हैरान कर देने वाला ख़ुलासा होगा, जिससे देश के कई जाने-माने उद्योगपति, मीडिया के कुछ बड़े चेहरे और कई केन्द्रीय मंत्री-राजनेता, एक ही हम्माम में नंगे खड़े नज़र आएंगे. नीरा राडिया, शासकीय अधिकारियों एवं रिलायंस समूह के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा जानकर सुप्रीम कोर्ट भी सकते में है. सरकारी अधिकारियों और उद्योपतियों ने मिलकर ग़लत तरीक़े से सरकार और शासन के साथ अरबों रुपयों की धोखाधड़ी की है, इसका ख़ुलासा राडिया टेप कांड से हुआ है. इस टेप की मार्फ़त जो सबूत सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं, उसकी बिना पर इस बात की संभावना है कि सीबीआई की जांच से जल्द ही रिलायंस समूह की गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर सकती है.

अब, जबकि सीबीआई ने नीरा राडिया टेप मामले में अभी तक तेरहवीं इन्क्वायरी दर्ज कर ली है और इस बाबत इनकम टैक्स के एक सीनियर ऑफिसर से पूछताछ भी शुरू कर दी है, तब और भी ऐसे कई सनसनीखेज़ ख़ुलासे हो रहे हैं, जो आने वाले दिनों में भारत के राजनीतिक, औद्योगिक और मीडिया जगत में बवंडर खड़ा कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत भी टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से हो चुकी है. नीरा राडिया पर महज़ टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में ही शामिल होने का आरोप नहीं लगा था, बल्कि वे बेजा तरीक़े से लौह अयस्क खदान और कोयला ब्लाक आबंटन जैसे आरोपों से भी जूझ रही हैं. नीरा राडिया के इन टेपों में राडिया की विभिन्न राजनेताओं, नौकरशाहों तथा उद्योगपतियों से टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड है. न्यायालय ने सीबीआई से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दो महीने में पेश करने को कहा है. जब नीरा राडिया के फोन टैप करने का आदेश इनकम टैक्स के डायरेक्टरेट जनरल ने दिया था, तब नीरा राडिया पर यह आरोप था कि उन्होंने सिर्फ़ नौ साल की छोटी सी अवधि में 300 करोड़ रुपयों का साम्राज्य ग़लत तरीक़े से खड़ा कर लिया था. साल 2008 में नीरा राडिया की गतिविधियों के बारे में शिकायत मिलने पर आयकर विभाग ने उनके फोन को सर्विलांस पर डाल दिया था. बातचीत में टूजी स्पेक्ट्रम आबंटन और पूर्व संचार मंत्री ए राजा का जिक्र होने के कारण सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जांच भी की थी. लेकिन टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले से सीधा जुड़ा नहीं होने के कारण राडिया को क्लीन चिट मिल गई थी. मज़ेदार बात ये यह है कि आयकर विभाग ने नीरा के फोन की शुरुआती टैपिंग, कर चोरी की संभावना के मददेनज़र की थी.

आयकर विभाग ने 2008-9 के दौरान शासन कोयला आवंटन मुद्दे पर एक समाचार पत्र के संपादक के साथ राडिया की बातचीत को टैप किया था. उसी टैप को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. राडिया पर पत्रकारों और संपादकों पर दबाव बनाया. टैप में उनकी बातचीत को कंपनियों को स्पेक्ट्रम आबंटन, प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन और अंबानी बंधुओं के बीच क़ानूनी लड़ाई जैसे शीर्षकों के तहत अलग-अलग रखा गया है.

सीबीआई ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पूर्व प्रमुख प्रदीप बैजल से राडिया की बातचीत के मामले में भी प्राथमिक जांच (पीई) का मामला दर्ज किया है. इस बातचीत में कथित तौर पर पाइपलाइन सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पर बैजल की नियुक्ति की बातें की गई हैं, ताकि अपनी तैनाती के बाद वह कथित तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ़ायदा पहुंचा सकें. सीबीआई ने इस पीई में बैजल और राडिया को नामजद किया है. सीबीआई ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस द्वारा बीएसई और ट्राई को घोषित उपभोक्ता डेटा बेस में कथित गड़बड़ी से जुड़ी राडिया की बातचीत के मामले में भी प्राथमिक जांच शुरू की है और इस मामले में रिलायंस कम्यूनिकेशंस को नामजद किया गया है.

सीबीआई के आरोप के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस सर्वोच्च न्यायालय की जांच के दायरे में आ गई है. सीबीआई का आरोप है कि आरकॉम ने लाइसेंस शुल्क बचाने के लिए

> **नीरा राडिया के इन टेपों में राडिया की विभिन्न राजनेताओं, नौकरशाहों तथा उद्योगपतियों से टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड है. न्यायालय ने सीबीआई से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दो महीने में पेश करने को कहा है. जब नीरा राडिया के फोन टैप करने का आदेश इनकम टैक्स के डायरेक्टरेट जनरल ने दिया था, तब राडिया पर यह आरोप था कि उन्होंने सिर्फ़ नौ साल की छोटी सी अवधि में 300 करोड़ रुपयों का साम्राज्य ग़लत तरीक़े से खड़ा कर लिया था. साल 2008 में नीरा राडिया की गतिविधियों के बारे में शिकायत मिलने पर आयकर विभाग ने उनके फोन को सर्विलांस पर डाल दिया था**

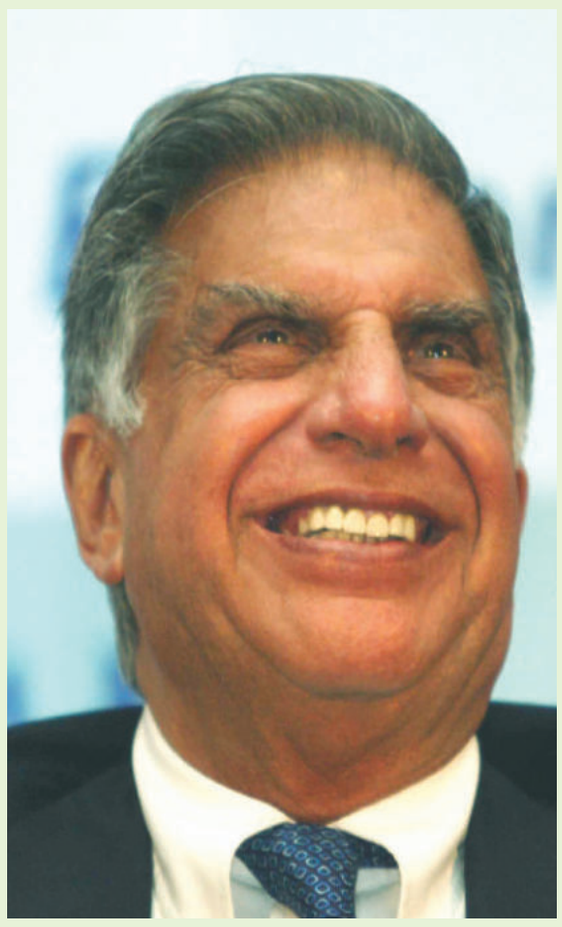

केवल अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) को कोयला ब्लॉक आवंटित कराने के भी आरोप हैं.

टाटा समूह इस्पात क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेशक है और झारखंड में लौह अयस्क के खदानों का एक भी आबंटन टाटा स्टील के हितों को प्रभावित कर सकता था. इससे पहले, लौह अयस्क खदानों के लिए एडीए समूह के आवेदन को जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि राडिया टैप मामले से इस मुद्दे का कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखा था. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अब इसे खनन मंत्रालय के पास भेज दिया है, ताकि मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी पूरे मामले पर ग़ौर करके उचित कार्रवाई कर सकें.

रिलायंस पावर को मध्य प्रदेश के शासन स्थित उसके अल्ट्रा मेगा बिजली संयंत्र (यूएमपीपी) के लिए कोयला खदान आवंटन पर न केवल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उंगली उठाई है, बल्कि कॉरपोरेट लॉबीइस्ट नीरा राडिया ने भी अपने बयान में हैरतंगेज़ खुलासा किया है. टाटा समूह और अन्य कंपनियों के लिए लॉबीइंग करने वाली राडिया ने बताया है कि सरकार से अतिरिक्त कोयले के इस्तेमाल के लिए मंज़ूरियां हासिल करने के लिए उनकी कंपनी रिश्वतखोरी और दबाव का इस्तेमाल करती थी.

नीरा राडिया और कई जानीमानी हस्तियों के बीच हुई बातचीत के टैप किए गए हिस्सों से जुड़े चार मुद्दों की जांच सीबीआई ने शुरू कर चुकी है. राडिया पर आरोप है कि वह टाटा पावर और मुकेश अंबानी जैसे अपने ग्राहकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और स्टॉक एक्सचेंजों को अपने ग्राहकों की संख्या से संबंधित ग़लत आंकड़े दिए थे.

इस सम्बन्ध में तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा ने 2009 में लोकसभा में भी कहा था कि आरकॉम और उसकी अन्य सहायक इकाइयों ने भी 2006-07 और 2007-08 के दौरान ट्राई को अपने राजस्व की ग़लत जानकारी दी, ताकि लाइसेंस शुल्कों के भुगतान से बचा जा सके. इस दूरसंचार कंपनी ने क़रीब 1000 से 1500 करोड़ रुपये कम राजस्व की जानकारी दी, जिससे सरकारी ख़जाने को क़रीब 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

दूरसंचार ऑपरेटरों को बतौर लाइसेंस शुल्क उनके कुल समायोजित राजस्व (एजीआर) की एक फ़ीसदी रकम का भुगतान करना था. इसलिए कम राजस्व दिखाकर लाइसेंस शुल्क में कमी की जा सकती थी. ट्राई ने 2009 में दूरसंचार विभाग को 5 ऑपरेटरों के 2006 से 2008 के वित्तीय बहीखातों का विशेष ऑडिट करने के लिए कहा था. दूरसंचार नियामक ने आशंका जताई थी कि इस दौरान इन ऑपरेटरों ने अपने राजस्व के बारे में संभवत: ग़लत जानकारी दी है. सरकारी ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में आरकॉम पर आरोप लगाया कि इस दौरान कंपनी ने लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क में क़रीब 315 करोड़ रुपये की चोरी की है. आरकॉम ने अपने समूह की दो कंपनियों मैक्रोनेट प्राइवेट लिमिटेड और इन्फ्रेंस सिस्टम्स लिमिटेड को एक्सपायर्ड प्रीपेड कार्ड बेचकर क़रीब 379 करोड़ रुपये की ठगी की. इसके अलावा आरकॉम पर 2007-8 में 2,915 करोड़ रुपये कम राजस्व दर्ज करने का भी आरोप है. यह ऑडिट रिपोर्ट 2009 में दूरसंचार विभाग को सौंप दी गई थी. नीरा राडिया और रतन टाटा के बीच हुई बातचीत की टैपिंग के दौरान केवल आरकॉम के वित्तीय खातों की विशेष जांच चल रही थी. लेकिन अगले छह से आठ महीनों के दौरान दूरसंचार विभाग ने स्वतंत्र एजेंसियों के जरिये सभी दूरसंचार कंपनियों के बहीखातों की विशेष जांच कराने का निर्णय लिया. इस क्रम में विभाग ने जनवरी 2012 में भारती एयरटेल, वोडाफोन, आरकॉम, आइडिया सेल्युलर और टाटा टेलीसर्विसेज को नोटिस भेजा, जिसमें 2006 से 2008 के बीच ग़लत राजस्व आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया गया था.

दरअसल, नीरा राडिया देश के कई बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का कारोबारी और राजनीतिक प्रबंधन देखती रही हैं, जिसके लिए नीरा ने समय-समय पर सरकारी महकमों, केन्द्रीय मंत्रालयों में ज़रूरत और हितों के मुताबिक़ नीतियों और उनके कार्यान्वयन में मनमाफ़िक फेरबदल करवाया है. नीरा की चार कंसल्टेसी कम्पनियां हुआ करती थीं, जिनके ज़रिये नीरा का साम्राज्य चलता था. नीरा, स्टार टीवी, टाटा समूह और यूनिटेक की राजनीतिक और सरकारी धंधेबाज़ी संभालती थीं तो नियोकॉम टेलीकॉम कि मार्फ़त मुकेश अम्बानी के रिलायंस समूह का राजनीतिक जोड़-तोड़ देखती थीं. नीरा ने नियोसिस नाम कि कंपनी कि शुरुआत ही इसलिए की थी कि वे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को ज़रिया बना कर उर्जा, उड्डयन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम आदि मंत्रालयों के कामों को अपने क्लायन्ट्स को किसी भी तरीक़े से दिलवा सकें, चाहे इसके लिए उन्हें मंत्रियों के मंत्रालय ही क्यों न बदलवाने पड़े हों. इसके लिए नीरा ने सभी पार्टियों में अपनी घुसपैठ बना रखी थी. न सिर्फ़ भाजपा के अनन्त कुमार, पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, बल्कि वामदल के प्रकाश करात सीटू के नेता भी नीरा के एक इशारे पर सही-ग़लत कुछ भी कर देने को राज़ी रहते थे. यह सब नीरा द्वारा दी गई रिश्वत का कमाल था. पत्रकार बरखा दत्त, वीर सांघवी, जहांगीर पोचा, अभय छजलानी जैसे मीडिया के बड़े नामों को नीरा ने अपना मोहरा बना रखा था, जिन्हें आलीशान गाड़ियां, घर, विदेश यात्राओं आदि का उपहार देकर ख़ुश रखा करती थीं. नीरा की शक्ति का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाटा के सिंगुर प्रोजेक्ट के अधर में लटक जाने के बाद उन्होंने अपने सूत्रों और संपर्कों का इस्तेमाल कर नैनो प्रोजेक्ट को गुजरात में ट्रांसफर करा दिया.

बहरहाल, ये सभी बातें तथ्यों समेत सुप्रीम कोर्ट में टैपों की शक्ल में जमा की जा चुकी हैं और इसके कागज़ी दस्तावेज़ भी जुटाए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब सीबीआई, उसे दिए गए दो महीने की अवधि के अन्दर सभी प्रमाणों के साथ कोर्ट में पेश होगी, तो एक बार फिर देश के मीडिया, सियासी और औद्योगिक जगत में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि कई बड़े और नामचीन लोग न सिर्फ़ क़ानून की गिरफ़्त में आएंगे, बल्कि देश के सामने उनका असल चेहरा भी सामने आएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

माले के महासचिव दीपांकर ने ख़बरदार रैली के दौरान यह संकेत दिया कि वे लालू के प्रति नरम ज़रूर हैं. हालांकि, भाजपा कांग्रेस और इसके साथ जाने वालों से समान दूरी बनाए रखने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि चारा घोटाले को सिर्फ़ लालू से ही जोड़कर क्यों देखा जा रहा है. जदयू के सांसद जगदीश शर्मा और भाजपा नेता ध्रुव भगत को भी सज़ा मिली है, यह भी बराबर तरीक़े से लोगों को बताया जाना चाहिए.

हुंकार रैली में राजनीतिक और आतंकी धमाके

पैसा भी बहा और ख़ून भी

सरोज सिंह

पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान कई सुनहरे इतिहास का गवाह रहा है, पर 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दिन बम धमाके की घटना को शायद गांधी मैदान भी याद न रखना चाहे. बिहार के माथे पर यह कलंक उस दिन लगा, जिस दिन भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ रहे थे. अगर यह धमाके नहीं हुए होते तो यह रैली दो चीज़ों के लिए याद की जाती. एक नरेंद्र मोदी का ज़ोरदार भाषण और दूसरा रैली का भव्य तामझाम. आम जनता के दिलों को छूने वाले भाषणों के लिए तो नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं, पर इस रैली की तैयारियों के लिए भाजपा ने जो पैसा बहाया, उसे देखकर भी आम लोग हैरान रह गए. जदयू के साथ संबंध टूटने के बाद भाजपा ने सही मायनों में हुंकार रैली के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं. पंचायतों को भी होर्डिंग और पोस्टरों से पाटने का अनूठा संकल्प लिया गया और देखते ही देखते पूरा बिहार नरेंद्र मोदी के पोस्टर और बैनर से पट गया. भीड़ के लिहाज से रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई. पॉकेट ख़र्च के लिए कहीं-कहीं नक़द-नारायण का भी इंतज़ाम था. एक दर्जन से अधिक रेलगाड़ियों की बुकिंग की गई. बस और छोटी गाड़ियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी. हज़ारों ऐसे कार्यकर्ता थे, जिन्हें नमो टी-शर्ट भेंट दी गई. रेलगाड़ी के इंतज़ाम में पूर्णिया के सांसद उदय सिंह अव्वल रहे. उन्होंने तीन ट्रेन की व्यवस्था कर रखी थी. भाजपा के विधायकों ने रैली के लिए अपना दिल बड़ा कर लिया था. समर्थकों के लिए गाड़ी से लेकर खाने-पीने का पूरा इंतज़ाम उन्होंने उठा रखा था. 92 विधायकों वाली भाजपा इस मायने में भाग्यशाली रही कि सभी ने मिलकर इंतज़ाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बात अगर पटना की करें तो पूरा पटना नरेंद्र मोदी के पोस्टर, बैनर व होर्डिंग से पट गया था. शहर के सारे होटल भाजपा के अतिथियों के लिए बुक थे. विधायकों के घरों पर कार्यकर्ताओं के खाने का इंतज़ाम था. गांधी मैदान का ज़िक्र करें तो पहले से बने स्थायी मंच के अलावा नरेंद्र मोदी के लिए स्टील का एक नया मंच भी बनाया गया. दिल्ली की एक कंपनी को साउंड सिस्टम का ठेका लाखों में दिया गया था. कोशिश यही थी कि नरेंद्र मोदी की आवाज़ जन-जन तक साफ तरीक़े से पहुंचे. आकर्षण का केंद्र मैदान में लगे एलईडी टीवी भी थे. इसके अलावा भाजपा ने रैली को सुचारु रूप से संपन्न करने के लिए दो हज़ार के क़रीब एसआईएस के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का भी इंतज़ाम किया था. इन्हीं सब वजहों से यह बात चर्चा में रही कि रैली में सौ करोड़ से ज्यादा का ख़र्च हुआ होगा. भाजपा में इन सब मामलों को देखने वाले सूरजनंदन मेहता का कहना है कि सौ करोड़ की बात विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही है. हक़ीक़त तो यह है कि बिहार की साढ़े दस करोड़ जनता ने खुद इस रैली की तैयारी की थी. पटना में तो नागरिक मंच बनाकर यहां के जाने-माने लोगों ने रैली में सहयोग किया. मेहता के अनुसार, भाजपा ही ऐसी पार्टी है, जिसमें ख़र्च के पाई-पाई का हिसाब दिया जाता है. हुंकार रैली से संबंधित ख़र्च का ब्योरा भी जल्द ही दे दिया जाएगा, लेकिन विरोधी मेहता की इस दलील को मानने को तैयार नहीं हैं. राजद विधायक सम्राट चौधरी कहते हैं कि यह भाजपा की नहीं, कॉरपोरेट घराने की रैली थी और इसमें सौ करोड़ रुपया फूंक दिया गया. राजद यह जानना चाहता है कि आख़िर एक चाय बेचने वाले शख़्स के लिए अरबों रुपया कौन और क्यों ख़र्च कर रहा है. बिहार में अन्ना हजारे के प्रतिनिधि संजय सिसोदिया कहते हैं कि हम लोगों ने चार से पांच लाख के ही ख़र्च में डेढ़ लाख लोगों को गांधी मैदान में जुटाया था. अन्ना हजारे का आकर्षण लोगों को गांधी मैदान तक ले आया, लेकिन भाजपा सौ करोड़ से ज्यादा ख़र्च करके भी गांधी मैदान लबालब नहीं भर पाई. सिसोदिया कहते हैं कि अन्ना हजारे की छवि बिहार की जनता के दिलों में बसी है. इसलिए केवल उनका नाम देखकर लोग दौड़े चले आते हैं. कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा का आरोप है कि नरेंद्र मोदी आम जनता के नहीं, कॉरपोरेट के नेता हैं. इसलिए उनकी रैलियों में करोड़ों-करोड़ बहाया जा रहा है. भीड़ को लाने के लिए पैसे पानी की तरह बहाए गए. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार तो साफ कहते हैं कि अगर भाजपा ने सौ करोड़ ख़र्च नहीं किया होता तो रैली में सौ लोग भी नहीं आते. यह तो बस पैसे का चकाचौंध था, जो कुछ लोग आ गए. नीरज कहते हैं कि इतना हायतौबा मचाने के बावजूद जदयू की अधिकार रैली की तुलना में यह रैली फ़ीकी साबित हुई. बहरहाल, रैली में कितना पैसा ख़र्च हुआ, इसका आंकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन रैली की चमक-दमक यह बतलाने के लिए काफ़ी है कि ख़र्च के मामले में हुंकार रैली ने इतिहास ही रचा.

ऐसे सुरक्षा इंतज़ाम होंगे तो फिर भगवान ही मालिक

हुंकार रैली के दौरान लगातार सात विस्फोट हुए. दर्जन भर जिंदा बम मिले. छह लोग मारे गए. सौ से अधिक लोग घायल हुए. रैली के दो दिन बाद तक गांधी मैदान में बम को निष्क्रिय करने का सिलसिला चलता रहा. कहां चूक हुई, सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, किसने क्या बयान दिया, इन बातों पर जाने से पहले आईबी के पत्र की कुछ पंक्तियों को देखें. आईबी ने हुंकार रैली को लेकर 23 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया था. बिहार पुलिस को यह पत्र 24 अक्टूबर को मिल गया था. पत्र में साफ़ कहा गया है कि नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें भारी भीड़ जुटने की संभावना है. रैली में जुटने वाली भीड़ और शहर में लोगों के आवागमन पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है. यह भी कहा गया है कि बिहार के विभिन्न भागों में यासीन भटकल और आईएम मॉड्यूल की गिरफ्तारी हुई है, जिसे ध्यान में रखना होगा. नरेंद्र मोदी हिंदुओं के नेता समझे जाते हैं, इसलिए अतिवादी मुस्लिम समूह उत्तेजित हो सकते हैं और उग्रवादी तत्व उन्हें निशाना बना सकते हैं. नरेंद्र मोदी पहले से ही विभिन्न आतंकी संगठनों के हिट लिस्ट में हैं. साथ ही पत्र के अंत में यह भी लिखा होता है कि कृपया उपयुक्त कार्रवाई करें.

धमाकों के बाद भी हुंकार रैली सफल रहती है. भाजपा नेताओं की सूझ-बूझ के कारण ही स्थिति भड़कती नहीं है. ठीक हुंकार रैली के दिन ही देर शाम को मुख्यमंत्री पटना पहुंचते हैं और संवाददाताओं को संबोधित करते हैं. इस दौरान सीएम कहते हैं कि बिहार सरकार को न तो राज्य की ख़ुफ़िया एजेंसी और न ही केंद्र की ख़ुफ़िया एजेंसी की तरफ से कोई इनपुट दिया गया था. इनके साथ-साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं कि 23 को हमें रूटीन चिट्ठी मिली थी, जिसमें आतंकी गतिविधियां, नक्सली गतिविधियां आदि की समीक्षा करने की सलाह दी गई थी. साथ ही अभयानंद यह भी कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था जेड प्लस के हिसाब से की थी, लेकिन आईबी के इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद सीएम नीतीश की बोलती बंद है और सूबे की सरकार या फिर पुलिस मुख्यालय भाजपा नेताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है. बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय कहते हैं कि 25 अक्टूबर को पटना प्रशासन के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ामों को लेकर विस्तार से बात हुई थी और सहमति बनी थी. पटना प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि गांधी मैदान के हर गेट पर एक दंडाधिकारी नियुक्त होंगे और जांच के बाद ही किसी को भी अंदर जाने दिया जाएगा. पुलिसवालों को भी अपना परिचय पत्र दिखाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. गांधी मैदान में लोग बेरोकटोक आ जा रहे थे. श्वान दस्ता और बम निरोधी दस्ते ने सिर्फ़ मंच की तलाशी कर खानापूर्ति करने का काम किया. भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए राज्य सरकार से बुलेटप्रूफ एसयूवी की भी मांग की गई थी, लेकिन यह कहते हुए मोदी को एसयूवी देने से मना कर दिया गया कि इस दिन मुख्यमंत्री मुंगेर जाएंगे. पांडेय बताते हैं कि मोदी को राज्य सरकार की तरफ से राजकीय अतिथि घोषित किया गया था, लेकिन हवाई अड्डे पर उन्हें रिसीव करने के लिए सचिवालय डीएसपी को भेजा जाता है. सुशील कुमार मोदी आरोप लगाते हैं कि बम विस्फोट की जानकारी हमें लंदन से एक आदमी ने दी और पहले धमाके के एक घंटे बाद जब हमने पटना के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन कर जानकारी दी तो उन्होंने कहा, हमें तो मालूम ही नहीं है कि विस्फोट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम मंच से लगातार यह कह रहे थे कि पटाखा न छोड़ें, ताकि शांति भंग न हो.

अब लोग अधिकार रैली और हुंकार रैली की सुरक्षा व्यवस्था की भी तुलना करने लगे हैं. हुंकार रैली के विपरीत अधिकार रैली के दौरान सुरक्षा चाकचौबंद थी. वहीं हुंकार रैली के दिन शहर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था. अधिकार रैली के दौरान गांधी मैदान में हाई रेज्योल्युशन और गांधी मैदान को आने वाली मुख्य सड़कों पर बीस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. पांच हज़ार पुलिसकर्मी रैली में लगाए गए थे और पांच हज़ार पुलिसकर्मी अन्य जिलों से पटना बुलाए गए थे, लेकिन हुंकार रैली में डीएसपी लेवल के 18, इंस्पेक्टर लेवल के 60 व एसआई व एएसआई लेवल के 850 अधिकारियों के ज़िम्मे सुरक्षा की व्यवस्था थी. यहां 3350 लाठीधारी पुलिस बल, 150 सशस्त्र पुलिस बल, 200 महिला पुलिसकर्मी और स्पेशल टास्क फोर्स की चार यूनिट की तैनाती हुई थी. तैनाती तो दो बम निरोधी और दो स्वान दस्ते की भी हुई थी, लेकिन इनकी सक्रियता कितनी थी, घटना के अगले दिन गांधी मैदान से मिलने वाले पांच बम से पता चलता है.

घटना के बाद से नीतीश कुमार लगातार बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं. भाजपा सहित अन्य दलों के नेता उन्हें निशाने पर ले रहे हैं. सही मायने में देखा जाए तो यह राज्य की ख़ुफ़िया विभाग की लापरवाही की पराकाष्ठा है.

(शशि सागर)

जनाक्रोश के साथ ख़बरदार रैली

शशि सागर

राजधानी पटना में एक ही झंडे (लाल झंडे) की दो रैली हुई. पहली रैली भाजपा की हुंकार रैली से ठीक पहले 25 अक्टूबर को भाकपा की जनाक्रोश रैली थी और दूसरी भाजपा के हुंकार रैली के बाद ख़बरदार रैली हुई. दहशत, भय और संगीनों के साये में हुई ख़बरदार रैली. हुंकार रैली के दौरान हुए विस्फोट की वजह से भले ही भाजपा की यह रैली कुछ अधिक की चर्चित रही और लगातार भय का आलम बना रहा, लेकिन दोनों वामपंथी पार्टियों की रैली के गहरे अर्थ भी हैं.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली कहने को तो सफल रही. कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ा. केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं ने जमकर भाषण भी दिया. लोगों से लाल झंडे से जुड़ने की अपील भी हुई, लेकिन जनाक्रोश रैली में जो होना था या वाम से हमदर्दी रखने वाले लोगों को जो उम्मीद थी, वही नहीं हुआ. जनाक्रोश रैली के दौरान आक्रोश का पूरा अभाव भी दिखा. भाकपा के लिए यह रैली इसलिए कई मायने में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसे अपने कैडरों में उत्साह भरना था. अपनी क्षमता और शक्ति का एहसास भी कराना था. साथ ही उसे बिहार की मेहनतकश जनता को यह भी दिखाना था कि भाकपा उसके साथ है और उसकी लड़ाई लड़ेगी. उसने भले ही अपने एक विधायक से नीतीश सरकार को समर्थन दिया हो, लेकिन पार्टी जनता के हक़ की आवाज़ बुलंद करती रहेगी, लेकिन विभिन्न राजनीतिक कारणों से ये सब हो नहीं सका. पार्टी के महासचिव सुधाकर रेड्डी, पूर्व महासचिव एबी बर्धन, लोकसभा में पार्टी के नेता गुरुदास दासगुप्ता सहित कई नेताओं ने जनता को संबोधित भी किया, लेकिन जदयू जिस तरह भाजपा को छोड़ सिर्फ़ नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेती है, ठीक उसी तरह पार्टी के ये वरिष्ठ नेता कांग्रेस से ज्यादा मनमोहन और नरेंद्र मोदी को ही निशाने पर लेते रहे. बिहार के मुद्दे पर खुलकर किसी नेता ने नहीं बोला. बिहार के कुछ मुद्दों पर नेताओं ने बोला तो ज़रूर, लेकिन ठीक उसी तरह, जैसे गांव में छोटे बच्चे छुआछुई का खेल खेलते हों. नेताओं ने नीतीश को सलाह देने की कोशिश ज्यादा की. आंकड़े बताए गए कि 22 लाख एकड़ जमीन हदबंदी से फाजिल है. छह लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके पास वास की ज़मीन नहीं है. 21 लाख परिवार के पास जोत की ज़मीन नहीं है. साथ ही यह भी कहा गया कि बंधोपाध्याय कमेटी बनाई गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया. उसके बाद नेताओं ने यह कहकर नीतीश की सराहना भी की कि सरकार में जदयू के साथ भाजपा थी, हमें तभी लग गया था कि भाजपा तो सामंतों और पूंजीपतियों की पार्टी है. यह कभी बंधोपाध्याय कमेटी की अनुशंसाओं को लागू होने नहीं देगी. राष्ट्रीय सचिव गुरुदास गुप्ता ने भी केंद्र और गुजरात सरकार पर ही तीखे प्रहार किए. 12 दिसंबर को दिल्ली चलने की अपील भी की गई. नियोजित शिक्षकों, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं से साथ आने का अनुरोध भी किया गया और यह भरोसा भी दिलाया गया कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं दिखा है कि ठेके पर बहाल बेरोज़गारों के लिए भाकपा ने कोई आंदोलन किया हो. हां, एबी बर्धन ने थोड़े तल्ख अंदाज़ में नीतीश को आड़े हाथों लिया, लेकिन बाद में बिहार के विकास मॉडल को सही भी ठहराया, नीतीश के सुर में सुर भी मिलाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए. साथ ही बर्धन इस बात पर चिंतित भी दिखे कि कभी हमारे एक लाख से अधिक कैडर हुआ करते थे और आज मात्र 85 हज़ार हैं. कुल मिलाकर भाकपा नीतीश के प्रति नर्म ही दिखी. एक वामपंथी साथी कहते हैं कि सारे दुश्मन से एक साथ तो नहीं लड़ा जा सकता है न. यही वजह है कि हमारी पार्टी का रुख़ नीतीश को लेकर थोड़ा नरम है.

हुंकार रैली और विस्फोट के बाद माले की रैली हुई. सुरक्षा कारणों से ज़िला प्रशासन ने रैली के लिए गांधी मैदान देने से इन्कार कर दिया. रैली से ठीक एक दिन पहले देर शाम को माले के अधिकारियों को कहा गया कि आपको मिलर हाई स्कूल और उसके आसपास के सड़कों पर ही रैली करनी होगी. प्रशासन लगातार असहयोग की मुद्रा में ही दिखा. देर रात से रैली वाली सुबह तक माले कार्यकताओं ने भिड़कर वीरचंद पटेल पथ को रैली के अनुकूल बना ही लिया. बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई रैली सड़क पर हुई. कहते हैं दूध का जला छांछ भी फूंक-फूंक पर पीता है. उसी तर्ज पर पटना पुलिस के आला अधिकारी भी रैली के दिन मुस्तैद दिखे. कहने को तो माले बिहार में विधायकविहीन पार्टी है, लेकिन यह भी सच है कि जन मुददों, आम-अवाम के सरोकारों को लेकर लगातार सड़कों पर सरकार के ख़िलाफ़ यह अकेली वामपंथी पार्टी दिखती है. कई मायने में ख़बरदार रैली अन्य रैलियों से भिन्न रही. दहशत के माहौल में जैसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भीड़ कम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. स्थान बदलने के बाद भी और एक दिन पहले तक बम मिलने की ख़बरों के छाए रहने के बावजूद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. पटना के लोगों को इस रैली में भले ही रुचि न हो, लेकिन ख़बरदार रैली ने दहशत में जी रही पटना की जनता में साहस तो अवश्य ही भरा. जनाक्रोश रैली में जहां भाकपा साफ स्टैंड नहीं ले पाई, वहीं माले बहुत ही बेबाक दिखी. माले के पोस्टरों से ही इसके स्टैंड साफ हो जा रहे थे, जिसमें साफ लिखा था कि निकम्मी नीतीश सरकार ख़बरदार. भाकपा ने भी वामपंथी पार्टियों के एक मंच पर आने की बात कही, लेकिन उसका दोहरा रवैया देखिए कि जब दिल्ली में सांप्रदायिकता विरोधी कन्वेंशन बुलाया जाता है तो माले को आमंत्रित ही नहीं किया जाता है. यह कन्वेंशन माकपा और भाकपा के ही पहल पर बुलाई गई थी. योजना थी कि इसमें 32 पार्टियों को बुलाया जाएगा, लेकिन मात्र 14 पार्टियां ही शामिल हो पाईं. माले सहित कई छोटी-छोटी वाम पार्टियों को तरजीह नहीं दी गई. माले के महासचिव दीपांकर ने अपने संबोधन में कहा भी कि जब सांप्रदायिकता विरोधी मंच तैयार कर रहे हैं तो इसकी कल्पना माले, लालू और रामविलास पासवान को छोड़कर नहीं कर सकता है. ख़बरदार रैली के दौरान दीपांकर ने यह संकेत भी दिया कि वे लालू के प्रति नरम ज़रूर हैं. हालांकि, भाजपा कांग्रेस और इसके साथ जाने वालों से समान दूरी बनाए रखने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि चारा घोटाले को सिर्फ़ लालू से ही जोड़कर क्यों देखा जा रहा है. जदयू के सांसद जगदीश शर्मा और भाजपा नेता ध्रुव भगत को भी सज़ा मिली है, यह भी बराबर तरीक़े से लोगों को बताया जाना चाहिए. यह तय है कि विधायकविहीन पार्टी माले को जदयू और भाजपा ज्यादा तवज्जो नहीं देंगी, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही माले को सीट मिले या न मिले, लेकिन उनके लिए परेशानी तो खड़ी कर ही सकती है. यह ध्यान रखना होगा कि इस बार चुनाव तीन ध्रुवों पर होगा और यह भी मानकर चलना चाहिए कि इस बार माले कम से कम काराकाट, औरंगाबाद, जहानाबाद, आरा जैसे इलाक़ों में चुनाव किसी भी दल को आसानी से तो नहीं ही जीतने देगी. राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं कि वामपंथ इतिहास में कभी भी इतना कमज़ोर नहीं रहा है. यह देश का दुर्भाग्य है. वे यह भी कहते हैं कि भले ही वाम एकता की बात मंच से की जाती हो, लेकिन यह संभव नहीं है, सीपीआई और सीपीएम का भीतरी एजेंडा ही कुछ और है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री के दौरे पर कितने रुपये ख़र्च हुए. सवाल यह है कि इन भारी–भरकम ख़र्चों से हासिल क्या हुआ? हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री ने जितने विदेशी दौरे किए हैं, उनमें किसी भी दौरे को लेकर बेहतर विदेश नीति के लिए उनकी तारीफ़ होने के बजाय उनकी आलोचना ही हुई है.

विदेशी दौरे और असफल विदेश नीति

मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री दस साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं. पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद, वे तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे ज्यादा कार्यकाल तक इस पद पर बने हुए हैं. बहुत संभावना है कि मनमोहन सिंह आगामी लोकसभा चुनाव के बाद अपनी कुर्सी से हट जाएं. ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि उनकी उपलब्धियों और असफलताओं पर बहस हो और देश को उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री क्या दिया और किन अवसरों, उपलब्धियों और प्रगतिमार्गों से वंचित रखा, इसकी सघन पड़ताल हो. हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान उनकी विदेश यात्राओं पर 642 करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च हो गए. ऐसे में यह सवाल उठता है कि इन दौरों का हासिल क्या रहा?

कृष्णकांत

इतिहास किसी को भी उसकी सार्वजनिक उपलब्धियों और असफलताओं के आधार पर ख़ुद में जगह देता है. किसी भी व्यक्ति को इतिहास इसी आधार पर परखता है कि देश और समाज के प्रति उसका अवदान कितना बड़ा है. यह ज़रूरी नहीं है कि कोई नेता अथवा प्रशासक अगर लंबे समय तक शासन करता है तो वह देश की महान विभूतियों में गिना ही जाए. आज का दौर ही ऐसा है कि इस दौर में दुनिया बुरी तरह बाज़ारवाद की चपेट में है. और शायद यह ऐसी आंधी है, जिससे बचने का विकल्प किसी भी देश के पास नहीं दिखता. इसका नतीजा यह है कि जनता की सरकारें जनता की जेब से पैसे निकाल कर बाज़ार के हवाले कर रही हैं. बाज़ार का मतलब है कुछ पूंजीपति और भ्रष्ट नेता. यह एक तरह की सरकारी लूट है, जिसे अलग–अलग तरीके से अंजाम दिया जा सकता है. सरकारी नीतियों की समीक्षा के क्रम में निगाह डालने पर आप पाएंगे कि विभिन्न रास्तों से जनता का पैसा कैसे पानी की तरह बह रहा है, जबकि जन सामान्य महंगाई और ग़रीबी से जूझ रहा है. ज़ाहिर तौर पर ये परेशानियां आम जनता को सरकारी नीतियों की ख़ामियों की वजह से मिली हैं. अब जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने दूसरे कार्यकाल के आख़िरी दौर में हैं, यह ज़रूरी है कि भारतीय राजनीति को उनके अवदान, उनकी उपलब्धियों और असफलताओं पर चर्चा की जाए.

हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी सार्वजनिक की कि पिछले नौ साल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विदेश दौरों पर 642 करोड़ रुपये से ज्यादा ख़र्च हुए हैं. ध्यान देने की बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय मनमोहन सिंह के 5 विदेशी दौरों का हिसाब नहीं दे सका. प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के कुल हिसाब–किताब में सामने आया है कि उन्होंने नौ साल में 67 विदेश यात्राएं कीं. इनमें से 62 यात्राओं में 642 करोड़ रुपये से ज्यादा का ख़र्च आया और 5 यात्राओं कोई हिसाब नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यालय में इसका कोई लेखा–जोखा नहीं मिल सका.

मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी. तब से अब तक क़रीब नौ साल हो चुके हैं और इस बीच उन्होंने 67 विदेशी दौरे किए. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि उनकी हवाई यात्रा पर कुल 642.45 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिनमें से पांच यात्राओं का हिसाब नहीं है. मनमोहन सिंह 2012 में जी–20 शिखर सम्मेलन के लिए मैक्सिको, और रियो प्लस–20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील गए थे. उनके इस सात दिवसीय दौरे पर सबसे ज्यादा 26.94 करोड़ रुपये खर्च हुए. 2010 में प्रधानमंत्री परमाणु सुरक्षा सम्मेलन, ब्रिक सम्मेलन और इब्सा सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी और ब्राजील गए थे. इस दौरे की हवाई यात्रा पर 22.70 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.

दरअसल, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने मंत्रिमंडल सचिवालय को आदेश दिया था कि व्यापक जनहित के मद्देनज़र मंत्रियों और वीवीआईपी की यात्राओं पर हुए ख़र्च का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए. मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्र का कहना था कि देखने में आया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसी हस्तियों की यात्राओं को लेकर लोगों की गहरी दिलचस्पी रहती है. आरटीआई आवेदनों के ज़रिए अक्सर इन दौरों के बारे में लोग जानकारी मांगते हैं. आयोग ने सामान्य जन की इस दिलचस्पी को जनहित में माना और तमाम रसूख़दार हस्तियों के दौरों का ख़र्च सार्वजनिक करने का आदेश दिया. लोकतंत्र के लिहाज से इसे अच्छी पहल माना जा रहा है. चूंकि, नेताओं पर हो रहा सरकारी ख़र्च जनता का पैसा है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि कहां पर कितना ख़र्च किया जा रहा है.

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भी दौरों की जानकारी सामने आने के बाद दौरों पर हो रही फिजूलख़र्ची की चर्चा गर्म हुई थी. अब दूसरे अतिविशिष्ट लोगों के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं. प्रतिभा पाटिल के बारे में भी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से ही उनके विदेशी दौरों पर हुए ख़र्च का ख़ुलासा हुआ था. पूर्व राष्ट्रपति के पांच साल के कार्यकाल के दौरान विदेशी दौरों पर 223 करोड़ रुपये ख़र्च हुए थे.

सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री के दौरे पर कितने रुपये ख़र्च हुए. सवाल यह है कि इन भारी–भरकम ख़र्चों से हासिल क्या हुआ? हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जितने विदेशी दौरे किए हैं, उनमें किसी भी दौरे को लेकर बेहतर विदेश नीति के लिए उनकी तारीफ़ होने के बजाय उनकी आलोचना ही हुई है. उनके विदेशी दौरों से भारत को राजनीतिक तौर पर कुछ ख़ास फ़ायदे नहीं हुए.

सितंबर में प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया और वहां पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया था, लेकिन उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा से हुई उनकी मुलाकात औपचारिकता मात्र थी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत तो किया, लेकिन उनके ठीक बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ से ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज़ को सुरक्षित निकालने में मदद के बदले पाकिस्तान को रणनीतिक और आर्थिक मदद का वादा किया. शरीफ और ओबामा ने संयुक्त वक्तव्य में भारत को बचपना छोड़ने और कश्मीर पर बात करने की नसीहत दे डाली. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ से भी उनकी मुलाक़ात हुई, लेकिन इस मुलाक़ात से आतंकवाद की समस्या पर भी कोई हल नहीं निकला.

जिस दौरान नवाज शरीफ़ अमेरिकी दौरे पर थे, मनमोहन सिंह पहले मॉस्को गए और फिर बीजिंग. उसी दौरान जसवंत सिंह की एक क़िताब चर्चा में थी–इंडिया एट रिस्क: मिस्टेक्स, मिसकॉन्सेप्शन ऑर मिसएडवेंचर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी. जसवंत सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि भारत ख़तरे में है, क्योंकि इसने कभी भी रणनीतिक संस्कृति का विकास नहीं किया. यह सही भी है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही भारत पाकिस्तान और चीन से मात खाता रहा है और आजतक रणनीतिक स्तर पर उससे निपटने तौर–तरीक़े हम विकसित नहीं कर सके हैं. नेहरू ने शांति के जिन उच्च विचारों से प्रेरित होकर पाकिस्तान और चीन से निपटने की कोशिश की, उसी के चलते मात खा गए.

आज पाकिस्तान रणनीतिक स्तर पर भारत से ज्यादा मज़बूत स्थिति में है. यह ग़ौर करने की बात है कि पिछले छह दशकों से भारत के संबंध पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के साथ अस्थिर ही रहे हैं और मनमोहन सिंह भी इसमें कोई नया अध्याय नहीं जोड़ सके. पिछले एक दशक से पाकिस्तान को लगातार शांति प्रस्ताव देने के बदले भारत को क़ायदे से सकारात्मक जवाब तक नहीं मिल सका है. मिश्र के शर्म अल शेख में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी द्वारा मनमोहन सिंह को दी गई पटकनी कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में आतंकवाद के लिए भारत को दोषी ठहरा दिया था.

मनमोहन सिंह कभी भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने वाले बेहतर अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज वे दस साल से प्रधानमंत्री हैं और चारों तरफ से भयावह असफलताएं उनका पीछा कर रही हैं. एक अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ के रूप में उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल हैं. अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं. आगामी चुनाव के मद्देनज़र सरकार का सारा ध्यान वोट बैंक पर है, जिसके चलते विदेश नीति, राजनय और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पीछे छूट गए हैं. सरकार नौ साल तक सत्ता में रहकर जिन मोर्चों पर असफल रही, अब आख़िरी साल में वह उन मोर्चों पर कुछ ख़ास कर पाएगी, ऐसी आशा करना कतई बेमानी है. ■

विदेश यात्राओं का कीर्तिमान

बताया जाता है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ज्यादा यात्रा करना पसंद नहीं है. वे कभी रात में हवाई यात्रा नहीं करते. यात्रा के दौरान वे पढ़ना पसंद करते हैं. मनमोहन सिंह ज्यादा खाना भी नहीं खाते. ज्यादा यात्राएं पसंद न होने के बावजूद मनमोहन सिंह ने विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड बनाया है. विदेश यात्राओं को लेकर डॉक्टर सिंह अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों से आगे निकल गए हैं. इसी के चलते उन्हें अनिवासी प्रधानमंत्री का ख़िताब भी मिल गया है. 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से वे अबतक 70 विदेशी यात्राएं कर चुके हैं और उन पर क़रीब 642 करोड़ रुपये ख़र्च हो चुके हैं. अपने दूसरे कार्यकाल में वे 37 विदेश यात्राएं पूरी कर चुके हैं. इनमें से वे 15 बार तब विदेश यात्रा पर गए थे, जब संसद का कोई न कोई सत्र चल रहा था. पिछले चार सालों में मनमोहन सिंह 14 में से 9 संसद सत्रों के दौरान थोड़े या ज्यादा दिन देश से बाहर रहे. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा का आरोप है कि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं पर जाकर संसदीय परंपरा को तोड़ा है. इसके पूर्व कभी भी प्रधानमंत्रियों ने संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा नहीं की. चाहे वे जवाहर लाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों या अटल बिहारी वाजपेयी. आम चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समेत कई देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुकाबले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (1999-2004) अपने कार्यकाल में 35 विदेश यात्राओं पर गए थे, जिनपर 185 करोड़ रुपये ख़र्च हुए थे. अपने दो कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा यानी 10 बार अमेरिका की यात्रा पर गए. अमेरिका के बाद दूसरा नंबर रूस का आता है. उन्होंने नौ बार रूस की यात्रा की. हालांकि, मनमोहन सिंह भारत के पड़ोसी देशों की यात्रा पर कम ही गए, जिसकी शायद ज्यादा ज़रूरत थी.

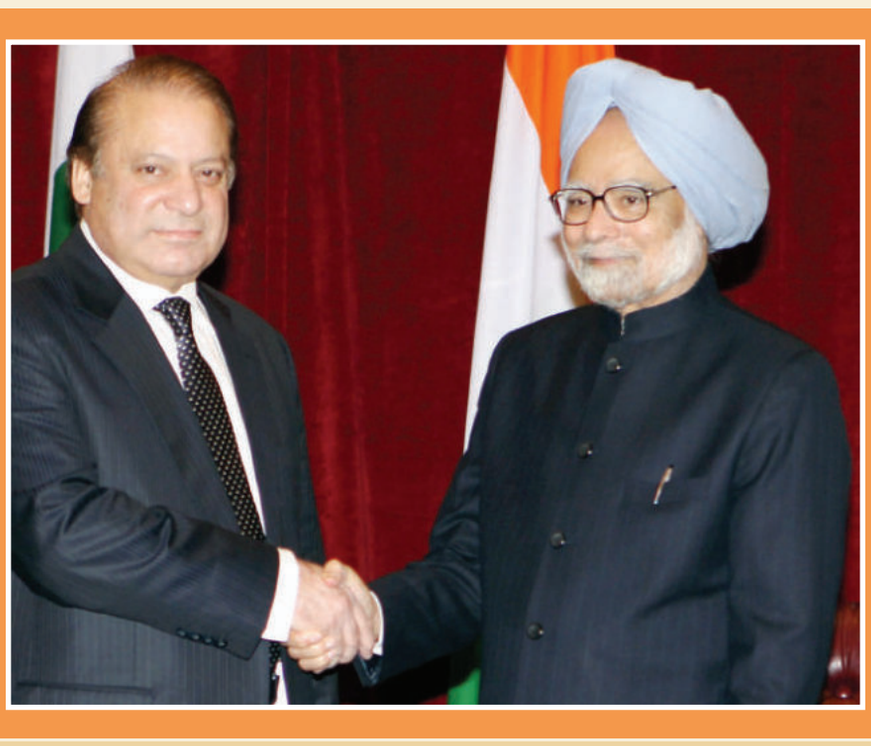

feedback@chauthiduniya.com

> आज हमारे समाज में हिंसा जिस क्रूर मोड़ पर आ गई है वहां से उसकी वापसी बहुत मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि आर्थिक गैरबराबरी, शहरीकरण और औद्योगीकरण व राजनीतिकरण ने समाज को संवेदनहीन बनाने के सारे औज़ार मुहैया करा दिए हैं. प्रचार माध्यमों ने इस संवेदनहीनता को और भी बढ़ाया है. फिल्मों, टेलीविज़न व अन्य संचार माध्यमों यथा इंटरनेट, वीडियोगेम्स आदि की भूमिका भी कम ज़िम्मेदार नहीं है.

उत्तर प्रदेश में मोदीमय भाजपा, संगठन रसातल में

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में है. मोदी का डंका बज रहा है. रैलियों में लाखों की भीड़ के जुटान को देखकर कमल खिलने का अनुमान बढ़ रहा है. करीब डेढ़ दशक के बाद भाजपा के गिरते जनाधार के बढ़ने की उम्मीद जागी है, यह सच्चाई है, लेकिन आज की तारीख में भाजपा दूसरे पायदान पर और मोदी पहले पायदान पर खड़े दिखे हैं. एक समय कांग्रेस में नारा गूंजा करता था, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा. आज भाजपा में भी ऐसे ही कुछ हालात हैं. भाजपा की तकदीर और तस्वीर बदलने का जिम्मा मोदी ने अपने कंधों पर ले लिया है.

यह है सिक्के का एक पहलू, जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो मोदी की रैलियों के कारण प्रदेश भाजपा नेता अन्य कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं. नमो के एक के बाद एक कार्यक्रम होने से भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, जबकि मोदी की रैली में जुटी भीड़ को वोटों में बदलने के लिए रणनीति बनाने की अभी से ज़रूरत है. प्रदेश इकाई के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वह कैसे इस समस्या से उबरें. रैली में ताकत झोंकने के बाद बचे समय में से पार्टी के नेता एक मोर्चा संभालते हैं, तो दूसरा पिछड़ जाता है. दूसरे पर ध्यान देते हैं तो तीसरे की अनदेखी होने लगती है. अब तो ऐसा लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को पुरानी लय में लाने के लिए बनी रणनीति को सुचारु रूप आगे बढ़ाने के लिए भी आलाकमान को एक रणनीति बनानी होगी. मोदीमय भाजपा संगठन रसातल में चला गया है. राजनैतिक पंडित 2012 के विधानसभा चुनाव को याद करके डर जाते हैं. उस समय भी भाजपा के दिग्गज नेताओं ने माहौल पार्टी के पक्ष में बना दिया था, लेकिन संगठन इसे वोट बैंक में नहीं बदल पाया था.

राज्य भाजपा संगठन का कामकाज देखने वाली टीम के लिए मुश्किल यह है कि किसी मोर्चे पर कोई कमी रह जाती है, तो उन्हें केन्द्रीय नेतृत्व की नाराजगी का सामना करना पड़ता है. नेताओं की रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा तो संगठन वालों के कंधों पर रहता ही है. इसके अलावा भाजपा के अन्य आनुषंगिक संगठनों के कार्यक्रम के लिए भी जुटना पड़ता है. आज स्थिति यह है कि प्रदेश भाजपा के बूथ समितियों के सत्यापन, सदस्यता अभियान जैसे कई महत्वपूर्ण अभियान भी परवान नहीं चढ़ पा रहे हैं. अक्टूबर बीत गया है और भाजपा नेता लाइन पीट रहे हैं. सारे कार्यक्रम उलझते जा रहे हैं. रही सही कसर पटना में मोदी की रैली वाले दिन हुए बम विस्फोटों ने पूरी कर दी है. पटना रैली के बाद भाजपा प्रदेश इकाई की चिंता और कामकाज दोनों बढ़ गए हैं. अब उसे बहराइच और उसके बाद होने वाली मोदी की तमाम रैली को सुरक्षित सम्पन्न कराने के लिए कमर कसनी ही होगी. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं मोदी की रैली में किसी गड़बड़ी की संभावना के डर से जनता रैली में आने से बिदक न जाए. पटना में मोदी की रैली में धमाकों में छह लोगों की मौत हो गई थी और सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. अब कार्यकर्ताओं और रैली के आयोजकों को यह सुरक्षा मोर्चे पर भी खास ध्यान देना होगा. यह अतिरिक्त जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है.

बहरहाल, सच्चाई यह भी है कि राजनीति का घोड़ा अपने हिसाब से दौड़ता है. चाहे कोई पीछे रहे या आगे इसे कोई मतलब नहीं है. यही डर भाजपाइयों को सता रहा है. बदले माहौल में बात प्रदेश भाजपा के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभाले नेताओं की असफलता की करें तो कई मौकों पर वह स्वयं पैर में कुल्हाड़ी मारते दिखते हैं. प्रदेश इकाई ने एक से पन्द्रह अक्टूबर तक बूथ समितियों के सत्यापन का फैसला किया था, लेकिन उसकी घोषणा ही चार अक्टूबर को तब हुई, जब भाजपा की क्षेत्रीय बैठकें चल रही थीं. सत्यापन की तारीख की घोषणा करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि क्षेत्रीय बैठकों के दौरान बूथ समितियों के सत्यापन के लिए कोई नेता कैसे समय निकाल पाएगा. परिणामस्वरूप वही हुआ जिसकी संभावना थी. बूथ समितियों के सत्यापन का काम कागजों से बाहर नहीं निकल पाया. बूथों का दौरा किया जाए तो अपवाद को छोड़कर कहीं भी बूथ समितियां सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रही हैं. सभी जगह बूथ समितियां भरी नहीं जा सकी हैं.

भाजपा की क्षेत्रीय बैठकों और बूथ समितियों के सत्यापन का काम शुरू नहीं हो पाया था और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्टों के पुनरीक्षण की जिम्मेदारी डाल दी गई. कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने और भाजपा समर्थक मतदाताओं के नाम शामिल करवाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके लिए पार्टी की तरफ से कोई आगे नहीं आया. निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में नये नाम जोड़ने और संशोधन के लिए एक महीने का कार्यक्रम चलाया था. मतदाता अपनी फरियाद लेकर चक्कर लगाते रहे, मगर मदद के लिए कहीं कोई आगे नहीं आया. कुछ भाजपाई नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि मामला सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है. अगस्त–सितंबर दो माह तक विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम चलते रहे. घोषित तौर पर ये कार्यक्रम थे तो विहिप के, पर इन कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भाजपा कार्यकर्ताओं पर रही. भाजपा की दुर्दशा के लिए प्रदेश के बड़े नेता भी कम जिम्मेदार नहीं हैं. यह नेता चुनाव लड़ना और जीतना तो चाहते हैं, लेकिन संगठन के लिए इनके पास समय नहीं है. भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों के बीच संवाद व समन्वय का अभाव हैं. एक समय था, भाजपा पहले कार्यक्रम बनाती थी उसके बाद इन कार्यक्रमों की समीक्षाएं होती थीं. कहीं कमी होने पर उसे सुधार लिया जाता था, पर अब यह प्रक्रिया भी बंद हो गई है. भाजपा के प्रकोष्ठों का भी बुरा हाल है. एक तो तमाम प्रकोष्ठ खाली पड़े हैं जो भरे भी हैं तो वह अपनी अलग राग छेड़े है. इसे सामजस्य का अभाव ही कहा जाएगा जब भाजपा के कई कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का काम चलने वाला था, तभी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सदस्यता अभियान की घोषणा कर दी है. ताज्जुब नहीं कि युवा मोर्चा के कार्यक्रम 10 लाख युवाओं को भाजपा से जोड़ने का ऐलान भी कागजों में सिमट कर न रह जाएं. माहौल भाजपा के पक्ष में होने के बाद भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी भी भाजपा की पहुंच के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जिनके सहारे वह केन्द्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है. अति पिछड़ों व अति दलितों को आरक्षण भाजपा का मुख्य एजेंडा रहा है, लेकिन जब इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने इस पर ऐसा फैसला दिया, जिसे भाजपा मुद्दा बना सकती थी, तब वह इस पर कुछ कर ही नहीं पाई. इसी तरह से प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, अराजकता का माहौल, कांग्रेस–बसपा और सपा के गठजोड़ के मसले पर भी भाजपा ने जनता के बीच कोई विशेष तेजी नहीं दिखाई. मोदी जरूर कांग्रेस–सपा और बसपा को तिकड़ी की उपमा देकर हवा का रुख मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. युवा मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह की लाचारी को भी भाजपा जनता के बीच कैश करा सकती थी, मगर इस मोर्चे पर भी वह कुछ ज्यादा नहीं कर पाई.

बहरहाल, तमाम चुनौतियों से जूझ रही भाजपा को मोदी का ही सहारा दिखाई दे रहा है. इसे लगता है कि प्रदेश में मोदी की तीन बड़ी कामयाब रैलियों से जो माहौल भाजपा के पक्ष में बना है. वह 08 नवंबर को बहराइच की रैली और इसके बाद 24 दिसंबर से पहले सूबे में मोदी की पांच रैलियों को लेकर काफी उत्साहित हैं. इसे लगता है कि इससे भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा. ■

हिंसा हमारी संस्कृति का अंग नहीं है

विनय कुमार राय

मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी का हालिया बयान सुनाने के बाद एक विषय दिमाग में उथल–पुथल मचाने लगा कि क्या हमारे देश हिंदुस्तान में सामाजिक सामंजस्य की इतनी कमी है कि आईएसआई जैसी कोई भी एजेंसी इसे जैसे चाहे भड़का दे? या फिर हमारे अंदर से अहिंसा कि प्रवृत्ति ख़त्म हो गई है और हम हिंसक हो चले हैं? और गाहे–बगाहे मौका मिलते ही हिंसा कि ओर बढ़ जाते हैं, जिसका लाभ कोई भी उठा लेता है या फिर हिंसा क्या हमारी संस्कृति का अंग है?

हिंसा हमारी संस्कृति का अंग है या नहीं यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर आज के माहौल में विवाद की पूरी गुंजाइश है. पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान में जैसा माहौल बन गया है और जितनी असहिष्णुता बढ़ गई है, उसे देखकर तो कुछ लोग तुरंत यह कह उठेंगे कि देश का वास्ता अहिंसा जैसी चीज़ से कभी नहीं रहा. यह सच है कि मनुष्य में हिंसा की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है और हिंदुस्तान में भी हिंसा का इतिहास मानव के इतिहास से जुड़ा हुआ है पर सभ्यता के विकास के साथ–साथ यहां अहिंसा की धारा मजबूत हो गई. बल्कि यह कहना भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदुस्तान में एक वक़्त ऐसा भी आया, जब अहिंसा इसकी मुख्य धारा बन गई थी.

ऐसे भी हिंसा हिंदुस्तान की रगों में कभी उस तरह नहीं बही जिस तरह मध्य–पूर्व विश्व में, आज यहां जिस तरह हिंसा का सैलाब उमड़ा पड़ा है, उसे देखकर यह एक सोचने लायक बात है कि गौतम बुद्ध, महावीर या महात्मा गांधी एक दिन की उपज नहीं होते. ये लोग समाज की आकस्मिक घटना नहीं थे, बल्कि अपने समाज में बह रही एक निरंतर प्रवाह के प्रतिफल थे. किसी एक व्यक्ति का इस रूप में उदय एक घटना हो सकती है पर किसी समाज में जब विभिन्न क्षेत्रों में एक ही तरह के लोग और विचार पैदा होने लगें तो मानना चाहिए कि इसके बीज पूरी तरह समाज में मौजूद हैं. कलिंग विजय के बाद उस भयानक नर संहार पर पश्चाताप करने वाला कोई अशोक हिंदुस्तान में ही हो सकता था. आज के इस टूटते भारतीय समाज में भी अहिंसा की इस धारा को महसूस किया जा सकता है. हिंदुस्तान में आज भी दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले मांसाहारी बहुत कम हैं और जो हैं भी उनमें इसे बीच–बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है. यानि उनके अन्दर की हिंसा को बार–बार अहिंसा से लड़ना पड़ता है. जीव मात्र से आत्मीय सरोकार का एक प्रबल भाव भारत की संस्कृति में रचा बसा रहा है. यूरोप में जानवरों पर अत्याचार बंद करने की मांग पेटा जैसे संगठनों द्वारा उठाई जाती रही है, पर भारत में प्रत्येक व्यक्ति/परिवार में जानवरों से प्यार करने की लम्बी प्रथा रही है. यहां तक कि भारतीय समाज में जानवरों की पूजा की जाती रही है.

सम्राट अशोक के शासन में भी जानवरों के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध थी. भारत में जानवरों से लगाव की यह परंपरा आज भी जीवित है. आज भी यहां छोटे कस्बों एवं गावों में मवेशी की उपयोगिता ख़त्म होने पर उसे कसाई के हाथों बेचते लोग हिचकते हैं, यानि अब भी जहां शहरी संस्कृति का प्रभाव कम है, वहां गाय–बैल, भैंस आदि परिवार का हिस्सा हैं. गावों में पक्षियों को रोटी के टुकड़े देते और चीटियों को आंटा खिलाते लोगों को सहज ही देखा जा सकता है. गांव में यह परंपरा आज भी थोड़ी बहुत सिर्फ इसलिए ज़िन्दा दिखाई देती है क्योंकि वहां की संस्कृति को पूरी तरह ख़त्म करने में पाश्चात्य प्रभाव अभी तक सफल नहीं हो पाया है. दरअसल, हमारी संस्कृति में भाईचारे और सहिष्णुता का एक गहरा पुट था. जहां तक मैं याद कर पता हूं कि गांव कस्बे में अगर दो बच्चे लड़ रहे होते थे तो उसे भी शांत करने को सारा मोहल्ला एकत्र हो जाता था. अंग्रेज़ों के आने के पहले तक भारत में हिन्दू और मुस्लमान में सम्पूर्ण एकता अलबत्ता नहीं थी, पर सांप्रदायिक हिंसा के बीज अंग्रेज़ों ने ही बोए. मुस्लिम समुदाय के कितने ही ऐसे धर्मस्थल हैं जहां हिन्दू भी उतनी ही श्रद्धा से हाथ जोड़ने जाते हैं. अजमेर शरीफ, जगह–जगह पीर या सैयद बाबा हिंदुओं के लिए उतनी ही श्रद्धा के केंद्र थे. उत्तर भारत के गावों में आज भी हिन्दू औरतें ताज़िए कि पूजा करती देखी जा सकती हैं. आज मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों से पहले गावों में सांप्रदायिक दंगों का कोई ख़ास इतिहास नहीं मिलता है. ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पहले हिंसा नहीं थी, लेकिन क्रूरता का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं था.

डायनों को सार्वजनिक रूप से मारने कि घटनाएं हों या अंधविश्वास के कारण होने वाली नर हत्या, ये अशिक्षित समाज में व्याप्त डर का परिणाम थीं, न कि क्रूरता का. यहां छुआछूत जैसी बुराई तो थी पर अमेरिका या यूरोप कि तरह नीग्रो की लींचिंग नहीं होती थी. लींचिंग यानि आदमी को सार्वजनिक रूप से स्टेज पर खड़ा कर क्रूरता से सता सता कर मारना, जिसका मज़ा उपस्थत लोग लेते थे. हिंदुस्तान में कभी हिंसा का वैसा नग्न तांडव नहीं था, यहां तो युद्ध भी समय, समाज और व्यवस्था कि मर्यादा के बीच लड़े जाते थे. यहां हिटलर कि तरह किसी कौम को ख़त्म करने जैसी कोई विचारधारा या प्रयास का ज़िक्र नहीं मिलता है बल्कि भारत में उन विदेशी आक्रमणकारियों को भी स्वीकार्यता मिल ही गई जो समय–समय पर भारत में आए और व्यापक पैमाने पर लूट–पाट मचाई तथा यहां के शासक बन बैठे. यह हिन्दोस्तानी संस्कृति की ही ताकत थी कि मुग़ल बादशाह अकबर का विकास ईरान के शाह जैसे नहीं हुआ और उसने दीन–ए–इलाही धर्म की कल्पना की.

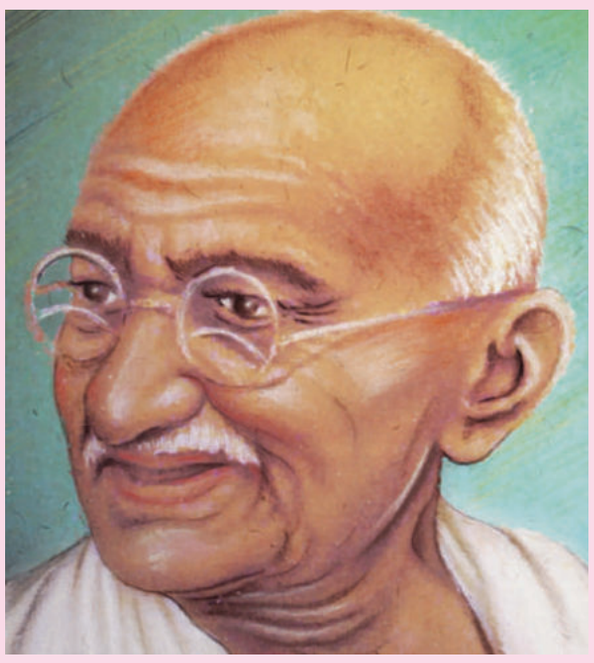

थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो यह पूरी तरह स्पष्ट है कि कुछ चरम पंथी ताकतों की राजनीति और विघटनकारी प्रयासों के बावजूद हिन्दुस्तान ने आज भी अपनी मूल भावना को दूषित नहीं होने दिया है. इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ इसकी सांस्कृतिक जड़ों की अहिंसा में गहरी पैठ ही है. भले ही तात्कालिक कारक उसे बार–बार उकसाएं पर वे फिर भी उतने उत्तेजित नहीं होते. हां, छिटपुट गोधरा, मऊ, मुज़फ़्फ़रनगर ही दिखते हैं , वो भी राजनितिक और प्रशासनिक मूढ़ताओं कि वजह से ना कि प्रवृत्ति के कारण.

आधुनिक समाज में जब–जब राजनीति और धर्म ने अपने–अपने आधार पर भौतिक ज़रूरत तथा विकाश व व्यवस्था कि अधकचरी समझ लोगों के मन मस्तिष्क पर थोप दिया, तभी हिंसक प्रवृतियों ने जन्म लिया और परिणाम हमारे सामने है. विकाश के पूंजीवादी नज़रिए ने लोलुपता को जन्म दिया, ज़ाहिर है लोलुपता अपने साथ हिंसा कि परछाई लेकर चलेगी और पैसा कमाने का शॉर्टकट, क्रूरता को हमारे भीतर जगाए रखेगा.

आज हमारे समाज में हिंसा जिस क्रूर मोड़ पर आ गई है वहां से उसकी वापसी बहुत मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि आर्थिक गैरबराबरी, शहरीकरण और औद्योगीकरण व राजनीतिकरण ने समाज को संवेदनहीन बनाने के सारे औज़ार मुहैया करा दिए है. प्रचार माध्यमों ने इस संवेदनहीनता को और भी बढ़ाया है. फिल्मों, टेलीविज़न व अन्य संचार माध्यमों यथा इंटरनेट, वीडियोगेम्स आदि की भूमिका भी कम ज़िम्मेदार नहीं है. आज तो बच्चों को दिए जाने वाले खिलौने तक हिंसा के प्रमुख इंस्टिंक्ट को आधार बनाकर तैयार किए जा रहे हैं. ऐसे में अहिंसा का विचार जो सामाजिक प्रचलन कि डोर थामे आगे बढ़ रहा था उसकी पकड़ कमज़ोर होती दिख रही है. कोई भी समाज जब किसी को ज़िंदा जलाकर मज़ा ले या बलात्कार के बाद अपने पौरुष की पीठ ठोंके तो समझना चाहिए कि गड़बड़ी कहीं बहुत गहरे पैठ गई है. गोधरा का दंगा हो या दिल्ली की निर्भया, मुज़फ़्फ़रनगर की हिंसा हो या मऊ में साम्प्रदायिक उत्पात, हर बार कहीं न कहीं लोगों में संवेदनहीनता का मुज़ाहिरा दिखा. आखिर भारत जैसे देश में जहां अहिंसा राष्ट्र की मुख्यधारा का हिस्सा हो वहां ऐसी संवेदनहीनता क्यों?

इस सिलसिले में एक तरफ ब्रेख्त के नाटक चॉक्स सर्किल का एक संवाद याद आता है, जहां नायिका कहती है कि तुम्हें देखकर एक लड़की डर रही है और तुम्हें शर्म नहीं आती? और दूसरी तरफ फ़िल्म शोले का गब्बर याद आता है जो अपने कांपते डरते साथियों की मज़ा ले–लेकर हत्या करता है, दोनों कि अपनी–अपनी भूमिकाएं हैं. ब्रेख्त और गब्बर आखिर हम अपना रोल मॉडल किसे मानें. ब्रेख्त ने जो कोशिश कि थी, शोले उसके उलट भाव देता है. यही असर हमारे समाज में आज दिखता है और कोई मुज़फ़्फ़रनगर या गोधरा खड़ा हो रहा है. ज़रा दूर तक देखें तो यह उसी उपभोक्ता संस्कृति की देन दिखाई देगी, जहां आदमी भी एक वस्तु से अधिक कुछ भी नहीं रहा. यहां हर चीज बिकाऊ है और उसकी अलग कीमत है का मूलमंत्र प्रभावी हो चला है.

कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि प्रेम और भाईचारे की बात दुनिया की लगभग हर कौम के प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है और हिंदुस्तान के लिए ये कोई अनूठी बात नहीं है. पर ये एक तथ्य है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में जहां ये बातें आम तौर पर किताबी चीज़ और एक सपना बनकर रह गईं, वहीं भारत में उसे जीवन पद्यति में उतारने की कारगर कोशिश हुई. दार्शनिक पतंजलि ने प्राचीन कल में सत्याग्रह की जो बात कही उसे हिंदुस्तान की जनता ने गांधी जी के नेतृत्व में कर्म में उतारा और अंततः एक ऐसा रास्ता तैयार हुआ जो हमें आज़ादी की मंज़िल तक ले गया. यह भारतीय संस्कृति की अहिंसा प्रवत्ति ही है, जहां हिंसा से भरपूर साहित्य (महाभारत) में भी मन को अमन चैन कि दिशा देने वाली गीता भी मौज़ूद है. भारत में आज की पीढ़ी में ये आम धारणा घर कर गई है कि अहिंसा की वकालत करना नपुंसकता को तर्कसंगत बनाना है, पर ऐसा नहीं है. गांधी जी ने भी अहिंसा और प्रेम कि सच्ची कसौटी निर्भयता को बताया है, यानि आप जितने ही अहिंसक होते हैं आपका डर उतना ही कम होता है. हिंसा का भाव भय से पैदा होता है अपने साथ हथियार लेकर चलने वाला व्यक्ति मूलतः एक भयभीत और अशांत व्यक्ति है. ऐसा नहीं है कि भारत में पहले हिंसा नहीं थी. भारत में शक्ति पूजा इस बात का द्योतक है. अहिंसक होने का अर्थ कायर होना तो कतई नहीं है, गीता में भी सत्य के लिए हथियार उठाने की वकालत कि गई है, लेकिन उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि क्रूरता भारतीय समाज में स्वीकार्य थी. समाज में गलत परम्पराओं और अंधविश्वासों के कारण बलि आदि की गलत प्रथा ज़रूर चल पड़ी थी.

बहरहाल आर्थिक गैरबराबरी वाले समाज में हिंसा की सम्भावना से हम इन्कार नहीं कर सकते पर अपनी परंपरा को याद रखते हुए हम एक शांत समाज बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यह एक सच्चाई है कि शांत समाज ही आगे बढ़ सकता है और उन्ही परिस्थितियों में इसे रचनात्मक दिशा मिल सकती है. ■

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं)

आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह जेपी एसोसिएट्स के इशारे पर काम कर रहा है. आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन उनकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं है. गौरतलब है कि जेपी ने संरक्षित वन क्षेत्र में एक नहीं, दो संयंत्र स्थापित कर लिए हैं, जो पूरी तरह पर्यावरण नीति के ख़िलाफ़ है. राज्य सरकार और प्रशासन संयंत्र मालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है.

कैमूर की पहाड़ियों को बचाने की जंग

नवीन चौहान

हमारे देश में सरकारें पूरी मुस्तैदी के साथ कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करती हैं. यदि कोई आदेश औद्योगिक घराने के पक्ष में आ जाता है तो केंद्र और राज्य की पूरी सरकारी मशीनरी उस आदेश के पालन में जुट जाती है. खासकर तब, जब मुद्दा जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ा हो. इनसे संबंधित आदेशों के पालन में प्रशासन की मुस्तैदी देखते ही बनती है. ऐसा लगता है कि देश में सबकुछ नियम क़ायदे से चल रहा है और क़ानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी क़ीमत पर नहीं बख़्शा जाता, लेकिन जब क़ानून का चाबुक टाटा, बिड़ला, अंबानी जैसे किसी बड़े औद्योगिक घराने पर पड़ता है, जैसा कि हाल ही में कोयला घोटाले में हुआ, तब सरकार और उसके मंत्रियों के औद्योगिक घराने को बचाने की छटपटाहट देखते ही बनती है. औद्योगिक विकास के नाम पर इन ख़ास लोगों को बचाने के लिए उलूल-जुलूल तर्क गढ़े जाते हैं और क़ानून में समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ाते हुए क़ानून की व्याख्या ही दूसरे ढंग से कर दी जाती है. इसका परिणाम यह होता है लूपहोल का फ़ायदा उठाकर ऐसे लोग क़ानूनी शिकंजे से बाहर निकल जाते हैं. यदि लोग जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दों पर औद्योगिक घरानों का विरोध करते हैं तो उनकी बात सुनने की बजाय साम, दाम, दंड, भेद आदि तरीक़ों से उनका दमन करने की कोशिश की जाती है. लोगों के पास अहिंसक तरीके से आंदोलन करने और अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब बात सीधे तौर पर औद्योगिक घरानों के विरोध की आती है, तब जनता के लिए, जनता द्वारा बनी सरकार और सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला ही जनता के संवैधानिक अधिकारों को ताक पर रख देता है. तब ऐसा लगता है, जैसे उन्होंने लोगों के वेलफेयर की जगह औद्योगिक घरानों के वेलफेयर की कसम ले ली हो. यही कारण है कि ओडिशा के नियमगिरि में आदिवासियों ने वेदांता के ख़िलाफ़ जो ऐतिहासिक जंग जीती, उस जंग का परिणाम देश के दूसरे राज्यों में नहीं दिख रहा है.

ओडिशा के नियमगिरि के पहाड़ और जंगलों को बचाने जैसा ही आंदोलन इस समय मध्यप्रदेश के सीधी जिले में कैमूर की पहाड़ियों को बचाने के लिए चल रहा है. समस्या यह है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के कैमूर पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है. मामला मध्यप्रदेश के सीधी जिले के मझिगवां-बुढ़गौना लाइम स्टोन खदान का है. सीधी जिला कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है. ये पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर समानान्तर पूरे जिले में फैली हुई हैं. मोटे तौर पर संपूर्ण जिला पहाड़ी क्षेत्र है. सीधी से सतना के बीच फैली कैमूर पहाड़ियों के लगभग 506 एकड़ में स्थित चूना पत्थर खदान को सरकार ने जेपी ऐसोसिएट्स को आबंटित किया है. यह क्षेत्र संजय गांधी नेशनल पार्क के भी करीब है. इसके साथ ही सोन घड़ियाल अभ्यारण है, जो सीधे तौर पर इस खदान से प्रभावित होगा. यह वह क्षेत्र है, जहां 1950 में पहली बार सफेद शेर देखे गए थे. इन्हीं सफेद शेरों के संरक्षण के लिए आबंटित किए गए पहाड़ के पास मांद संरक्षण क्षेत्र में एक चिड़िया घर, एक बचाव केंद्र और सफेद बाघों के लिए प्रजनन केंद्र शुरू करने जा रहा है. दूसरी तरफ इसके आस-पास के वन्य और पहाड़ी क्षेत्र को खनन के लिए कंपनियों को दे दिया गया है. कैमूर पहाड़ियों में बाघ, चीतल, हिरण सहित कई वन्यजीवों का आवास है, पर वन विभाग द्वारा झूठा प्रतिवेदन दिया गया है कि आबंटित क्षेत्र में एक भी वन्य जीव नहीं हैं.

जेपी ऐसोसिएट्स इस खदान से निकाले जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग अपने सयंत्र में सीमेंट निर्माण में करेगा. इस क्षेत्र के ग्रामीण सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं, इसलिए ग्रामीण रोको-टोको और ठोको क्रांतिकारी मोर्चा की अगुवाई में पिछले तीन माह से आंदोलन कर रहे हैं. मोर्चा का आरोप है कि खदान आबंटन में नियमों का पालन नहीं किया गया है. मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने बताया कि सरकार ने कैमूर पहाड़ के जिस हिस्से को आबंटित किया है, उससे उस क्षेत्र की 15 पंचायतों का प्रभावित होना सुनिश्चित है. खदान के आबंटन के लिए ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पारित कराकर विधिसम्मत सहमति नहीं ली गई है, जबकि पर्यावरण मंजूरी के लिए बाकायदा जनसंसद आयोजित होनी चाहिए थी, लेकिन शासन-प्रशासन ने इसके लिए कोई पहल नहीं की. ग्रामसभा प्रस्तावों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई. हम पिछले तीन महीने से रेवेन्यू और वन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बात कर रहे हैं और इस विषय से जुड़ी रिपोर्टें लोगों से साझा करने को कह रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि सबकुछ क़ानून और नियामानुसार हो रहा है और यह कह कर बात टाल जाते हैं. कुछ ग्रामसभाओं ने तो जंगल की कटाई और पहाड़ों की खुदाई के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किए हैं.

नियमगिरी के मसले पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय को ग्रामसभाओं द्वारा वेदांता पर फैसला करने की प्रक्रिया की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ग्रामसभा के जरिये उन सभी की राय ली जाए, जिनका नियमगिरि पहाड़ से धार्मिक और भावनात्मक संबंध है, लेकिन कैमूर पहाड़ियों के खनन के मामले में ग्रामीणों की राय नहीं ली गई, न ही इस निर्णय से उनके जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन किया गया. पहाड़ का उत्खनन करने से यहां की सांस्कृतिक विरासत खत्म हो जाएगी. खनन के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी व जनजातीय लोगों के जीवन पर विपरीत असर पड़ेगा. खनन क्षेत्र के आसपास के खेत बंजर हो जाएंगे. जिसका सीधा-सीधा प्रभाव उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा.

इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की बंदरबाट और पर्यावरण एवं प्राणियों के अस्तित्व को उत्पन्न होने वाले खतरे को भांपते हुए आसपास के गांवों के लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया तो उसे दबाने के लिए खनन एजेंसियों ने प्रशासन के साथ मिलकर आंदालन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब सीधी और सतना जिले के दर्जनों गांव के लोगों ने टोको-रोको-ठोको क्रांतिकारी मोर्चा तथा छुइया घाटी बचाओ संघर्ष मोर्चा के साथ जंगल के वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षों से लिपटकर चिपको आंदोलन चलाया तो कुछ दिनों के लिए कटाई रोक दी गई, लेकिन एक बार फिर से वृक्षों की कटाई शुरू हो गई. टोको-रोको-ठोको मोर्चा के सचिव सचिन सिंह चौहान ने बताया कि आबंटन के बाद से ही पहाड़ पर पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया गया था, जो कि अब तक जारी है. 26 सितंबर को बुलडोजर की मदद से पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया था, जिससे कि जमीन तो पहले से ही बंजर है, यह दिखाया जा सके. पेडों की कटाई के काम को पुलिस के कड़े पहरे के बीच किया जा रहा था, इसलिए विरोध के लिए तीन ग्रामीण राजेश पांडेय, हरिशंकर तिवारी और देवेंद्र तिवारी 27 सितंबर को पहाड़ की चोटी पर आमरण अनशन के लिए बैठ गए. 11 दिन तक उनका यह अनशन चला और सरकार ने उनकी कोई मांग नहीं मानी. अब तक पहाड़ के लगभग 30 एकड़ हिस्से को समतल किया जा चुका है. अब बारी खनन की शुरुआत होने की है. ग्रामीणों की बात सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है. आंदोलन को कुचलने की हर संभव कोशिश की जा रही है.

इसी बीच 30 सितंबर को बिना अनुमति के जिला प्रशासन और जेपी ऐसोसिएट्स का पुतला जलाने की कोशिश करने के आरोप में 22 लोगों को आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया और पिपरांव पुलिस चौकी ले जाया गया. गिरफ्तार किए गए लोगों से जबरन आगे आंदोलन न करने का बॉन्ड भरवाने की कोशिश की गई, जब आंदोलनकारी नहीं माने तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन शाम होते-होते लगभग 1500 की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारियों को छोड़ने की मांग की, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों को एसपी और कलेक्टर के आने तक शांति बनाए रखने को कहा. रात को लगभग 10 बजे अचानक वहां की बिजली गुल हो गई और तब तक वहां एकत्रित हो चुके लगभग 500 पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया. लाठीचार्ज की वजह से लोग तितर-बितर हो गए. इसके बाद गिरफ्तार किए लोगों को सीधी जिला जेल ले जाया गया. सबसे मजेदार बात यह है कि जिन धाराओं में आंदोलनकारियों को एक पखवाड़े तक हिरासत में रखा गया, उन धाराओं में पलक झपकते ही मुचलके पर जमानत मिल जाती है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नहीं छोड़ा, जिससे कि आंदोलन की धार कुंद हो सके. सूत्रों के हवाले से यह पता चला कि इस विरोध प्रदर्शन को न बढ़ने देने के आदेश ऊपर से आए थे. बात यहीं खत्म नहीं हुई. इसके बाद मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी को जिले की कलेक्टर स्वाती मीणा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का नोटिस थमा दिया. नोटिस में टोको-रोको-ठोको मोर्चा के संयोजक पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चौकी का घेराव करके सरकारी कार्य में बाधा डाली. साथ ही एकत्र हुए लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाया. बिना इजाजत आंदोलन किया और पिपरांव चौकी पर जबरन कब्जा किया. यदि एक सप्ताह के अंदर उन्होंने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उन पर जिला बदर या अन्य कार्रवाई किए जा सकने की बात कही. जिला प्रशासन पर जो आरोप लगाए उनमें ही विरोधाभास है. पहला तो यह कि उमेश तिवारी सहित जिन 22 लोगों को जुलूस से गिरफ्तार करके चौकी ले जाया गया था, वे लोग चौकी पर कब्जा कैसे कर सकते हैं. नोटिस में मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने 30 सितंबर को 11.15 से रात के 10 बजे तक पिपरांव चौकी पर कब्जा किया, जबकि उन्हें चौकी से 2 किलोमीटर पहले मझिगवां माइंस नहर पुल से पहले दोपहर 1:30 बजे 22 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया या और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. यह बात पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में कही गई है. लाख टके का सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो जगहों पर एक साथ कैसे उपस्थित हो सकता है? इससे जिला प्रशासन की मंशा साफ हो जाती है कि वह किसके लिए काम कर रहा है.

आंदोलनकारियों ने जेपी सीमेंट्स बघवार को लीज पर दी गई वन भूमि का नक्शा, डीएफओ सीधी द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र, कलेक्टर सीधी द्वारा खदान के लिए जमीन लीज पर दिए जाने का प्रतिवेदन, भूमि गैर वन्य प्रायोजन के लिए जेपी ऐसोसिएट्स को दी गई स्वीकृति से संबंधित दस्तावेजों की मांग मुख्य प्रदेश संरक्षक से सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत की थी. अब सूचनाएं उपलब्ध होने के कारण आंदोलनकारी प्रथम अपील भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सूचनाएं शासन द्वारा अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं. न ही आबंटन के दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं. इससे तो यह सिद्ध होता है कि प्रदेश सरकार जेपी एसोसिएट्स के लिए बतौर एजेंट काम कर रही है.

सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत आवेदन दिए जाने के बावजूद इससे संबंधित सूचनाएं अब तक प्राप्त नहीं हो पाई हैं. इन दस्तावेजों के संबंध में जब चौथी दुनिया ने सीधी के वन मंडलाधिकारी आर बी शर्मा से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि नियामानुसार ही जमीन आबंटित की गई है. उन्होंने कहा कि पहाड़ की खुदाई से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा. जब चौथी दुनिया ने उनसे आबंटित किए गए क्षेत्र में पेड़ों के धनत्व और वहां वन्यजीवों की संख्या के संबंध में जानकारी चाही, तब इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. जब इसी विषय के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (वन) एस पी एस गहरवार से बात की तो उन्होंने बताया कि निर्धारित सर्वे यहां किया गया था. जेपी एसोसिएट्स ने भारत सरकार को सफेद चूना पत्थर की खुदाई के लिए आवेदन दिया था, जितनी जगह नियमानुसार उपयुक्त पाई गई है, उतनी ही जमीन का आबंटन किया गया है. मैंने स्वयं यह अनुमोदन किया है कि खुदाई के दौरान किसी भी तरह नियमों का उलंघन होता पाया गया तो लीज निरस्त समझी जाएगी.

आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह जेपी एसोसिएट्स के इशारे पर काम कर रहा है. आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन उनकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं है. गौरतलब है कि जेपी ने संरक्षित वन क्षेत्र में एक नहीं, दो संयंत्र स्थापित कर लिए हैं, जो पूरी तरह पर्यावरण नीति के खिलाफ है. राज्य सरकार और प्रशासन संयंत्र मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है. अलबत्ता आंदोलनकारियों पर दमनचक्र चलाए हुए है. प्रदेश विधानसभा चुनावों के मुहाने पर खड़ा है, इसी महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाग्य का फैसला होना है. बावजूद इसके लोगों के विरोध को दरकिनार कर प्रदेश सरकार औद्योगिक घरानों के पक्ष में काम करती दिख रही है. इस कारण लोगों का असंतोष राज्य सरकार के प्रति खुल कर बाहर आ रहा है. यह खदान मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उर्फ राहुल भैया के विधानसभा क्षेत्र में आती है. उन्होंने कुछ समय पहले अंग्रेजी के एक अखबार में बयान दिया था कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जेपी ग्रुप की जेब में हैं तो जिला प्रशासन ग्रामीणों से क्यों बात करेगा. प्रदेश बीजेपी पूरी तरह अवैध खनन में लिप्त है. कांग्रेस आंदोलन का समर्थन करेगी, लेकिन न तो यह विषय सीधी में चुनावी मुद्दा बन रहा है, न ही कोई राजनीतिक दल खुलकर आंदोलनकारियों के समर्थन में सामने आ रहा है. इससे तो चोर-चोर मौसेरे भाई ही नज़र आ रहे हैं. आंदोलनकारी इस लीज को निरस्त कराने और तत्काल कार्य रोकने के लिए उच्च न्यायालय की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कि खनिज संपदा और धरोहरों को लूट से बचाया जा सके. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

देश में खनिज संपदाओं की लूट बदस्तूर जारी है. सरकार और उसकी मशीनरी इस लूट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले आंदोलनकारियों का दमन करने की ठान ली है. वास्तविकता यह है कि कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़ प्लानिंग के तहत प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबाट में लगा है. कुछ यही हाल है इस समय कैमूर के पहाड़ियों की. इस समस्या से सरकारों की मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है.

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने इस दावेदारी के बाद अपने पहले ही भाषण में कहा था कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है, इसलिए हम सेना का इस्तेमाल पाकिस्तान को सबक़ सिखाने के लिए करेंगे. यह एकदम बेतुकी बात है. हमें लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है. हमें प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है. अगर हम अपने पड़ोसियों से जुड़े मसलों को सेना के माध्यम से ही हल कर सकते हैं तो पाकिस्तान की तरह हमारे देश का नेतृत्व भी आर्मी चीफ ही कर सकते हैं.

देश राजनीतिक विकल्पहीनता की स्थिति में है

बीते दिनों दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वाम दलों ने सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ एक रैली का आयोजन किया. चूंकि स्टेडियम भरा हुआ था, इसलिए ज़ाहिर है रैली में लोगों की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी. कई पार्टियों के नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया, जिनमें मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, एच डी देवेगौड़ा, बाबू लाल मरांडी के अलावा लेफ्ट पार्टियां– जिनमें सीपीआई, सीपीआई (एम), फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ–साथ कुछ क्षेत्रीय दल जैसे असम गण परिषद प्रमुख थे. इसके अलावा नवीन पटनायक, अन्ना डीएमके, डीएमके और शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने–अपने प्रतिनिधि भेजे थे. कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी पार्टियों की एकजुटता को उत्साहजनक कहा जा सकता है, लेकिन यह रैली केवल सांप्रदायिकता का विरोध करने के लिए आयोजित की गई थी. इन सभी राजनीतिक दलों ने इस मंच से न तो किसी गैर कांग्रेस, न ही गैर भाजपाई विकल्प की बात की. काफ़ी हद यह ठीक भी था, क्योंकि इन पार्टियों के आपस में ही कई विरोधाभास हैं.

इसी विरोधाभास के चलते जहां मुलायम सिंह होंगे, वहां मायावती नहीं जाएंगी. इसी तरह अगर मंच पर वाम दल हैं तो ममता बनर्जी उसमें नहीं शामिल होंगी. जहां एआईडीएमके है, वहां डीएमके साथ नहीं आ सकती. स्पष्ट है इनके बीच अन्तर्विरोध तो हैं ही. इन अन्तर्विरोधों के बावजूद अगर यह सभी राजनीतिक दल और इनके समर्थक एकजुटता के साथ सांप्रदायिकता के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से देश अपने सामने मौजूद सबसे बड़े ख़तरे से बच जाएगा. हम किसी ऐसे प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं कर सकते जो न केवल सांप्रदायिकता की भाषा का इस्तेमाल करता हो, बल्कि फासीवाद की भी.

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने इस दावेदारी के बाद अपने पहले ही भाषण में कहा था कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है, इसलिए हम सेना का इस्तेमाल पाकिस्तान को सबक़ सिखाने के लिए करेंगे. यह एकदम बेतुकी बात है. हमें लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है. हमें प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है. अगर हम अपने पड़ोसियों से जुड़े मसलों को सेना के माध्यम से ही हल कर सकते हैं तो पाकिस्तान की तरह हमारे देश का नेतृत्व भी आर्मी चीफ ही कर सकते हैं.

वास्तव में महत्वपूर्ण तो यह है कि हमें लोकतंत्र के उस दौर में लौटने की ज़रूरत है जो 1947 से 1991 के बीच था. हालांकि, 1991 के बाद भी देश में लोकतंत्र ही है, लेकिन इसके शासन की बागडोर अब हमने कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में सौंप दी है. यही सबसे बड़ी मुश्किल है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका झुकाव कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ़ है. उन्हें इसमें कोई नुकसान नहीं दिखता. कॉरपोरेट सभी चीज़ों पर कब्ज़ा करता जा रहा है. साथ ही पार्टी कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद व्याप्त करके अल्पसंख्यकों का ख़ात्मा करना चाहती है. जनजातियों के बारे में न तो उन्हें कोई चिंता है और न ही उनकी समस्याओं को वे समझते हैं.

दूसरी तरफ़ कांग्रेस पार्टी भले ही अपनी पुरानी दृढ़ता दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके काम बिल्कुल इसके विपरीत हैं. बेशक उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं जैसे मनरेगा की शुरुआत ग़रीबों की मदद करने के लिए की, लेकिन बड़े पैमाने पर देखा जाए तो उन्होंने देश को जो नुकसान पहुंचाया है, पार्टी उसे नहीं समझ पा रही है. नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर से ही जो आर्थिक नीतियां देश में लागू थीं, 1991 के समय तत्कालीन सरकार ने उन नीतियों पर पूरी तरह से यू–टर्न ले लिया. ठीक है! आप एक चुनी हुई सरकार हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. लेकिन अगर आप संविधान में दी हुई परिकल्पना को ही बदल रहे हैं, तब आपका यह दायित्व बनता है कि आप देश के सामने एक दूरदर्शी परिकल्पना रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

1991 से बीस साल बाद 2011 में पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय उत्पादन नीति बनाने की घोषणा की. लाइसेंसिंग प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन यह बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई कि उसकी जगह कोई नई व्यवस्था की जाए. 20 वर्ष से यह क्षेत्र बिना किसी नीति के ही चल रहा है.

वास्तव में इस क्षेत्र में नीतियां बनाने की ज़रूरत है. जब तक देश के पास मज़बूत आर्थिक आधार नहीं होगा, तब तक आप दुनिया के दूसरे मुल्कों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते. भारत को सरकार ने विफल नहीं किया, उद्योगपतियों ने विफल नहीं किया, बल्कि कृषि व्यवस्था ने किया. ऐसा इसलिए है क्योंकि किसानों और कृषि की बेहतरी की लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर सरकार गंभीर नहीं है. यह ग़रीब किसान ही हैं जो खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो दुनिया की कुल आबादी के सातवें हिस्से के लिए अन्न उगा रहे हैं. देश बचा है तो केवल ग़रीब किसानों की वजह से, इसमें सरकार का योगदान बेहद कम है. निश्चित रूप से सरकार की नीतियां जैसे मुफ़्त बिजली, खाद व अन्य सुविधाएं किसानों की बेहतरी के लिए हैं. अगर सरकार विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुने, तब तो वह किसानों को छूट देना बंद कर देगी और उन्हें बाज़ार के हवाले कर देगी. ऐसी स्थिति में देश के सामने भुखमरी की स्थिति आ जाएगी. हम लोग दुनिया के कई छोटे देशों की तरह निर्धन देशों की श्रेणी में आ जाएंगे. भाग्यवश ऐसा कभी हुआ नहीं.

सरकार आंकड़ों की बानगी को समझ नहीं रही है. देश में 75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो अतिरिक्त उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, कि उसे बाज़ार में बेच सकें. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक कह रहे हैं कि सब्सिडी को बंद करो और किसानों को अपना माल बाज़ार के मूल्य पर बेचने दो. अरे जब किसानों के पास अतिरिक्त उत्पादन ही नहीं है, वो केवल अपने खाने भर का अनाज पैदा कर पा रहे हैं और अगर उन्हें सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी तो वे खेती के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तब किसान रोज़गार की तलाश में बाज़ार में आ जाएंगे. ऐसे में देश के सामने क़ानून व्यवस्था का संकट पैदा हो जाएगा.

देश में चुनाव होने जा रहे हैं. जो भी नई सरकार बनने जा रही है, उसे चाहिए कि देश के सामाजिक ढांचे के प्रति गंभीरता से सोचे. आप इसे बदल नहीं सकते. अभी भी देश में ग़रीबी व्याप्त है. जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाएगा, यह रहेगी. सवाल है कि कैसे? देश में तक़रीबन 15 प्रतिशत मुसलमान हैं. उन्हें उम्मीद का रास्ता कैसे दिखाया जाएगा. उनके गुस्से को कैसे थामा जाएगा. यही सबसे बड़ी समस्या है.

हमारे सामने दो विकल्प दिख रहे हैं. कांग्रेस पार्टी सोचती है कि उद्योगपति इतना धन पैदा कर सकते हैं कि ग़रीबी चली जाएगी और बीजेपी सोचती है कि हिंदू इतने शसक्त हो जाएंगे कि उनकी ताक़त के सामने मुस्लिम ठहर नहीं पाएंगे. दोनों ही ग़लत हैं. हमें ऐसे दलों की ज़रूरत है जो गरीबों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के प्रति सहानुभूति रखे. अगर देश के कई ज़िले माओवाद से प्रभावित हैं तो वह इसलिए क्योंकि वहां जनतातियों के साथ बुरा बर्ताव हुआ है. अगर आप जनजातियों में उनके उत्थान की उम्मीद जगाएंगे तो माओवाद सफल नहीं हो सकता. अगर पुलिस जनजातियों की समस्याओं को सुलझा पाती और सेना मुद्दों को सुलझा पाती तो देश में लोकतांत्रिक सरकारों की कोई ज़रूरत नहीं होती. नेतृत्व की आवश्यकता न होती. जितना जल्दी लोग सही ढंग से सोचें उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

परिस्थिति का इलाज

ठाकुर दास बंग

गांधी ने कहा था कि आज़ादी नीचे से शुरू होनी चाहिए. हर गांव में प्रजातंत्र या पंचायत का राज होगा. उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी. इसका मतलब यह है कि हर गांव को अपने पांवों पर खड़ा होना होगा, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके. सच्चा स्वराज्य थोड़े से लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से हासिल नहीं होगा, बल्कि तब होगा, जब हर व्यक्ति में सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार करने की क्षमता आ जाएगी.

देश ने यह दिशा छोड़ दी, इसीलिए वह आज समस्याओं का एक जंगल बन गया है. हर आदमी एक या दूसरी समस्या से घिरा होकर परेशान है. अलग–अलग समस्याओं से लड़ने की कोशिश में लोग हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि समस्याएं वास्तव में अलग–अलग हैं नहीं, वे मौजूदा व्यवस्था और मूल्यों की गिरावट के परिणाम हैं.

इस अंधकार में भी आज कई जगह परिवर्तन की आकांक्षा से प्रेरित अनेक नि:स्वार्थी व्यक्ति परिस्थिति से जूझ रहे हैं, यह आशा का चिन्ह है. पर आज की परिस्थिति की पुकार है कि ये सब शक्तियां संगठित हों. अलग–अलग समस्याओं या प्रश्नों पर शक्ति लगाना अब कारगर नहीं होगा. मौजूदा व्यवस्था का आमूल बदलकर एक स्वावलंबी, विकेंद्रित और शोषणरहित व्यवस्था के निर्माण के लिए जनता तैयार हो, यही आज की परिस्थिति का इलाज और उसकी मांग है. ऐसा करना आज आदर्श का सवाल नहीं है, अस्तित्व बचाने का धर्म है. एक–एक दिन जो बीत रहा है, वह इस संकट को और अधिक गहरा तथा लाइलाज बनाता जा रहा है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में जिनका निहित स्वार्थ है, वे इस बीच अपना शिकंजा और मजबूत करते जा रहे हैं.

अत: नई व्यवस्था के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए हम राष्ट्र को नीचे लिखी दिशा में बढ़ने का निवेदन करते हैं.

1–नागरिक–अधिकार, व्यक्ति स्वातंत्र्य, प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद है. इनका सतत विस्तार होना चाहिए. इन्हें कुंठित करने वाली सभी गतिविधियों का सजग होकर प्रतिकार करना चाहिए.

2– अपना कारोबार खुद चलाना हर गांव का जन्मसिद्ध अधिकार है. अत: गांव के अंतर्गत आने वाली जमीन, जंगल आदि को व्यवस्था, गांव के झगड़ों का गांव में निबटारा, सफाई, कंपोस्ट, साक्षरता, व्यसन–मुक्ति आदि रचनात्मक काम ग्राम स्तरीय सरकारी कर्मचारियों पर देख–रेख तथा नियंत्रण आदि के काम ग्रामसभाएं अपने हाथ में लें. ग्रामसभा के अंतर्गत गांव के कमजोर तबकों को सशक्त करने का अभिक्रम हाथ में लिया जाना चाहिए, ताकि ग्राम–सभा में व अन्य स्वायत्त संस्थाओं में उनकी पूरी भागीदारी बने. गांव की तरह नगरों और कस्बों की जनता भी मुहल्ले–मुहल्ले में संगठित होकर यथासंभव अपनी व्यवस्था संभालने की ओर बढ़े.

3–जमीन पर गैर–हाजिर मालिकी समाप्त होनी चाहिए और जमीन जोतने वाले की होनी चाहिए. गाय–बैल खेती तथा ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था के अपरिहार्य आधार हैं. उनकी हर तरह से रक्षा और संवर्द्धन होना चाहिए. किसानों को अपनी उपज का वाजिब दाम और खेतिहर मजदूरों तथा कारीगरों को उनके काम की उचित मजदूरी मिले, साथ ही उपभोक्ताओं को भी उचित मुल्य शुद्ध चीजें मिले, इसके लिए कदम उठाने चाहिए. बेकारी निवारण, स्वावलंबन, तथा अंत्योदय की दृष्टि से गांव की योजना गांव में बननी चाहिए. गांव में घरेलू व ग्रामीण उद्योग प्रारंभ करने चाहिए और ग्रामकोश इक्ट्ठा करना चाहिए. जो चीजें गांव में छोटे उद्योगों द्वारा बन सकती हैं, उन्हें केंद्रित उद्योगों द्वारा बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. आर्थिक शोषण से बचने के लिए, ग्रामद्योगों से होड़ करने वाली केंद्रित उद्योग से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और गांधी जी की कल्पना के अनुसार स्वदेशी पर जोर देना चाहिए.

4– आजादी के बाद भी बड़े उद्योगों के हित में ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करके योजनाएं बनाई गईं. उनकी जगह सामान्य जन के हित, पर्यावरण के संतुलन व आगे आनेवाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बननी चाहिए. राष्ट्रीय योजना में आम आदमी की जरूरतों की पूर्ति को प्राथमिकता दी जाय तथा भोगवादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली विलास की वस्तुओं के उत्पादन व आयात पर रोक लगाई जाय. बड़े पैमाने के उद्योग–व्यवस्था की मालिकी और प्रबंध समाज, यानी उन उद्योगों में काम करने वाले कच्चे माल के उत्पादकों, उपभोक्ताओं, स्थानीय समाज तथा राज्य के प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए.

5– गांव के बाद जिला, प्रदेश या केंद्रीय स्तर पर जो सरकारें होंगी, उन पर तथा जनप्रतिनिधियों पर जनता का प्रभावकारी नियंत्रण रह सके, इसके लिए हर स्तर पर लोक–समितियां बनाई जाएं. लोकसभा, विधानसभा आदि हर स्तर की प्रतिनिधिक संस्थाओं में उनके क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन हो, यह संबंधित मतदाता स्वयं संगठित होकर तय करें. लोकप्रतिनिध की पहली जिम्मेदारी मतदाताओं के प्रति हो, पार्टी के प्रति नहीं. चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सके, इसके लिए चुनाव के कानून और नियमों में सुधार तथा दल–बदल का कानून बनाने के लिए जनता को दबाव लाना चाहिए. राजनीतिक दल खुद भी इस बारे में आचार संहिता बनाकर उसका कड़ाई से पालन करें. राजनीतिक दल रजिस्टर्ड होने चाहिए. उनके हिसाबों की विधिवत जांच होनी चाहिए और उनका सार्वजनिक प्रकाशन होना चाहिए.

6– संविधान के निर्देश के अनुसार शराबबंदी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शराब के उत्पादन व बिक्री पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए. उसे सरकारी आमदनी का जरिया हर्गिज न बनाया जाय. पीने वालों को समझाकर उनकी आदत छुड़ाने तथा गांव व मुहल्ले को शराब–मुक्त करने के लिए पहल करनी चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

देश ने यह दिशा छोड़ दी. इसीलिए वह आज समस्याओं का एक जंगल बन गया है. हर आदमी एक या दूसरी समस्या से घिरा होकर परेशान है. अलग–अलग समस्याओं से लड़ने की कोशिश में लोग हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि समस्याएं वास्तव में अलग–अलग हैं नहीं, वे मौजूदा व्यवस्था और मूल्यों की गिरावट के परिणाम हैं.

पाठकों की दुनिया

तीसरे मोर्चे के झूठे वादे

तीसरे मोर्चे की बैठक में 14 दल शामिल हुए, जिसमें नारा दिया गया कि सांमप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट होना चाहिए. विकास का नाता इनसे दूर–दूर का नहीं है, न ही इन्होंने रोजगार पर कोई बात की, लेकिन नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा छाये रहे. नीतीश को देश को लूट रही कांग्रेस को कोसना चाहिए था, क्योंकि वह 9 सालों से देश को लूट रही है. नीतीश तो केवल गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कोसते रहे. नरेंद्र मोदी भी एक उन्हीं की तरह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको कोसने से क्या फायदा. इनमें से अधिकतर दल वहीं हैं, जो अपने को समाजवादी बताते हैं, लेकिन ये केवल खुद को समाजवादी बताते हैं, ये सामजवादी हैं नहीं. ये सब केवल सत्ता के लोभी हैं, जनता को झूठे सपने दिखाने के सिवाय इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिस पर यह चुनाव लड़ सके. यह मोर्चा केवल एक छलावा है. इसके सिवाय कुछ नहीं. यह पार्टियां केवल सत्ता के लिए ही तीसरे मोर्चे का नाटक करती हैं. चुनाव बाद यह कुर्सी के लिए कांग्रेस या भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें शामिल पार्टियों के अपने–अपने राग हैं. नीतीश कुमार से लेकर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं. राममनोहर लोहिया कहते थे कि कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन यह समाजवादी पार्टियां सत्ता के लिए देश को एक बार भी बर्बाद करने के लिए कांग्रेस के हाथ में सत्ता का डोर थमाना चाहती हैं. 2014 लोकसभा में चुनाव किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो यह पार्टियां सांप्रदायिकता का नाटक करेंगी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगी. इन पार्टियों की असली मंशा यहीं है कि अपने–अपने स्वार्थों को पूरा करो. देश को बर्बाद करने का फिर एक मोर्चा खड़ा किया जा रहा है. तीसरे मोर्चे की सच्चाई क्या है, यह सभी जानते हैं. इनकी सच्चाई 1990 और 1996 में जनता देख चुकी है.

अभिषेक, बलिया

सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता

वामपंथियों की अगुवाई में राजधानी दिल्ली में तीसरे मोर्चे की बात करने वाली 14 क्षेत्रीय पार्टियों का दिल्ली सम्मेलन किया गया, जिसमें कहा गया कि सारे दल सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. सम्मेलन में शामिल सभी नेताओं ने गैर कांग्रेसवाद और भाजपा विरोधी राजनीति को आगे बढ़ाने की बात की. क्या भारत में केवल एक सांप्रदायिकता ही मुद्दा रह गया है? कांग्रेस से लेकर तीसरे मोर्चे की पैरवी करने वाली ये पार्टियां केवल सांप्रदायिकता की बात करती हैं. क्या भारत में अब गरीबी, विकास, रोजगार, भूखमरी, किसानों आदि की कोई समस्या नहीं है, जो ये पार्टिया केवल सांप्रदायिकता की बात करती हैं. यह वहीं पार्टियां हैं, जो 1990 में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थीं. 1996 में जब अटल जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बहुमत नहीं हासिल करने के कारण गिर गई थी तो इन्हीं पार्टियों ने फिर एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था. ये पार्टियां केवल सत्ता की लोभी हैं. इनमें से सभी एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों में शामिल रहीं हैं. ये जिस सांप्रदायिकता की बात करती हैं, इन पार्टियों के अधिकतर लोगों पर हत्या का आरोप है. यदि बात करें तो कांग्रेस से लेकर सपा जैसे पार्टियों पर हत्या के आरोप हैं. कांग्रेस पर सिखों की हत्या का आरोप है और सपा पर कारसेवकों (राम भक्तों) के हत्या का आरोप है. केवल आरोप लगने से पार्टी और नेता सांप्रदायिक हो जाता है तो यह पार्टियां कैसे धर्मनिरपेक्ष हुईं.

ओमकार सिंह, पटना

सरकार की नाकामी है दंगा भड़कना

मुजफ्फरनगर में दंगा एक बार फिर भड़क गया है. यह सरकार की नाकामी है कि वह दंगों पर काबू नहीं कर पा रही है. राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगे में अपनों को खो चुके युवकों से आईएसआई संपर्क में है. इसकी जांच क्यों नहीं हुई? यदि यह सच है तो सरकार अपनी बदनामी के डर से यह सच छुपा रही है. आईएसआई भारत में दंगे फैला रही है तो यह मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है. एनआईए और बाकी जांच एजेंसिया यह पता लगाने में विफल रहीं है या राजनीति का शिकार होने से डर रहीं है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, जिनमें राजनीतिक द्वेष के कारण जांच एजेंसियों को कठघरे में खड़ा किया गया. यदि ऐसा है तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो कि सत्ता के मोह में सरकार देश को दंगो के आग में झोंक रही हैं. सरकार के लिए सत्ता पहले नहीं होना चाहिए. पहले देश होना चाहिए. राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं. उन्हें वोट के सिवाय कुछ और दिखता ही नहीं, सांप्रदयाकिता के नाम पर, जो देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे जनता को समझाना चाहिए. मुसलमानों के वोट के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, जिससे भेदभाव की राजनीति की जा रही है. अब देश के हिंदु और मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि यह आपको बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, आपको केवल लड़ाएंगे और चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यह सांप्रदायिकता के नाम पर जनता को डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं. जनता को चाहिए कि सांप्रदायिकता की बात करने वाले लोगों को चुनाव में सबक सिखाएं, जिससे यह मुद्दा खत्म हो जाए. केवल बात हो तो भाईचारे, विकास, रोजगार का, अन्यथा ये पार्टियां केवल सांप्रदायिकता के नाम पर देश में भेदभाव का बीज बोती रहेंगी.

आशा, भागलपुर

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

एक बड़ा ही मशहूर शेर है. *बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो क़तरा–ए–ख़ूं भी न निकला.* कुछ ऐसा ही माहौल बना जब तीस अक्टूबर को दिल्ली के तालकटोरा मैदान में सांप्रदायिकता के विरोध में 14 राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ. सम्मेलन में बार–बार कहा गया कि 17 राजनीतिक दल हैं और वहीं पर यह घोषणा हुई कि 14 राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं. तीन दलों का फ़र्क़ और वो भी आयोजकों के मुख से ही बार–बार इस अंतरविरोध का प्रकट होना आख़िर तक नहीं समझा पाया कि इस सम्मेलन में 14 दल थे या 17 दल थे. सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सांप्रदायिकता था. सांप्रदायिकता का विरोध करने का संकल्प वहां मौजूद सबने लिया, पर यह किसी ने नहीं बताया की आज सांप्रदायिकता का स्वरूप कैसा है. सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शब्द का इस्तेमाल किया फासिज्म. फासिज्म और सांप्रदायिकता में अंतर है. लेकिन वहां मौजूद जनता को सांप्रदायिकता और फासिज्म का फ़र्क़ और उसके मायने किसी ने नहीं बताया.

सांप्रदायिकता के विरोध की दिशा तय करनी होगी

यह भी सवाल उठा कि सांप्रदायिकता का विरोध आख़िर करें तो कैसे करें. इस पर सम्मेलन में किसी ने अपना विचार नहीं रखा. क्या सांप्रदायिकता का विरोध सिर्फ़ चुनाव के ज़रिए किया जा सकता है या सांप्रदायिकता का विरोध किसी अन्य माध्यम से भी किया जा सकता है. जो महान विद्वान नेता वहां मौजूद थे उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा. सबसे महत्वपूर्ण बात, वामपंथी नेताओं के अलावा किसी ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया. जब सांप्रदायिकता और फासिज्म की बात हो रही है तो उसका प्रतीक कौन है, यह भी तो स्पष्ट होना चाहिए. आपसी बातचीत में जब ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, लेकिन मंच पर से किसी ने नाम नहीं लिया. मुलायम सिंह यादव ने तो कहा कि जब कोई नाम नहीं ले रहा है तो मैं क्यों लूं. मुलायम सिंह जी से यह अपेक्षा थी कि वो जलेबी नहीं बनाएंगे और सीधे–सीधे सांप्रदायिकता के लिए ज़िम्मेदार ताक़तों और उनके नेताओं का नाम लेंगे, लेकिन वो भी कन्नी काट गए.

दरअसल, सांप्रदायिकता निरपेक्ष शब्द नहीं है, सापेक्ष शब्द है. सांप्रदायिकता अमूर्त नहीं है, मूर्त है. सांप्रदायिकता को पारिभाषित करना आवश्यक है. लेकिन सिर्फ़ सांप्रदायिकता की बात करना और उसका असर क्या हो रहा है, इसकी चर्चा न करना सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ लड़ाई को कमज़ोर करना है. सांप्रदायिकता की वजह से देश को क्या–क्या भुगतना पड़ सकता है और सांप्रदायिक शक्तियों को कैसे काबू में किया जा सकता है इसकी बात इस सम्मेलन में नहीं हुई. शायद सम्मेलन में भाषण देने आए सारे नेता यह समझते रहे कि जैसा वो समझते हैं, वैसा ही जनता समझती है और नेताओं की यही ग़लतफ़हमी उन्हें जनता से दूर कर देती है. बाबू लाल मरांडी का भाषण अख़बारों में कहीं कोट नहीं हुआ, लेकिन बाबू लाल मरांडी ने एक बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि हमें सांप्रदायिकता से कोई लेना–देना नहीं है. हमारे यहां ग़रीबी है, भूख है, बेकारी है. इनके ख़िलाफ़ अगर कोई रणनीति बनती है तो उसका स्वागत होना चाहिए. केवल सांप्रदायिकता पर बहस करके क्या इन मुश्किलों से छुटकारा पाया जा सकता है? हमारा मानना है कि बाबू लाल मरांडी कुछ हद तक सही हैं, लेकिन बाबू लाल मरांडी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो वहां सिर्फ़ 250–300 लोग थे, क्योंकि वहां में सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले लोग नहीं आए थे, बल्कि दलों के लोग आए थे. मुलायम सिंह का समर्थन करने वाले लोग टोपियां लगाए हुए बैठे थे, जिससे यह पता चल रहा था कि समाजवादी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में या कहें कि सबसे बड़ी संख्या में हाल में मौजूद थे. इसीलिए श्री देवेगौड़ा के बाद जब दूसरे प्रतिनिधि को भाषण देने के लिए बुलाए जाने की बात होने लगी, तो मुलायम सिंह जी के समर्थक शोर मचाने लगे कि पहले मुलायम सिह जी से भाषण कराया जाए. मुलायम सिंह जी ने भाषण दिया. अच्छा भाषण दिया. लेकिन वह भाषण भी लोगों के मन में उत्साह नहीं पैदा कर पाया. वास्तविकता तो यह है कि किसी के भी भाषण ने उपस्थित कार्यकर्ताओं के बीच जोश नहीं पैदा किया. हां, नेताओं के समर्थकों ने बीच–बीच में अपने नेताओं का नाम लेकर नारे लगाकर जोश ज़रूर प्रकट किया. नीतीश कुमार ज़िंदाबाद, शरद यादव–केसी त्यागी ज़िंदाबाद, मुलायम सिंह यादव ज़िंदाबाद इस तरह के नारे वहां लग रहे थे. सबसे संयत वामपंथी दलों के कार्यकर्ता रहे. उनकी संख्या कम भी थी, लेकिन वे अनुशासन में रहे.

सांप्रदायिकता निरपेक्ष शब्द नहीं है, सापेक्ष शब्द है. सांप्रदायिकता अमूर्त नहीं है, मूर्त है. सांप्रदायिकता को पारिभाषित करना आवश्यक है. लेकिन सिर्फ़ सांप्रदायिकता की बात करना और उसका असर क्या हो रहा है, इसकी चर्चा न करना सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ लड़ाई को कमज़ोर करना है. सांप्रदायिकता की वजह से देश को क्या–क्या भुगतना पड़ सकता है और सांप्रदायिक शक्तियों को कैसे काबू में किया जा सकता है, इसकी बात इस सम्मेलन में नहीं हुई. शायद सम्मेलन में भाषण देने आए सारे नेता यह समझते रहे कि जैसा वो समझते हैं, वैसा ही जनता समझती है और नेताओं की यही ग़लतफ़हमी उन्हें जनता से दूर कर देती है.

इस सम्मेलन का कोई नतीजा देश के सामने नहीं निकला. दरअसल, लोगों के मन में यह ख़्वाहिश थी कि जितने भी दल गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई विचारधारा के हैं, वो कम से कम ऐसा संकेत देंगे कि वो आपस में किसी न किसी तरह का तालमेल करें और मिलकर चुनाव लड़ें, ताकि सांप्रदायिकता विरोध के नाम पर ही सही, कम से कम कोई एका होता तो दिखाई दे. पर सबसे पहले नीतीश कुमार ने यह कहकर कि अभी कोई एकता संभव नहीं है और वो एकता, जो हो सकती हो, उसकी कोशिश करनी चाहिए, बता दिया कि अब कोई भी आकर यह नहीं कहने वाला है कि यहां जो मौजूद लोग हैं, उन्हें एक मोर्चा बनाना चाहिए. इसीलिए जब बाक़ी नेताओं ने, जिनमें वामपंथी नेता भी शामिल थे, यह कहा कि इस सम्मेलन से किसी मोर्चे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो फिर सवाल उठता है कि सांप्रदायिकता के विरोध में यह सम्मेलन बुलाया क्यों गया? अच्छा होता कि सांप्रदायिकता के विरोध में जो प्रस्ताव सम्मेलन में रखा गया, उसके लिए इतना तामझाम किए बिना इन दलों के दस्तख़त के साथ उसे अख़बारों में दे दिया जाता. यह प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है, जो लोगों को कोई दिशा दे सके.

दिमाग में सवाल कुलबुला रहा है कि आख़िर यह हुआ क्यों? तो ऐसा लगता है कि यह सम्मेलन बिना किसी होमवर्क के, बिना किसी निश्चित दिशा के सिर्फ़ इसलिए हुआ, ताकि देश में एक संदेश जाए कि हमारे दलों का भी कोई अस्तित्व है. नीतीश कुमार से लोग सुनना चाहते थे नरेंद्र मोदी के भाषणों का जवाब, लेकिन नीतीश कुमार ने एक हलके उल्लेख के अलावा नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं दिया. वहां पर डी. पी. त्रिपाठी थे, जो कि एनसीपी के सांसद व महासचिव हैं. उन्होंने साफ कहा कि हम सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, भले ही हम सरकार में शामिल हैं, लेकिन हम किसी मोर्चे में शामिल नहीं होने वाले. ज़ाहिर है, महाराष्ट्र में वे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां किसी मोर्चे में कैसे शामिल हो सकते हैं.

अब जबकि चुनाव सिर पर हैं तो ऐसे सम्मेलनों का कोई अर्थ है नहीं. या तो पहले आपस में बातचीत हो गई होती. एक प्रोग्राम तय हो गया होता और उस प्रोग्राम को मानने वाले लोग कम से कम यह संकल्प दोहराते कि हम अगले एक महीने में कोई न कोई ढांचा तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई. और बात इसलिए नहीं हुई, क्योंकि कोई बात करना नहीं चाहता. अगर मुलायम सिंह जी इसमें पहल करते तो ज़रूर तीसरे मोर्चे को लेकर कोई तस्वीर उभर सकती थी, लेकिन मुलायम सिंह अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव उन्हें कांग्रेस के साथ लड़ना या अकेले लड़ना है. कांग्रेस बार–बार कह रही है कि वह किसी के साथ समझौता नहीं करेगी, लेकिन लोग हैं कि कांग्रेस को लेकर फिलर्स भेज रहे हैं. ऐसे फिलर भेजने वालों में नीतीश कुमार भी हैं और मुलायम सिंह यादव भी. वामपंथी दल कांग्रेस की ख़िलाफ़त इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस का साथ अगर फिर से देना पड़ा तो उन्हें उस स्थिति को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है. बहरहाल, यह कवायद बिल्कुल बेकार थी. इसका कोई मतलब नहीं था. मुझे तो इस कवायद का मक़सद भी समझ में नहीं आया. जो लोग सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, उन्हें यह तय करना होगा कि वे सापेक्ष विरोध करते हैं या निरपेक्ष विरोध करते हैं. यह सम्मेलन सापेक्ष विरोध का था. सापेक्ष विरोध का तरीक़ा क्या हो, कैसे विरोध करें, क्यों विरोध करें और लोकसभा में इस विरोध का वास्तविक स्वरूप क्या हो, जब चुनाव आएं तो सांप्रदायिकता विरोधी ताक़तें एक–दूसरे के सामने खड़ी हों या सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हाथ में हाथ डाल कर चलें? यह सवाल 30 अक्टूबर से पहले भी मुंह बाए खड़ा था और आज भी मुंह बाए खड़ा है.■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राजनीति लोगों को अलग करती है

भारत में जितने भी राजनेताओं की हत्याएं हुई हैं, सभी के पीछे कोई न कोई कारण था. ऐसा सिर्फ़ भारत में ही नहीं है, वरन पूरा दक्षिण एशिया राजनीतिक हिंसा के चपेट में रहा है. आमतौर पर बौद्ध धर्म के अनुयायिओं को अहिंसात्मक माना जाता है, लेकिन श्रीलंका में सोलोमन भंडारनायके की हत्या एक बौद्ध भिक्षु के हाथों ही हुई.

अपने पूरे क्रिकेट करियर के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दौरान उन्हें अपने प्रशंसकों का अपार प्रेम और स्नेह मिला. वहीं लंबे समय तक अपनी जादुई आवाज़ से जीवन भर लोगों का मनोरंजन करने वाले मन्ना डे भी नहीं रहे. मैंने उन्हें पहली बार छह वर्ष की उम्र में सुना था. विजय भट्ट की क्लासिकल फिल्म राम राज्य में गई तू गई नामक गाना उस दृश्य पर फिल्माया गया था, जिसमें सीता ने भू–समाधि ली थी. मन्ना डे को याद करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और यहां तक कि वे भी उन्हें याद करेंगे, जो उनसे कभी नहीं मिले.

हाल ही में राहुल गांधी ने अपने उस भय की चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें डर लगता है कि उन्हें भी मारा जा सकता है. जैसा कि पहले भी उनके परिवार के लोगों को मारा जा चुका है. उन्होंने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान यह याद दिलाई कि किस तरह उनके पिता और दादी की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद उन्होंने भाजपा पर नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन इस दौरान उन्हें यह बात साफ़ करनी चाहिए थी कि उनके पिता और दादी की मौत किसी केसरियाधारी या जेहादी द्वारा नहीं की गई थी. उनके पिता राजीव गांधी की हत्या लिट्टे आतंकियों ने की थी, जो

हिन्दू थे, लेकिन उनका हिंदुत्व से कोई लेना–देना नहीं था. श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह सिंघला समुदाय ही है, जिसने सिंघली को राजकीय भाषा बनाकर और बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर एक बहुसंख्यकवाद शासन थोपने की कोशिश की. लिट्टे इसके ख़िलाफ़ था. शायद वह तमिलवाद पर ज़ोर दे रहे थे. राहुल की दादी इंदिरा गांधी की हत्या खालिस्तान समर्थकों ने की थी. उनका भी कोई संबंध भारत के किसी भी प्रकार के राष्ट्रवाद की धारा से नहीं था, चाहे धर्मनिरपेक्ष हो या हिंदू.

भारत में जितने भी राजनेताओं की हत्याएं हुई हैं, सभी के पीछे कोई न कोई कारण था. ऐसा सिर्फ़ भारत में ही नहीं है, वरन पूरा दक्षिण एशिया राजनीतिक हिंसा से चपेट में रहा है. आमतौर पर बौद्ध धर्म के अनुयायिओं को अहिंसात्मक माना जाता है. लेकिन श्रीलंका में सोलोमन भंडारनायके की हत्या एक बौद्ध भिक्षु के हाथों ही हुई. श्रीलंका ने ख़ुद को बौद्ध राष्ट्र तो घोषित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वह दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त देशों में से एक है. राष्ट्रपति रानासिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी गई और राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंग ने एक चुनावी रैली के दौरान हुए हमले में अपनी एक आंख गंवा दी, वहीं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली ख़ान की भी हत्या हुई और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, जबकि उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई. बांग्लादेश अपने संस्थापक मुजीबुर्रहमान की हत्या का गवाह बना.

राजनीति लोगों को अलग करती है, जबकि खेल और सिनेमा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्रिकेट में देखने को मिलता है, जहां दोनों देशों के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद यह जनता को आपस में जोड़ता है. ठीक उसी तरीक़े से, जैसे नुसरत फतेह अली खान की गायकी दोनों देशों को जोड़ती है, बिल्कुल वैसा ही काम पाकीज़ा और मुगले–आज़म जैसी फिल्में करती हैं. जयललिता भले ही श्रीलंकाई खिलाड़ियों के खेलने पर आपत्ति जताती हों, बावजूद इसके भारतीय प्रशंसकों को उन्हें खेलते देखना पसंद है.

मेरे हिसाब से दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता का कारण इन देशों में राष्ट्रवाद के कमज़ोर होने का सिद्धांत है. दक्षिण एशिया के चार देशों का अस्तित्व एक तरह से प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इतिहास की दुर्घटनाएं हैं. ये सभी पश्चिमी संबंधों के नतीजे हैं, जिसकी शुरुआत वास्को डिगामा ने की थी. राष्ट्रों की स्थापना पहली बार यूरोप में की गई थी और इन्हें सीमाओं, भाषा और जातीयता के आधार पर बांटा गया था. ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोग ख़ुद को दुनिया में सबसे पुरातन बताते हैं, लेकिन इन दोनों देशों की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही हो पाई. उसी प्रकार मध्यपूर्व के सभी देश किसी समय ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे. यही स्थिति दक्षिण एशियाई देशों की भी है. ये सभी कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं. हालांकि, सभी अपने पुराने इतिहास का दावा करते हैं.

भारत एक सूत्र में इसलिए बंध पाया, क्योंकि इस पर एक यूरोपीय महाशक्ति (ब्रिटेन) ने कई अन्य महाशक्तियों पर विजय पाई, जो न सिर्फ़ भारत की धरती पर लड़ रहे थे, बल्कि बाहर भी युद्ध लड़ रहे थे. वरना भारत भी आसानी से पुर्तगाली, फ्रेंच, डैनिश, इंग्लिश सीमाओं में बंट जाता. आज़ादी के बाद भारत दो भागों में बंट गया. बाद में पाकिस्तान भी बंट गया और बांग्लादेश बना. श्रीलंका भी डच, पुर्तगाली और इंग्लिश सीमाओं में बंट जाता अगर अंग्रेजों ने दूसरे देशों को हरा न दिया होता. यह अविभाजित रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने दूसरों को हरा दिया.

यही कारण है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में राष्ट्र को लेकर प्रतिद्वंद्व चलता रहता है. इनमें बांग्लादेश अपवाद है. इन सभी देशों में कोई एक भाषा नहीं है और न ही एक धर्म, जो इन्हें जोड़कर रख सके. यहां तक कि धर्मों में भी एक दूसरे से लेकर लड़ाई चल रही है. राष्ट्रवाद पर परस्पर विरोधी सिद्धांतों और धर्म या मतों के बीच विभेद दूर करने की बातें राजनीति को बुरा बनाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

निर्माण कार्यों का निरीक्षण आपका अधिकार है

चौथी दुनिया ब्यूरो

कई बार आपको मांगी गई सूचना के बदले ग़ैर ज़रूरी सूचना थमा दी जाती है या फिर आपके मोहल्ले या शहर की सड़क बनने के एक महीने के भीतर ही टूट जाती है. फिर सालों तक उसकी मरम्मत नहीं होती. आख़िर सरकार ने तो पूरा पैसा दिया था, तब इतनी घटिया सड़क क्यों बनी? सड़कें निर्धारित मापदंड के अनुसार क्यों नहीं बनीं? सड़कों की चौड़ाई निर्धारित सीमा से कम क्यों हो जाती है? मस्टर रोल में भी फर्जी इंट्री की शिक़ायतें आम हैं. सड़क बनाने के काम पर अक्षम और गांव में न रहने वाले लोगों की एंट्री भी मस्टर रोल में दिखा दी जाती है. आख़िर इन सब का उपाय क्या है? सूचना क़ानून में ऐसी समस्याओं का समाधान है. इसके तहत कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइलों या किसी भी विभाग द्वारा कराए गए कामों का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए आपके क्षेत्र में यदि कोई सड़क बनाई गई है और आप सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री या सड़क की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो आप निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं. आप सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं. कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग से सूचना मांगते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अमुक सूचना हज़ार पृष्ठों की है और इसके लिए आपको एक खास शुल्क अदा करनी होगी. कुछ मामलों में तो आवेदक से लाखों रुपये तक की मांग की गई है. ज़ाहिर है, एक ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते आप यह ज़रूर जानना चाहते होंगे कि इन स्थितियों का मुक़ाबला कैसे किया जाए? आरटीआई एक्ट की धारा 2(जे)(1) के तहत आप किसी भी सरकारी काम या फाइल के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं. इस अंक में हम इसी से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी समस्या के समाधान या सुझाव के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

कार्यों का निरीक्षण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

कृपया मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दी जाए:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-2(जे)(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार है. इसके तहत मैं निम्नलिखित कार्य का निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे तिथि, समय एवं स्थान बताएं, जबकि मैं आकर इस कार्य की जांच कर सकूं. (कार्य का विवरण)

2. मैं निरीक्षण के दौरान इस कार्य से संबंधित दस्तावेजों का भी निरीक्षण करना चाहूंगा, इसलिए निरीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराएं:

क. मेज़रमेंट बुक

ख. खर्चों का विवरण

ग. रेखाचित्र

इन दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी तो कानून के तहत

निर्धारित शुल्क लेकर प्रतियां उपलब्ध कराएं.

3. धारा-2(जे)(3) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्यों में प्रयोग की गई सामग्री का प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार है. इसके तहत मैं उपरोक्त कार्य में प्रयोग की गई सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूं. नमूना मेरी उपस्थिति में विभाग द्वारा एकत्र किया जाए और सीलबंद हो तथा विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि सीलबंद नमूना कार्य की सामग्री का असली नमूना है. कृपया मुझे स्थान, समय एवं तिथि सूचित करें, जबकि

मैं प्रमाणित नमूने के लिए आ सकूं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा

6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत

हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का

नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उतर-चढ़ाव वाला रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी. घर में बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. संपत्ति खरीदने संबंधी सकारात्मक निर्णय लेगे. आपको लाभ होगा और आत्मबल बढेगा. परिवार में मांगलिक कार्य होने के संकेत है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह जमीन-जायदाद या वाहन खरीदने का प्रबल योग है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत से सफलता प्राप्त होगी. भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. आप कोई निर्णय स्वयं करें और किसी से प्रभावित होकर जल्दबाजी में कोई कार्य न करें. आर्थिक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला समय रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह लाभ का प्रबल योग है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. नौकरीपेशा वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी. आप अपने नजरियां में बदलाव लाएं. पहले से लंबित पड़ा कार्य पूर्ण होगा. परिवार का सहयोग प्राप्त होगा. मन में उत्साह रहेगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी, जिसेक कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. यात्रा पर अचानक जाने से बचें. आपका स्वभाव प्रेमपूर्ण होगा, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ेगी. आपके सफलता का मूलमंत्र मेहनत होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह पूरानी वस्तुओं को न बेचें. पूर्व से चले आ रहे कानूनी लड़ाई में सफलता मिलेगी. आप आपसी रिश्तों को निखारेंगे. आपको मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. मुश्किल कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह आप आवश्यकता के अनुसार अपने कार्य में बदलाव लाएंगे. आप कम से कम समय में अधिक लाभ कमाने चाहेंगे. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विरोधी प्रभावी रहेंगे, लेकिन आप संयम से कार्य करें. आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और संतान सुख में बढ़ोत्तरी होगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आपको सोच से ज्यादा लाभ मिलेगा. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. नौकरीपेशा वालें लोग चिंतित रहेंगे, लेकिन व्यापारियों में उत्साह रहेगा. लाभ से ज्यादा खर्च होगा और मन विचलित रहेगा. परिवार का कोई सदस्य आपके विपरीत कार्य करेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह आप अपने माता पिता का सेवा करना न भूलें और आपको उनका पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा. व्यापारियों और नौकरीपेशा वाले लोगों में उमंग रहेगा. विशेष व्यक्ति और अधिकारियों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. परिवारिक उलझनों से बचें. आपके पराक्रम में बृद्धि होगी. नए लोगों के आगमन से खर्च में बृद्धि होगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह अचानक यात्रा होगी, जिससे आपको फायदा होगा. परिवार में मांगलिक कार्य के कारण खर्चों में बृद्धि होगी. कानूनी दस्तावेजों पर दस्तखत करने से पहले उसकी जांच कर ले. कोई विदेशी व्यक्ति मददगार साबित होगा. शारीरिक कष्ट थोड़ा बढ़ेगा और आप आलस्य महसूस करेंगे. माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह आप अपने संपत्ति से सम्बंधित दस्तावेजों को संभाल कर रखे. आप अपने उपलब्धियों के तरफ ज्यादा ध्यान न दें. आप धन की अहमियत को समझेंगे. आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा में बृद्धि होगी. आप मन से कार्य करेंगे. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, जिससे आपको तकात मिलेगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह पारिवारिक कलह से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बाहर और मसालेदार भोजन से बचें. दांपत्य जीवन में प्रेमपूर्वक रहे, तनाव से बचें. आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देंगे. किए गए कार्यों के गुणवत्ता पर ध्यान दें. व्यवसायी नए कार्यों की योजना बनाएंगे

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह व्यावसायिक दृष्टि से समय अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा वोले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. अधिक कार्य के कारण थकान महसूस करेंगे. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और विपरीत परिस्थितियों को भी आप अपने पक्ष में मोड़ लेंगे. आप अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे.आपके साथ नए लोग जुड़ेंगे.

ज़रा हट के

कुत्ते ने हासिल की एमबीए की डिग्री

हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइवेट कंपनियों में एमबीए होल्डर कुत्तों की मांग आने लगे. कुत्ते की जितनी बड़ी डिग्री, उतनी ज्यादा कुत्ते की कीमत, पर कुत्ता एमबीए कैसे कर सकता है? क्या ऐसा संभव है? प्रतियोगिता का जमाना है. कुछ भी हो सकता है. बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर देखे होंगे, डॉक्टर-इंजीनियर देखे होंगे, एमबीए होल्डर देखे होंगे, लेकिन किसी जानवर को एमबीए की क्लास में बैठा नहीं देखा होगा. एमबीए की क्लास छोड़िए, किसी भी क्लास में कोई जानवर आकर बैठ जाए तो शायद आप डरकर भाग ही जाएं. अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने आश्चर्यजनक रूप से एक कुत्ते को एमबीए की डिग्री दी है. डिग्री का आधार कुत्ते का 15 साल का कार्य का अनुभव है. दरअसल, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन द्वारा बहुत दिनों से दूरस्थ शिक्षा में फर्जी डिग्री दिए जाने की बात हो रही थी. इसी को साबित करने के लिए एक न्यूज हाउस ने एक कुत्ते की डिग्री के लिए आवेदन कर दिया. आवेदन में ऐसी कोई जानकारी मांगी नहीं गई थी, जिससे कुत्ते की पहचान उजागर होती. काम करने का अनुभव और नाम की जगह कुत्ते का नाम पेटे बताया गया और कार्य का अनुभव 15 साल. इसके साथ 7 हजार 278 डॉलर की बड़ी रकम फीस के रूप में जमा कराई गई. बस विश्वविद्यालय ने बिना सत्यापन या किसी और जानकारी के डिग्री उपलब्ध करा दी. आज यह खबर सुर्खियों में है. कुछ भी हो, यह भाग्यशाली कुत्ता दुनिया का पहला कुत्ता होगा, जिसे एमबीए होने का गौरव मिला है. ■

दबे सोने का राज बताती पत्तियां

भारत में एक संत के कहने पर कि उसने सपने में जमीन में दबा सोना देखा है. संत के सपने के आधार पर जमीन में दबे सोने की खोज होने लगती है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ पेड़ों की पत्तियां जमीन में दबे खजाने के बारे में बता रही हैं. ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में कालगूर्ली क्षेत्र में युकेलिप्टस के कुछ ऐसे पेड़ हैं, जिनकी पत्तियों में अत्यंत बारीक सोने के कण पाए गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार पत्र द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन के खबर अनुसार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के काल-गूर्ली क्षेत्र में यूकेलिप्टस की पत्तियां जमीन के भीतर दबे सोने का पता बताती हैं. समाचार पत्र के अनुसार, इस क्षेत्र में जमीन के नीचे दबे सोने के कण पेड़ों के जड़ों के जरिये पत्तियों और अन्य हिस्सों तक पहुंचता है. सीएसआईआरओ के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया और इससे संबंधित शोध पत्र विज्ञान शोध पत्रिका नेचर कम्यूनिकेशंस के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है. शोध पत्र में मुख्य शोधकर्ता और रसायनविद मेल लिंटर ने कहा है कि सुनहरी पत्तियों से जमीन के नीचे सोने के अमूल्य खजाने का पता लग सकता है. लिंटन ने आगे कहा है कि इनमें से कुछ वृक्षों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक गई हुई हैं और हमारे लिए जमीन के भीतर दबे खजाने के लिए खिड़की की तरह काम करती हैं. समाचार पत्र के अनुसार, इस शोध के बाद पारंपरिक तरीके से ड्रीलिंग द्वारा जमीन के अंदर सोने का पता लगाने की बजाय पत्तियों के परीक्षण द्वारा यह कार्य काफी किफायती हो जाएगा. इस तकनीक से सोने के अलावा जमीन में दबे अन्य धातुओं का भी पता लगाया जा सकता है. ■

फेंक दिए तीन करोड़

एक आदमी ने तीन करोड़ से ज्यादा कीमत के गोल्ड इन्वेस्टमेंट कागजात को इसलिए कूड़े में फेंक दिया कि उसको अपनी पत्नी को तलाक के बाद उसमें हिस्सा न देना पड़े. कोलोराडो का रहने वाला 50 साल का अर्ल रे जोन्स ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि वह इन दस्तावेजों को कोलोराडो स्प्रिंग्स मोटल के पीछे कूड़े में फेंक आया है. जोन्स ने कहा कि वह नहीं चाहता था कि तलाक के बाद उसकी 25 साल की पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिले. हालांकि उसके गोल्ड इन्वेस्टमेंट दस्तावेज फेंकने के कोई पक्के सबूत नहीं मिले. जोन्स पूर्व डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता था. वह इस समय टेलर कोर्ट जेल में है. उसे अपनी पत्नी से मारपीट करने और उसके सामान पर कब्जा करने के लिए सजा हुई थी. इसके बाद पत्नी ने अदालत में तलाक की अर्जी दी थी. दोषी ठहराए जाने के बाद जोन्स को नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी. कूड़े को निपटाने का प्रबंधन करने वाली कंपनी का कहना है कि तीस हजार टन कूड़ा हर महीने फेंका जाता है. अगर जोन्स की पत्नी के गोल्ड के शेयर इस कचरे में मिलते हैं तो वो उन्हीं के होंगे. ■

मज़ार की देखभाल हिंदू करते हैं

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सांप्रदायिक सौहार्द का एख अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है. यहां जलाउद्दीन बगदाद वाले बाबा की मज़ार है जिसकी पूरी देख-रेख यहां के लिए बनी हिन्दुओं की समिति करती है. पिनकापार गांव में एकमात्र मुस्लिम परिवार रहता है और वह भी हिन्दुओं की इस धार्मिक आस्था से प्रसन्न है. गांव में बनी मज़ार की पिछले 100 वर्ष से यहां के हिन्दू पूरी शिद्दत से देखभाल करते आ रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई है, जो मज़ार को सुरक्षित रखने के लिए पहले अस्थाई शेड बनाना चाहती है, इसलिए गांववालों से धन संग्रह किया जा रहा है. यहां की आबादी करीब 450 परिवारों की है, जिसमें मुस्लिम परिवार सिर्फ एक है. शुरुआत में परकोटे का निर्माण दाऊ शशि देशमुख ने कराया और प्रत्येक शुक्रवार को 20 से अधिक हिन्दू परिवार मज़ार पर अगरबत्ती व धूप से इबादत करते हैं. बुजुर्गों का कहना है कि वर्ष 1890 में यहां करीब 70 मुस्लिम परिवार रहते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही सत्तार खां का परिवार रहता है. बताया गया कि एक दशक पहले हिंदुओं के सहयोग से महबूब खां ताजिया निकाला करते थे और जब से उनकी मृत्यु हुई, ताजिया निकलने बंद हो गए हैं.पिनकापार से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम जेवरतला है. यहां के निवासी धनराज ढोबरे (मराठा) पिछले 26 साल से प्रत्येक शुक्रवार इस मज़ार पर आ रहे हैं. ढोबरे कहते हैं कि यहां आने पर उन्हें सुकून मिलता है. इसी तरह से 20 साल से इतवारी रजक भी मज़ार पर आ रहे हैं. रजक ने अपने होटल में मज़ार के विस्तार के लिए दानपात्र रखा है. अब तो यहां आसपास के गांवों से भी हिन्दू इबादत के लिए पहुंचने लगे हैं. ■

कुछ साल पहले गोपनीय सूचनाएं लीक कर अमेरिका की चूलें हिला देने वाले जूलियन असांजे ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि इंटरनेट पूरी दुनिया पर सर्विलांस की तरह काम करता है. उनकी बात अब चरितार्थ होते दिख रही है. अमेरिका की इस हालिया जासूसी के बारे में जानकारी देने वाले पूर्व सीआइएकर्मी एडवर्ड स्नोडेन वर्तमान समय में रूस की शरण में हैं और देश के द्वारा की जाने वाली जासूसी की हरकतों का खुलासा कर रहे हैं.

संचारतंत्र के मायाजाल में फंसती दुनिया

अमेरिकी जासूसी की सभी नेता यह कहते हुए निंदा कर रहे हैं कि यह निजता का हनन है. दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. दो बातें सामने आ रहीं हैं. पहली कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को इन नेताओं फोन टैपिंग के बारे में जानकारी थी. दूसरा यह कि अमेरिकी अधिकारी लगातार इस बात से इन्कार कर रहे हैं कि इन सभी नेताओं की जासूसी देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी में हो रही थी.

अरुण तिवारी

अमेरिका द्वारा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और अन्य नेताओं की फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अमेरिकी जासूसी की सभी नेता यह कहते हुए निंदा कर रहे हैं कि यह निजता का हनन है. दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. दो बातें सामने आ रहीं हैं. पहली कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को इन नेताओं के फोन टैपिंग के बारे में जानकारी थी. दूसरा यह कि अमेरिका लगातार इस बात से इन्कार कर रहा है कि यह सबकुछ राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी में हो रहा था.

कुछ साल पहले गोपनीय सूचनाएं लीक कर अमेरिका की चूलें हिला देने वाले जूलियन असांजे ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि इंटरनेट पूरी दुनिया पर सर्विलांस की तरह काम करता है. उनकी बात अब चरितार्थ होते दिख रही है. अमेरिका की इस हालिया जासूसी के बारे में जानकारी देने वाले पूर्व सीआइएकर्मी एडवर्ड स्नोडेन वर्तमान समय में रूस की शरण में हैं और देश के द्वारा की जाने वाली जासूसी की हरकतों का ख़ुलासा कर रहे हैं. यहीं नहीं इससे पहले भी इसी तरह की एक बड़ी घटना में मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक को भी अपना अख़बार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड कई नेताओं की फोन टेपिंग के आरोपों के बाद हुई छीछालेदर के कारण बंद करना पड़ा था.

बात सिर्फ़ किसी बड़े नेता या किसी रसूखदार व्यक्ति की जासूसी की नहीं है. अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हमारे किसी जानने वाले का या नज़दीकी व्यक्ति का सोशल साइट अकाउंट हैक हो गया. कई अटपटी सामग्री उसकी साइट के ज़रिए पोस्ट कर दी जाती हैं. ऐसी स्थिति सोशल साइट को संचालित करने वाली कंपनी के द्वारा पासवर्ड बदलने की सुविधा तो मुहैया कराई जाती है, लेकिन अकाउंट हैक होने पर उसकी निजता का जो हनन होता है उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती. हालांकि, इसके लिए क़ानून है लेकिन ज्यादातर लोगों इन क़ानूनों की जानकारी न होने की वजह से परेशानी का ही सामना करना पड़ता है. जीमेल, याहू जैसी ही अन्य सेवाएं मेल करने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं. इन सेवाओं का प्रयोग करने वाले अपनी अत्यधिक ज़रूरी सूचनाएं इनमें संकलित करते हैं. ऐसे में हैकर्स के हाथ में पड़ने पर इस सामग्री का कैसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

कुछ समय पहले तक इंटरनेट की जो दुनिया बहुत खुली और भयरहित नज़र आती थी, अचानक डरावनी लगने लगी है. इंटरनेट पर काम करने वालों को जब पता चलेगा कि उनकी हर गतिविधि पर कोई आंखें गड़ाए है तो वे पहले की तरह बेख़ौफ़ नहीं रह पाएंगे. उनकी निश्चिंतता तब ख़त्म हो जाएगी जब उन्हें एहसास होगा कि सबसे शक्तिशाली मुल्क की कुख्यात ख़ुफ़िया एजेंसियां उनकी हर गतिविधि के नए अर्थ खोज रही हैं और कभी भी अर्थ का अनर्थ कर सकती हैं.

दरक रहा है इस्तेमाल करने वालों का विश्वास

इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों का विश्वास अब इससे दरक रहा है. उन्हें इस बात का यकीन था कि उनकी निजी अकाउंट में कोई दख़ल नहीं देगा और न ही निगरानी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. इसका कारण है कि दुनियाभर में अपनी ताक़त का लोहा मनवा चुका अमेरिका वैश्विक स्तर पर उनकी निगरानी में लगा हुआ है. संवादों, विचारों या संदेशों के आदान-प्रदान की छानबीन कर रहा है. एडवर्ड स्नोडेन ने बाक़ायदा प्रमाण देकर बताया है कि नेशनल सेक्युरिटी एजेंसी और सीआईए प्रिज्म नाम से फोन और इंटरनेट पर निगरानी का विश्वव्यापी अभियान चला रहे हैं. द वॉशिंगटन पोस्ट एवं द गार्जियन ने स्नोडेन द्वारा दी गई जानकारियों को प्रकाशित किया है.

सोशल साइट्स पर अमेरिकी निगाह

एक अख़बार के मुताबिक अमेरिका की जिन देशों से सूचनाएं जुटाता है उनमें सबसे पहली श्रेणी में भारत भी शामिल है. अख़बार के मुताबिक उसे यह सूचनाएं एनएसए के पूर्व ख़ुफ़िया अधिकारी एडवर्ड स्नोडेन ने दी है. अख़बार के अनुसार एनएसए ने भारत की इंटरनेट और फोन नेटवर्कों से 30 दिनों में अरबों की तादाद में छोटी-बड़ी जानकारियां जुटाई. आप किससे, कितनी देर तक और कितनी बार फोन करते हैं, या किसे ईमेल भेजते हैं और किस वेबसाइट पर जाते हैं-दुनिया भर से गुप्त तौर पर इस तरह की जानकारियां इकठ्ठा करने का आरोप अमेरिकी एजेंसियों पर लगा है. ख़ुद अमेरिका के नागरिकों ने बड़ी संख्या में इसे निजता का हनन माना और अभियान का विरोध किया, लेकिन अमेरिकी सरकार इसे सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताती है. इस मामले पर साइबर क़ानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल कहना है कि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक डाटा का काफ़ी महत्व है. ये डाटा प्रत्येक राष्ट्र के लिए बड़ा महत्व रखते हैं, इसलिए जानकारियां जुटाई जाती हैं. कोशिश की जाती है कि जनसंख्या इंटरनेट पर क्या जानकारी भेज रही है, या क्या कर रही है, उसकी पूरी जानकारी रखी जाए.

जासूसी पर रक्षात्मक अमेरिका

फोन टैपिंग के मामलों और इंटरनेट पर सूचनाओं की जासूसी ने अमेरिका जैसे ताक़तवर देश को भी रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है. जबकि इस रहस्योद्घाटन ने अमेरिकियों को और साथ ही अमेरिका के मित्र देशों को भी नाराज कर दिया है क्योंकि अमेरिकी प्रशासन उनकी भी ख़ुफ़ियागिरी कर रहा था. स्नोडेन ने जानकारियां लीक कर विश्व में अमेरिकी साख़ को न सिर्फ़ बट्टा लगाया है बल्कि उसे रक्षात्मक होने पर मजबूर भी कर दिया है. स्नोडेन अपने काम को ग़लत नहीं मानते, इस वजह से उन्हें इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है. इसके उलट अमेरिकी सरकार स्नोडेन के इस काम के लिए उनके पीछे पड़ी हुई है. स्नोडेन द्वारा किए गए इस भंडाफोड़ को वाटरगेट कांड और वियतनाम युद्ध में अमेरिकी कारगुजारियां जगज़ाहिर करने वाले पेंटागन पेपर्स के लीक होने से भी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है.

इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) गोपनीय जानकारियां इकट्ठा करने के लिए गूगल और याहू के डाटा केंद्रों को भी नहीं छोड़ती. अख़बार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व सीआइए कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के हवाले से बताया कि इन दोनों इंटरनेट कंपनियों के नेटवर्कों से लाखों रिकार्ड प्रतिदिन चोरी किए जाते थे. रिपोर्ट के अनुसार एनएसए सर्वर को हैक करने के स्थान पर गोपनीय जानकारियां उसी समय हासिल कर लेता है जब वो डाटा के रूप में ऑप्टिकल फाइबर केबल के ज़रिए किसी नेटवर्क डिवाइस से सर्वर तक यात्रा कर रही होती हैं. एजेंसी ने जो जानकारियां जुटाई थीं उसमें मेटा डाटा से लेकर टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो तक शामिल थे, जिसे बाद में एनएसए के प्रोग्राम मसक्यूलर से प्रोसेस किया गया.

एडवर्ड स्नोडेन के इस ख़ुलासे के बाद गूगल के मुख्य क़ानूनी अधिकारी डेविड ड्रमंड ने कहा कि हमारे निजी फाइबर नेटवर्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इससे हममें निराशा भी है और नाराज़गी भी. इस तरह की कार्रवाइयों में तत्काल सुधार की ज़रूरत है. इसके अलावा गूगल ने इस तरह के किसी किसी कार्यक्रम की जानकारी होने से भी इन्कार किया. वहीं दूसरी तरफ अख़बार वाशिंगटन पोस्ट द्वारा ख़ुलासा किए जाने के बाद एनएसए के प्रवक्ता ने बयान जारी कर अख़बार की रिपोर्ट को झूठ क़रार दिया. बयान में कहा गया कि इस प्रकार से बड़ी संख्या में अमेरिकियों के डाटा इकट्ठा करने का दावा पूरी तरह झूठ पर आधारित है.

संयुक्त राष्ट्र की संचार व्यवस्था पर नज़र नहीं रखेगा अमेरिका

एनएसए की हालिया हरकत से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में नाराज़गी झेलने के बाद देश ने इस बात का फ़ैसला किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र की संचार व्यवस्था की निगरानी नहीं करेगा. ख़ुफ़िया निगरानी के तरीक़े को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय काफी गुस्सा है जिसे लेकर ऐसा फैसला किया गया है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के प्रवक्ता मार्टिन नेर्सिकी ने इस मामले में कहा है कि हम अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं. उन्होंने ने हमें इस बात का भरोसा दिलाया है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा नहीं किया जाएगा. ■

क्या है हैकिंग?

अपने घर में बैठे हुए ही दुनिया के किसी कोने में स्थित किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने वाले और उससे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से निकालने वालों को हैकर्स कहते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि हैकिंग के लिए बाज़ार में तमाम सॉफ्टवेयर मौजूद हैं लेकिन इसपर रोक लगाने का कोई तरीक़ा अभी तक नहीं बना है. लंबे समय तक उनके शैतानी कारनामों को बचपना बताकर ख़ारिज कर दिया जाता था. लेकिन अब हैकर्स का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया के हर कोने में मौजूद है. इनका मक़सद पैसा कमाना हो गया है. इनके निशाने पर छोटी-मोटी साइटें नहीं, बल्कि प्रतिष्ठित, विश्वसनीय और बड़ी वेबसाइटें होती हैं, जहां लोग नियमित तौर पर अपने वेब ब्राउजर के ज़रिए विजिट करते हैं. ये बिक्री और वितरण से जुड़ी वेबसाइटों को ख़ास तौर पर निशाना बनाते हैं. एक आंकड़े के मुताबिक साल पहले छह महीनों में गलत तरीके से साइट हैक करने की दो लाख बारह हज़ार मामलों की शिनाख्त की गई. इसमें प्रति इंटरनेट उपभोक्ता के ये मामले सबसे ज्यादा इजराइल में देखने को मिले.

feedback@chauthiduniya.com

साई

अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए. साई बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, तुम पूजन और कांकड़ आरती करो. लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे. इस दृष्टांत के बाद वे वहां आए और ज्यों ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए.

एक बार...

साई का स्मरण करो

चौथी दुनिया ब्यूरो

हिंदू धर्म में जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आ जाती है तो उसे धार्मिक ग्रन्थ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है कि मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके. राजा परीक्षित को एक ऋषिपुत्र ने शाप दिया और एक सप्ताह के पश्चात ही उनकी मृत्यु निकट आ गई. महात्मा शुकदेव ने उन्हें श्रीमद्भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई. महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रन्थों का पाठ किया जाता है. साई बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की. जब उन्हें विदित हो गया कि वह अब शीघ्र इस नश्वर देह को त्याग देगें, तब उन्होंने वक्षे को रामकथा का आठों पहर पाठ करने की आज्ञा दी. वक्षे ने उस अध्याय की द्वितीय आवृति तीन दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए. जब वक्षे थक गए तो उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई. साई बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए. दो–तीन पूर्व ही साई भिक्षा मांगना बंद कर दिए और वे मस्जिद में ही बैठे रहते थे. साई अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय नहीं बताया. इन दिनों काकासाहेब दीक्षित और बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोज करते थे. महानिर्वाण के दिन (15 अक्टूबर को) आरती समाप्त होने के बाद बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा. फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण बाला शिम्पी और नानासाहेब निमोणकर वहीं रह गए. लक्ष्मीबाई शिन्दे को 9 रुपये देने के बाद बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी के पत्थर वाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा. ये ही अंतिम शब्द साई के मुख से निकले. इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी. भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नानासाहेब निमोणकर को पुकार कर यह बात कही.

शिरडी के सब नर-नारी और बालक गण मस्जिद की ओर दौड़े. चारों ओर हाहाकार मच गया. सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ. प्रत्येक की आंखों से आंसू गिर रहे थे. उनके इस महान दुःख में कौन आकर उन्हें सांत्वना देता, जबकि उन्होंने साक्षात् परब्रह्म को खो दिया था. अब कुछ भक्तों को साई बाबा के वचन याद आने लगे. किसी ने कहा कि महाराज (साई बाबा) ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे आठ वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे. ये एक सन्त के वचन हैं और इसलिए किसी को भी इन पर सन्देह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्णावतार में भी चक्रपाणि (भगवान विष्णु) ने ऐसी ही लीला की थी.

नानासाहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के मुख में डाला, जो बाहर निकल आया. तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई. अरे देवा. तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े, जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो. अब स्पष्ट हो गया कि साई ने सचमुच ही शरीर त्याग दिया है.

शिरडी के सब नर–नारी और बालक गण मस्जिद की ओर दौड़े. चारों ओर हाहाकार मच गया सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ. प्रत्येक की आंखों से आंसू गिर रहे थे. उनके इस महान दुःख में कौन आकर उन्हें सांत्वना देता, जबकि उन्होंने साक्षात परब्रह्म को खो दिया था. अब कुछ भक्तों को साई बाबा के वचन याद आने लगे. किसी ने कहा कि महाराज (साई बाबा) ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे आठ वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे. ये एक सन्त के वचन है और इसलिए किसी को भी इन पर सन्देह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्णावतार में भी चक्रपाणि (भगवान विष्णु) ने ऐसी ही लीला की थी . श्रीकृष्ण माता देवकी के सामने आठ वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रगट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था. साई बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था. ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम–संबंध विकसित करके साईबाबा दौरे पर चले गए और भक्तों को दृढ़ विश्वास था कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे.

अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए. साई बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, तुम पूजन और कांकड़ आरती करो. लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे. वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते, उसके बाद ग्राम देवियों और देवताओं का. उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के बाद वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और ज्यों ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए. स्वप्न की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया. फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ भी चिंता न कर विधिवत पूजन और कांकड़ आरती की. बाबा के अंतिम वचनों को आदरपूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटी वाड़े में ही रखने का निश्चय किया और सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. दूसरे दिन प्रातःकाल बम्बई से अमीर भाई और कोपरगांव से मामलेदार भी वहां आ पहुंचे. उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं हैं. तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत वाड़े के पक्ष में ही है. फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे. साई बाबा की प्रेरणा से विरोधियों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन सबने मिलकर अपना मत भी वाड़े के ही पक्ष में दिया. उस संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में लाया गया और विधिपूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई, जहां कृष्ण की मूर्ति स्तापित होनी थी. सच तो यह है कि बाबा कृष्ण बन गए और वाड़ा समाधि–मंदिर तथा भक्तों का एक पवित्र देवस्थान, जहां अनेक भक्त आया–जाया करते थे और अभी भी नित्य–प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

ध्यान द्वारा सत्य का अनुभव

डॉ. अभय बंग

परिस्थिति का इलाज प्राणायाम में सांस लेने (पूरक) तथा छोड़ने (रेचक) की अपेक्षा कुम्भक(जब सांस रुकी हुई होती है) का योगाशास्त्र में अधिक महत्व है. इस कुम्भक के भी तीन प्रकार हैं–आंतर्कुम्भक (सांस अंदर लेने के बाद का समय) वाह्य कुम्भक (सांस छोड़ने के बाद का समय) व कैवल्य कुम्भक (अपने आप होने वाला कैवल्य कुम्भक) कैवल्य कुम्भक किया नहीं जा सकता. वह यदि हुआ तो अपने आप ही कभी होगा. बाह्य कुम्भक अभी मैं ठीक तरह से नहीं कर पाता हूं. दम घुटने लगता है, लेकिन आंतर्कुम्भक (सांस अंदर लेकर कुछ समय उसे वहीं रहने देना व स्थिर रहना) सध गया है. कई दिनों से धीरे–धीरे सध रहा था. आज सांस अंदर लेने के बाद आंतर्कुम्भक के कुछ क्षणों के काल में अचानक मन शांत प्रतीत हुआ. मन का आकाश निस्तब्ध, निर्विचार हो गया था. एक पंक्षी पंख पसारकर ऊंचे आकाश में स्थिर होकर तैरे, वैसे ही अस्तित्व की मात्र एक अनुभूति तरंगित हो रही थी. कहीं कोई गड़बड़ी–हड़बड़ी न थी. असीम शांति भर गई थी. प्रत्येक सांस के बांद दस–बारह क्षणों का यह शांति का अनुभव एकदम भिन्न था. कुम्भक का महत्व अब कुछ–कुछ समझ में आ रहा था.

कुम्भक से कुछ क्षणों की शांति मिलती, लेकिन टिकटी नहीं थी. मन में सतत् चमकने वाले विचारों से यह मौन की धारा बारंबार खंडित हो जाती थी. कभी विचार, तो कभी केवल शब्द. हवा के साथ कागज के टुकड़ों जैसे उड़नेवाले शब्द. उनकेमन में सतत् कोलाहल चलता रहता. ये ही मन को शांत नहीं रहने देते, यह बात मेरी समझ में आने लगी. ये विचार, ये शब्द क्यों आते हैं? मुझे दिखाई दिया कि मेरे न बुलाने पर भी, आवश्यकता न होने पर भी, वे स्वयं अपनी गति से आ धमकते हैं. थोड़ी सी भी शांति हुई नहीं कि विचारों के बुलबुले तुरंत ऊपर आ जाते हैं. विचार–असंगत, निरर्थक विचार, थका डालने वाले, त्रस्त कर देने वाले विचार. अनेक बार तो सार्वजनिक लाउडस्पीकर की भांति दो–दो विचार एक साथ आ धमकते. विचारों का शोर ही शोर. मन में यह चक्की सतत् चलती ही रहती. मेरे मन को शब्दों की चक्की पीसने की आदत हो गई थी. मजबूत पक्की आदत.

इन विचारों की वजह से मेरी एकाग्रता भंग होती थी. इतना ही नहीं. मैं उस क्षण के अवधान से ढल जाता था. मैं ध्यान द्वारा सत्य का अनुभव करना चाहता था, लेकिन अनुभव की बजाय ये विचार ही चित्त को व्याप्त कर रहे थे और ये विचार सत्य नहीं थे. सत्य का अनुभव व्यक्त करने के लिए शब्दों के प्रतीकों के बुलबुले किसी ने बनाए थे. ये सत्य के सबस्टीटयूट थे. नकली माल. भस्मासुर की तरह वह मुझ पर उलट पड़े थे. सारे मन को व्याप कर, वे मुझे सत्य के अनुभव से वंचित कर रहे थे. अनुभव को जीने की बजाय उस अनुभव को शब्दों का रूप देने की इतनी ललक मुझे क्यों है? बहुत दिन हुए एक उपन्यास पढ़ा था. उस उपन्यास में एक पात्र कहता है. मेरे अंदर का लेखक क्षणभर के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता. सतत् मेरी गर्दन पर बैठकर मुझे यंत्रणा देता है. यह अनुभव मैं

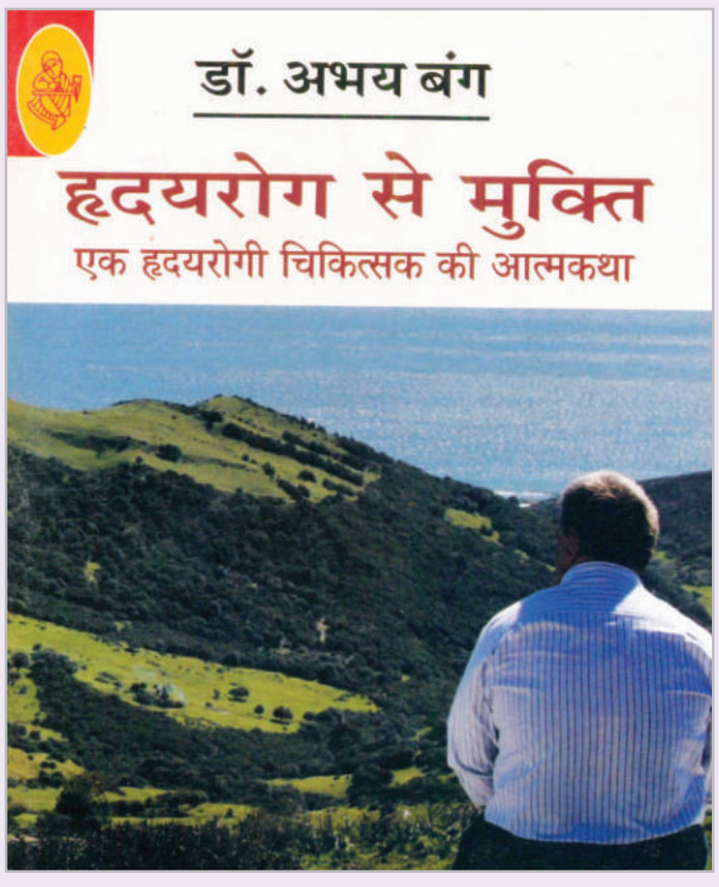

कैसे लिखूंगा? यही विचार मुझे सताता रहता है. मेरा इकलौता लड़का मर गया. उसका शव चिता पर रखकर अग्नि देते समय भी मेरे मन में विचार आया–यह दुख अब मैं किस तरह अभिव्यक्त करूंगा? मैं अपने अंदर झाकने लगा. किसी अन्य की तो बात ही छोड़िए. एंजिओप्लास्टी टेबल पर मौत के मुंह में पहुंचने पर भी उस अनुभव को अणुविसर्जन यह नाम मैंने दे ही दिया था. अब याद आया कि 18 अप्रैल को सीने में दर्द उठने पर शोध ग्राम में स्वयं का ईसीजी जब देख रहा था, तब एक ओर अपने हार्टअटैक की चिंता सता रही थी, लेकिन दूसरी ओर विचार भी चल रहे थे. अपनी भी क्या हालत है, स्वयं का हार्टअटैक स्वयं ही देखना पड़ रहा है. यह तो उस रसियन सर्जन जैसी हालत हो गई. उत्तर ध्रुवीय बर्फीले प्रदेश में अकेला होते हुए अपेंडसायटिस का दौरा पड़ने पर अपनी जान बचाने के लिए एक रसियन सर्जन को खुद अपने पेट का ऑपरेशन आईने में देखकर करना पड़ा था. अपनी हालत उस सर्जन जैसी. मन में वाक्य उठा था. मृत्यु की छाया में भी शब्दांकन की यह आदत पीछा नहीं छोड़ रही थी. अनुभव हुआ नहीं कि तुरंत उसके बाद उठते शब्दों के बुलबुले. हर अनुभव को विचारों के रूप में संगठित करने का पागलपन ही मेरे मन पर सवार था. विचार यह जैसे मेरे मन का कैंसर था. लगातार पीड़ा देने वाला, जीवन रस चूसने वाला परोपजीवी. फिर समझ में आया–अरे मन यानी और कुछ नहीं. ये संबद्ध–असंबद्ध विचारों की सतत् चलने वाली अव्यवस्था–यही मन है. विचार व उसके पीछे उठने वाली प्रतिक्रियाएं, यही मेरा मन है. वह मुझे सतत् व्यस्त रखता है, पीड़ा देता है. यह मेरी अशांति की जड़ है. मुझे मिलने वाले प्रत्येक क्षण को यह मन निगल लेता है. यह क्षण सत्य है, इस क्षण का अनुभव सत्य है, लेकिन मैं उसे कहां जी रहा हूं? मैं तो सतत् उस क्षण के संबंध में उठनेवाली शाब्दिक प्रतिक्रियाओं में जी रहा हूं. जी रहा हूं? कि जीवन व्यर्थ कर रहा हूं? इन विचारों को शांत करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है. ध्यान से ये विचार शांत होंगे क्या? शांत होंगे तो आखिर कैसे?

सच पूछो तो ध्यान बुद्धि का क्षेत्र नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि शांत बैठती ही नहीं थी. ध्यान को वह अपने तरीके से समझने का प्रयत्न कर रही थी. धीरे–धीरे योगशास्त्र एवं आधुनिक मनोविज्ञान की कुछ बातों में समानता नजर आने लगी. एल्बर्ट एलिस नामक विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई रेशनल इमोटिव थैरपी (आर.ई.टी) नामक उपचार–पद्धति के विषय में पढ़ा. इसके अनुसार हमारी भावनाओं एवं मूड्स को आकार देने का मुख्य कार्य हमारे मन के विचार ही करते हैं. ये विचार माने अपने से ही बातचीत अर्थात सेल्फ टॉक होती है. अपना यह सेल्फ टॉक ध्यान से सुना जाए और उसे सही तरीके से बदला जाए तो मन की भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है. बड़ी मजेदार बात है. मन के पेटेंट वाक्य (जैसे–मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता) बोल–बोलकर हम स्वयं ही अपनी भावना गढ़ते रहते हैं. ये वाक्य सुनेंगे तो समझने लगेंगे कि भावनाएं किस प्रकार गढ़ी जाती हैं. वाक्य बदलिए तो भावनाएं भी बदल जाएंगी. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

अंधा बढ़ई

किसी गांव में एक आदमी बढ़ई का काम करता था. ईमानदारी से काम करके वह जितना भी कमाता था, उसमें वह और उसका परिवार गुज़ारा कर लेता था. उसकी पत्नी और बच्चे संतुष्ट रहते थे, पर स्वयं बढ़ई के मन में असंतोष व्याप्त रहता था. वह स्वयं से कहता–मैं बहुत गरीब हूं और अपने परिवार को खुश नहीं रख पाता. अगर मेरे पास कुछ सोना आ जाए तो मैं और मेरा परिवार बहुत सुख से रहेंगे. एक दिन उसने बाज़ार में एक सुनार की दुकान पर बिक्री के लिए रखे गए सोने के जेवर देखे और अचानक ही वह एक जेवर उठाकर भाग गया. दुकानदार यह देखकर चिल्लाने लगा. शोर सुनकर कुछ सिपाही वहां आ पहुंचे और बढ़ई को घेरकर पकड़ लिया. उसे पकड़कर थाने ले गए और जेल में बंद कर दिया. च्वांग–त्ज़ु उसे देखने के लिए गया और उसने उससे पूछा–इतने सारे लोगों के आसपास होते हुए भी तुमने जेवर चुराने का प्रयास क्यों किया? बढ़ई बोला–उस समय मुझे सोने के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. च्वांग–त्ज़ु सुनार के पास गया और उससे बोला–जिस व्यक्ति ने तुम्हारा जेवर चुराया वह स्वभाव से बुरा आदमी नहीं है. उसके लोभ ने उसे अंधा बना दिया और सभी अंधे व्यक्तियों की तरह हमें उसकी भी सहायता करनी चाहिए. मैं चाहता हूं कि तुम उसे जेल से मुक्त करवा दो. सुनार इसके लिए सहमत हो गया. बढ़ई को रिहा कर दिया गया. च्वांग–त्ज़ु एक महीने तक हर दिन उसके पास जाकर उसे जो मिले, उसी में संतुष्ट रहने का ज्ञान देता था.

***शिक्षा :** संतोष ही सबसे बड़ा सुख है.*

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साहित्य

> राजेन्द्र यादव का योगदान है हंस. अस्सी के दशक में जब संस्थागत पूंजी वाली हिंदी की पत्रिकाएं एक–एक कर दम तोड़ रही थीं तो उस वक्त राजेन्द्र यादव ने हंस को पुनर्प्रकाशित करने का जोख़िम उठाया. जोख़िम इस वजह से कि उसके पीछे कोई संगठित पूंजी नहीं थी, थी सिर्फ़ इच्छाशक्ति और मित्रों का साथ. नामवर जी हमेशा कहते हैं कि राजेन्द्र का नाम सिर्फ़ हंस की वजह से ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा.

भाषा महोत्सव

सूना हुआ हिंदी का जीवंत कोना

अनंत विजय

उनतीस अक्टूबर तड़के मॉर्निंग वॉक के लिए जाने को तैयार होकर मोबाइल उठाया तो देखा कि उसमें कई साहित्यक मित्रों के मिस्ड कॉल और मैसेज थे. राजेन्द्र यादव नहीं रहे का एसएमएस पढ़ते ही लगा कि दुनिया थम सी गई. मॉर्निंग वॉक से लौटकर चाय पीते हुए हर दिन तकरीबन साढे सात से आठ बजे के बीच यादव जी से बात होती थी. अस्सलाम आलेकुम के बाद या तो किसी मुद्दे पर बहस होती थी या फिर चंद सेंकेड में फोन रख दिया जाता था. ज्यादातर मैं ही उनको फोन करता था और अगर मैं न कर पाऊं तो वो नाश्ते के बाद सवा आठ साढे आठ बजे फोन कर लेते थे. फोन उठाते ही उधर से आवाजा आती– क्या कर डाला. मैं कहता फिलहाल तो कुछ नहीं तो कहते कर डालो कुछ तो करो यार. साहित्य जगत बहुत ठंडा पड़ा है. कभी नई–नई किताबों पर बात होती या फिर नए विमर्शों पर. मुझे ठीक–ठीक याद नहीं कि यह सिलसिला कब से शुरू हुआ. लेकिन मेरा अनुमान है कि पिछले दस सालों से तो ये बातचीच हो ही रही थी. उनके निधन के पहले वाली शाम यानि अट्ठाइस अक्टूबर को उनसे लंबी बात हुई थी. उन्होंने मुझे इस बात के लिए हड़काया था कि हंस का मेरा स्तंभ उन्हें देर से मिलता है. उनकी शिकायत थी कि मेरी वजह से पत्रिका में काम करनेवालों को देर होती है. उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि पांच से दस तारीख के बीच मैं अपना स्तंभ उनको भेज दिया करूंगा. यह पूरा प्रसंग बताने का मतलब सिर्फ़ इतना था कि यादव जी हमारे जैसे अदने से लेखक का भी न केवल उत्साहवर्धन करते थे, बल्कि लगातार कुछ लिखने के लिए उकसाते रहते थे. अभी पिछले ही हफ्ते अचानक एक दिन उनका फोन आया– अरे यार काफ्का ने अपने पिता को एक ख़त लिखा था. मैंने कहा कि हां बहुत लंबा और बहुत मशहूर ख़त है वो. तो उन्होंने कहा कि ये मुझे फ़ौरन चाहिए. मैंने कहा कि दफ्तर के लिए निकल गया हूं, कल सुबह आपके गेट पर छोड़ दूंगा. हमारे बीच किताबों, लेखों का आदान–प्रदान उनकी सोसाइटी आकाशदर्शन के गेट पर मौजूद गार्ड के माध्यम से ही होता था. मुझे कुछ दोना होता था तो मैं गेट पर लिफाफा छोड़ देता था और उनको कुछ देना होता था तो मेरे नाम का लिफाफा वो अपने गेट पर रखवा देते थे. अभी उनका आखिरी लिफाफे में हंस का नवंबर अंक मिला था. लिफाफे के ऊपर इतने बड़े साइज में मेरा नाम लिखा था कि मैंने मिलते ही उनको फोन किया कि इतने बड़े साइज में क्यों लिखा तो उन्होंने कहा कि छोटा तुम्हें दिखता नहीं तो हंस का अंक गुम हो जाता.

राजेन्द्र यादव से पहली मुलाकात हंस के उनके दफ्तर में 1991 में हुई थी, तब मैं दिल्ली आया ही था. उसके पहले उनसे लंबे–लंबे पत्र व्यवहार हुए थे. पहली मुलाकात में ही वो इस तरह से मिले जैसे सालों से जानते हों. फिर कई मुलाकातें हुईं. जिस संबंध की नींव दरियागंज के हंस के दफ्तर में पड़ी थी वो बाईस सालों के बाद उनके निधन से खत्म हुआ, लेकिन स्मृति में अब भी ताजा रहा करेगा. राजेन्द्र यादव के व्यक्तित्व का अगर मूल्यांकन करें तो उसके चार पड़ाव आपको साफ तौर पर दिखाए देंगे. नई कहानी के दौर के पहले कहानी मनोरंजन के तौर पर (मुझे ठीक से याद नहीं पर शायद नामवर जी ने कहीं ऐसा लिखा है) पढ़ी जाती थी, लेकिन इस दौर के कहानीकारों ने उसे मनोरंजन से मुक्त कर यथार्थ की जमीन पर ला पटका था. और इस काम के अगुवा बने थे मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेन्द्र यादव. इन तीनों ने उस दौर में अपनी काहनियों के माध्यम से कहानी की स्थापित मान्यताओं को छिन्न–भिन्न कर दिया था. उसके बाद राजेन्द्र यादव का योगदान है हंस. अस्सी के दशक में जब संस्थागत पूंजी वाली हिंदी की पत्रिकाएं एक–एक कर दम तोड़ रही थीं तो उस वक्त राजेन्द्र यादव ने हंस को पुनर्प्रकाशित करने का जोखिम उठाया. जोखिम इस वजह से कि उसके पीछे कोई संगठित पूंजी नहीं थी, थी सिर्फ इच्छाशक्ति और मित्रों का साथ. नामवर जी हमेशा कहते हैं कि राजेन्द्र का नाम सिर्फ हंस की वजह से ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. लगातार अट्ठाइस साल तक बगैर किसी बाधा के व्यक्तिगत प्रयासों से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसी चमत्कार से कम नहीं है. राजेन्द्र यादव ने इस चमत्कार को कर दिखाया था. हंस का एक बड़ा योगदान यह भी है कि उसने हिंदी में नए कहानीकारों की कई पीढ़ियां तैयार कर दीं– जिसमें उदय प्रकाश, अखिलेश, शिवमूर्ति, सृंजय, संजय खाती जैसे नामचीन कथाकार हैं. इसी हंस के माध्यम से राजेन्द्र यादव ने हिंदी साहित्य के हाशिए पर पड़े दलित और स्त्री विमर्श के जरिए साहित्य के केंद्र में स्थापित कर दिया. यह राजेन्द्र जी का हिंदी साहित्य को बड़ा योगदान है. उन्होंने कई लेखिकाओं को हंस में छापकर उन्हें न केवल पहचान दिलवाई, बल्कि प्रसिद्धि भी. मैत्रेयी पुष्पा तो खुलेआम कहती हैं कि हंस उनके लिए विश्वविद्यालय है. हालांकि, यादव जी के इस स्त्री विमर्श के भी कई छोर थे और उनपर स्त्री विमर्श की आड़ में देह विमर्श के भी आरोप लगते रहते थे. लेकिन इस तरह के आरोपों से उनको ऊर्जा मिलती थी. विवादों में बने रहने की उनकी आदत की वजह से नामवर जी उन्हें विवादाचार्य कहा करते थे. नामवर जी के साथ उनकी नोंक–झोंक बेहद आनंददायक हुआ करती थी, सार्वजनिक मंच पर भी और व्यक्तिगत रसरंजन के कार्यक्रमों में भी.

इसके अलावा यादव जी ने हंस के संपादकीय के माध्यम से सांप्रदायिकता के खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ी थी. उनके एक संपादकीय में हनुमान पर टिप्पणी से इतना विवाद उठा कि उनके खिलाफ कई केस हुए. हंस की प्रतियां जलाई गईं. हंस के दफ्तर के बाहर हिंदू कट्टरवादियों ने तोड़–फोड़ की. लेकिन यादव जी इससे डिगे नहीं. उस दौर में उन्हें सुरक्षा मिली थी. उनकी जिंदादिली की एक मिसाल– उनका विरोध चल रहा था, उनके घर के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात थे. सुबह–सुबह उनका फोन आया– अरे यार कभी तुम एके 47 के साथ सोए हो. साली रात भर सोने ही नहीं देती. रातभर तंग करती रहती है. हटवाओ किसी तरह से. उन्होंने प्रयत्नपूर्वक अपनी सुरक्षा वापस कर दी. यादव जी की भारतीय लोकतंत्र में अगाध श्रद्धा थी. विचारों में वो खुद को प्रगतिशील मानते थे, लेकिन हंस को उन्होंने एक लोकतांत्रिक मंच बनाया, जहां निशंक भी छपते थे और घोर वामपंथी भी. यादव जी के जाने से हिंदी साहित्य का एक जीवंत कोना बेहद सूना हो गया है. निकट भविष्य में उसकी भरपाई संभव नहीं दिखाई देती. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

पुरानी यादें

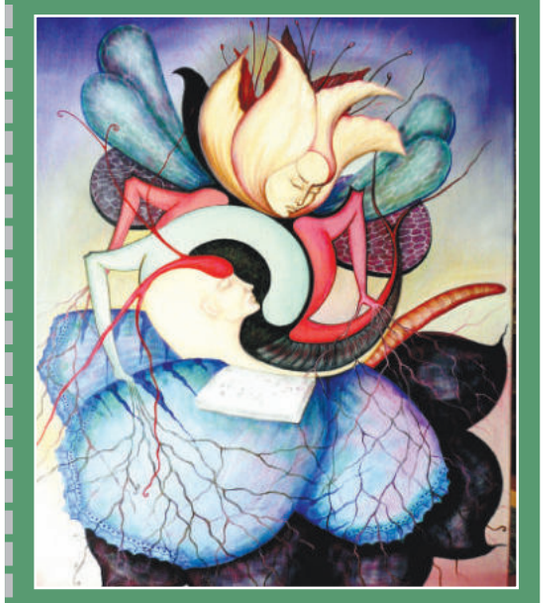

अपराजिता मिश्रा

सोच रही हूं
कुछ सालों से जो उलझा पड़ा है
उसे सुलझा दूं आज
कुछ पुरानी तस्वीरें हैं
थोड़ी यादें भी हैं
जिन्हें दफ़नाने की
एक भरपूर कोशिश में
तुम्हारा दिया हुआ
कांच का शीशा टूटकर
चुभ गया था
निशान मिट गया पर
चुभन अब भी बाक़ी है
पिछली रात को टटोला तो
कुछ टूटी हुई सासें
और कुछ अधूरी बातें भी थीं
पर देख रही हूं कि
वक़्त ने इन्हें कैसे
धुंधला और खोखला कर दिया है
कुछ मुस्कराहटें थीं
जो वक्त के साथ छीज गई हैं
संभाल कर रखे थे
उस वक्त के तमाम निशान
उनकी जगह कोई और भर गया है

स्मृति शेष: पद्मश्री केपी सक्सेना

मेरा मातम न करो

मौत क़िस्मत का नविश्ता है कोई ग़म न करो, ज़ुल्फ़-ए-बरहम को संवारो मेरा मातम न करो... केपी सक्सेना इन पंक्तियों के माध्यम से पहले ही कह चुके थे कि जिंदगी केवल जीने के लिए है, मातम मनाने के लिए नहीं. उत्तर प्रदेश की सरज़मीं पर समय-समय पर ऐसी कई शख्सियतों ने जन्म लिया, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुए. ऐसी ही एक शख्सियत थे हिन्दी साहित्य की महान विभूति केपी सक्सेना यानी कालिका प्रसाद सक्सेना. बीवी नातियों वाली जैसे भारत के पहले टीवी सोप ओपेरा और ऑस्कर की दावेदारी बनी बहुचर्चित फिल्म 'लगान' के संवाद और पटकथा लेखक, अपनी ख़ास शैली से गद्य और व्यंग्य के लेखन को नई ऊंचाइयां देने वाले पद्मश्री केपी सक्सेना ने 81 वर्ष की उम्र में दुनिया से विदाई ली तो साहित्य समाज और उनके चाहने वाले ठगे से रह गए. 1932 में बरेली में जन्मे और 1950 में पिता के साथ लखनऊ आकर बस गए केपी ने यहीं से अपनी साहित्य यात्रा शुरू की और हास्य व्यंग्य की लेखनी को पहचान दिलाई. करीब पांच दशकों तक देश की प्रत्येक प्रमुख पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में अपनी जगह बनाए रखी. उन्होंने मंच पर भी गद्य और व्यंग्य के पाठ की एक ख़ास शैली विकसित की, जिसके चलते उनकी गिनती हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसे प्रमुख व्यंग्यकारों के समकक्ष होती थी. हर उम्र, हर तबके और हर वर्ग के लोगों ने केपी को अपने दिलों में बसा रखा था. इसीलिए साहित्य से लेकर सामाजिक और राजनीतिक से फिल्मी दुनिया तक में केपी की मौत से सन्नाटा छा गया. राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख मुलायम सिंह, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह सहित सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया. केपी का मौत से गहरा नाता था. वे हमेशा मानते रहे कि आनन-फानन में मर जाना सही नहीं है. उन्होंने जिंदगी के अलावा मृत्यु पर भी अपनी लेखनी चलाई थी. वह कहते थे इस शेर को पढ़ने के बाद मेरा मौत का डर ख़त्म हो गया था. अपनी पत्नी को सबसे अच्छा क्रिटिक मानने वाले केपी सक्सेना अपनी पत्नी सावित्री की मौत से बुरी तरह टूट गए थे. पत्नी की मौत के बाद केपी ने मंच से नाता तोड़ लिया था. गत दिनों एक अक्टूबर को वृद्ध दिवस पर उन्हें आख़िरी बार सम्मान मिला और किसी समारोह में देखा गया था. केपी कहा करते थे कि महान साहित्यकार अमृतलाल नागर से प्रेरणा लेने के बाद ही व्यंग्य की दुनिया में उनका पर्दापण हुआ था. हास्य कवि सर्वेश अस्थाना ने बताया कि केपी सक्सेना ने कविताओं और शायरी के दौर में व्यंग्य को शिखर पर पहुंचाया. उन्होंने अपने मुहावरे स्वयं गढ़े. किसी के मरने पर बेचारे खर्च हो गये का मुहावरा उन्हीं का था, जो बाद में लोगों की जुबान पर चढ़ा.

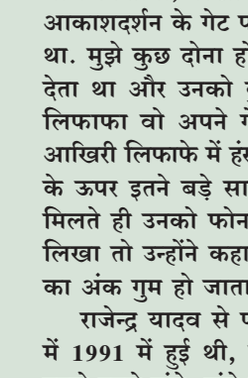

-अजय कुमार

भाषाओं का संगम

समन्वय: भाषा और संस्कृतियों का महोत्सव

हमारी भाषा हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़ी होती है. हर भाषा की ख़ास विरासत है जो कि संबंधित भाषाई समुदाय की पहचान होती है. कहते हैं कि यदि किसी समाज को मारना है तो सबसे पहले उसकी भाषा मिटा दीजिए, वह समाज अपने आप सांस्कृतिक तौर पर मृतप्राय हो जाएगा. आज पूरा विश्व एक भाषा और एक तरह की बाज़ार संस्कृति के पागलपन में मुब्तला है. पूरी दुनिया में हर भाषाई समुदाय पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वह वही भाषा इस्तेमाल करे जिसकी बाज़ार इजाज़त देता हो, भले ही उसकी भाषा कोई भी हो. यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी भाषा सांस्कृतिक दृष्टि से कितनी समृद्ध है, क्योंकि बाज़ार इसकी इजाज़त नहीं देता. ऐसे सांस्कृतिक संकट के दौर में भाषाओं का उत्सव मनाना कितना महत्वपूर्ण है, यह सहज ही समझा जा सकता है.

कृष्णकांत

बीते माह 24 से 27 अक्टूबर के बीच दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारतीय भाषा समारोह समन्वय संपन्न हुआ. समन्वय का यह तीसरा संस्करण था जिसमें साहित्य और कला जगत की तमाम नामचीन हस्तियों ने शिरकत की. समन्वय नामक भाषा महोत्सव का यह मंच दो साल पहले शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है विभिन्न भारतीय भाषाओं की रचनाओं को लेकर एक मंच पर चर्चा हो, सभी भाषाओं के लेखक एक मंच पर एकत्र होकर पाठकों से मुखातिब हो सकें और विभिन्न भाषाओं की विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर लोगों से उसका परिचय कराया जा सके.

इस भाषा उत्सव में किसी एक भाषा के लेखक को सम्मान भी प्रदान किया जाता है. इस बार यह सम्मान गुजराती भाषा के लेखक श्री चंद्रकांत टोपीवाला को दिया गया. पहले दिन भाषा महोत्सव का उद्घाटन उर्दू के मशहूर साहित्यकार शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी और हिंदी के नामचीन कवि विनोद कुमार शुक्ल, नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक एमए सिकंदर और समन्वय के निदेशक राज लिब्राहन ने किया. उद्घाटन सत्र में हाल ही में दिवंगत पार्श्व गायक मन्ना डे और तेलुगू लेखक रवुरी भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी गई. समन्वय के क्रिएटिव डायरेक्टर सत्यानंद निरूपम ने बताया कि पिछले साल इस समारोह में चौदह भाषाओं को शामिल किया गया था. इस बार इसमें बीस भाषाओं को शामिल किया गया. साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं, जिन्हें हमने अब तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया है. इस आधार पर तो हम उन शब्दों के लिए गूंगे ही हुए. प्रख्यात साहित्यकार शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी ने कहा कि हमें ज़बान की ताक़त पहचाननी चाहिए. ज़बान तहज़ीब की जननी होती है. आज के समय में ज़बान की ताक़त का ग़लत इस्तेमाल किया जा रहा है. हम उसे संबंध जोड़ने के बजाय तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

समारोह के दूसरे दिन गीतकार गुलज़ार की क़िताब बोस्की का पंचतंत्र का विमोचन हुआ. इस दिन भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश रहीं लीला सेठ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को अपनी क़िताब हम भारत के बच्चे के बारे में बताया जो कि मूलत: बच्चों को भारत के संविधान की उद्देशिका सरल शब्दों में समझाने के लिए लिखी गई है. दूसरे सत्र में संस्कृतियों के संदर्भ पर चर्चा हुई. इसमें भाषाविद प्रोफेसर अन्विता अब्बी, अंग्रेजी भाषा के विद्वान आलोक राय, आदिवासी विषयों के जानकार अश्विनी कुमार पंकज और भाषाविद उदय नारायण सिंह उपस्थित हुए. इस दौरान आलोक राय ने कहा कि एक आदमी मरता है तो एक दुनिया ख़त्म होती है, लेकिन जब एक भाषा मरती है तो कई लाख संस्कृतियां ख़त्म होती हैं.

उदय नारायण सिंह ने कहा कि यूनेस्को से सर्वे से पता चला है कि भारत में 196 भाषाएं ख़तरे में हैं. तीसरे सत्र में राजस्थानी भाषा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई, जिसमें राजस्थानी भाषा के कई साहित्यकारों ने हिस्सा लिया. चौथे सत्र में तेलुगू भाषा के नामचीन साहित्यकारों ने अपनी बात रखी. पांचवां सत्र खासी भाषा पर आधारित था. अपनी किताब के लोकार्पण के दौरान गुलज़ार साहब ने कहा कि जब जेनेरेशन बदलती है तो ज़बानें भी बदलती हैं. भाषा अगर ज़िंदा है तो बदलती रहेगी. आजकल हिंदी में हिंग्लिश का प्रयोग बढ़ रहा है. इसे बंद करना चाहिए. इस दौरान उन्होंने अपनी कुछ नज़्में पढ़ीं.

समारोह के तीसरे दिन देह का प्रश्न: काम और हिंसा नामक सत्र में प्रख्यात विद्वानों ने अपने विचार रखे. इसमें स्त्रीवादी विचारक कविता कृष्णन, दलित चिंतक कांचा इलैया, निवेदिता मेनन और पत्रकार मीनाक्षी रेड्डी ने शिरकत की. दूसरा सत्र भोजपुरी साहित्य और परंपरा पर हुआ जिसमें पद्मश्री शारदा सिन्हा समेत कुछ विद्वानों ने अपनी बात रखी. तीसरा सत्र फिल्मकार महेश भट्ट, पत्रकार अजय ब्रम्हात्मज और रवि सिंह की बातचीत पर आधारित था. छठवां और सातवां सत्र बांग्ला और पंजाबी साहित्य पर केंद्रित रहा. समारोह के अंतिम दिन सिविल सोसाइटी और उसके क्रांतिकारी पहलुओं पर चर्चा हुई. परंपरा और आधुनिकता पर भी विद्वानों ने चर्चा की. चूंकि यह आयोजन भारतीय भाषाओं के बीच विभिन्न स्तर पर संवाद क़ायम करने के लिए आयोजित किया किया जा रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि यह अपने उद्देश्यों में सफल है. इसके ज़रिये निश्चित ही एक बेहतर सांस्कृतिक परिदृश्य के निर्माण में मदद मिलेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

टोयोटा ने अपनी लग्जरी एसयूवी कार फॉरच्युनर का टीआरडी स्पोर्टीवो के नाम से लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है. नया लुक और डिजाइन देने के लिए कंपनी ने इसमें ड्यूअल फ्रंट और रीयर बंपर स्पॉइलर, रेडियटर ग्रिल पर टीआरडी एंबलेम, बॉडी पर टीआरडी स्ट्रीप्स, बैक पैनल पर रूफ स्पॉइलर दिया है.

Panasonic T31

पैनासोनिक ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन

स्मार्टफोन के बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए पैनासोनिक ने अपना नया और कम दाम का स्मार्टफोन लॉन्च किया है. एंड्रॉयड पर चलने वाले इस स्मार्टफोन में बेमिशाल फीचर्स हैं. कम दाम वाले इस स्मार्टफोन में सारे बढ़िया फीचर्स मौजूद हैं. कम दाम के स्मार्टफोन्स में यह एक बढ़िया विकल्प है. जापानी कंपनी पैनासोनिक ने छोटे शहरों के युवाओं को लक्ष्य बनाते हुए अपना यह स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इसी के मद्देनजर इसके दाम कम रखे गए हैं. कंपनी के मैनेजिंग डॉयरेक्टर (इंडिया) ने बताया कि ये स्मार्टफोन मेट्रो शहर से अलग भारत के छोटे शहरों के युवाओं के लिए खासतौर पर बनाया गया है. पैनासोनिक टी31 फोन एंड्रॉयड जैली बीन ओएस पर चलता है. पैनासोनिक ने इस स्मार्टफोन की कीमत मात्र 8 हजार रुपये रखी है.

जानिए क्या हैं पैनासोनिक टी31 के फीचर्स

- 4 इंच डिस्प्ले स्क्रीन
- 1.3 गीगाहर्ट्ज ड्यूअल कोर प्रोसेसर
- 512 एमबी रैम
- एंड्रॉयड 4.2.2 जैली बीन
- इंटरनल मेमोरी 4जीबी, एक्सपेंडेबल 32 जीबी मेमोरी
- 3.2 मेगा पिक्सल कैमरा
- वीजीए फ्रंट कैमरा
- ड्यूअल सिम स्पोर्ट

लावा का ड्यूअल सिम और वॉयस कॉलिंग

लावा का यह नया टैबलेट एंड्रॉयड 4.1 जैलीबीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कंपनी ने इस टैबलेट को 7 इंच डिस्प्ले स्क्रीन के साथ पेश किया है.

स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनी लावा ने ड्यूअल सिम और वॉयस कॉलिंग सपोर्ट के साथ ई-टैब आइवरी टैबलेट लॉन्च किया है. खास बात यह है कि ई-टैब आइवरी लावा का पहला ड्यूअल सिम और वॉयस कॉलिंग सपोर्ट का टैबलेट है. लावा का यह नया टैबलेट एंड्रॉयड 4.1 जैलीबीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कंपनी ने इस टैबलेट को 7 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन के साथ पेश किया है. इसका स्क्रीन रेज्ल्यूशन 1024-600 पिक्सल है. सिम सपोर्ट का सबसे सस्ता टैबलेट ई-टैब आइवरी 1.2 गीगाहर्ट्ज का ड्यूअल कोर मीडियाटेक प्रोसेसर, 1जीबी रैम और 4जीबी इंटरनल मैमोरी के साथ काम करता है. मैमोरी को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिये 32जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा इसमें 5 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 0.3 एमपी का सेकेंड्री कैमरा दिया गया है. कंपनी ने इसकी कीमत 10,199 रुपये तय की है. ■

आकर्षक रंगों में टोयटा फॉरच्युनर का नया मॉडल

इन दिनों कई कार कंपनियों ने नये मॉडल बाजार में उतारे हैं. इसके अलावा, कुछ कंपनियों ने इस सीजन में अपने लोकप्रिय मॉडल के नये एडिशन भी बाजार में पेश किए हैं. टोयोटा ने अपनी लग्जरी एसयूवी कार फॉरच्युनर का टीआरडी स्पोर्टीवो के नाम से लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है. नया लुक और डिजाइन देने के लिए कंपनी ने इसमें ड्यूअल फ्रंट और रीयर बंपर स्पॉइलर, रेडियटर ग्रिल पर टीआरडी एंबलेम, बॉडी पर टीआरडी स्ट्रीप्स, बैक पैनल पर रूफ स्पॉइलर दिया है. कंपनी ने नई फॉरच्युनर को सुपर व्हाइट तथा सिल्वर माइका मेटेलिक दो रंगों में पेश किया है. टोयोटा ने अपनी इस ग्लोबल एसयूवी को भारतीय बाजार में वर्ष 2009 उतारा था. इसके अलावा, हाल ही में इनोवा, एटिओज सेडान तथा एटिओज लीवा हेचबैक के भी लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर चुकी है. टोयोटा फॉरच्युनर का लिमिटेड एडिशन नई दिल्ली एक्स-शोरूम पर पर इसकी कीमत 24.26 लाख रुपये रखी गई है.■

मोबाइल देगा भूकंप की जानकारी

भूकंप आने के साथ ही यह सेंसर फोन के स्क्रीन पर बनने वाले एक मैप के सहारे धरती के अंदर हो रही गतिविधियों को दिखाना शुरू कर देता है.

आपका स्मार्टफोन भी भूकंप की तरंगों को डिटेक्ट कर सकता है. इसके लिए आपको अपने हैंडसेट में एक छोटा सा सेंसर लगाना होगा. माइक्रोइलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) नाम का यह सेंसर 5 से ज्यादा मैग्निट्यूड वाले भूकंप की तरंगों को पढ़ सकता है. भूकंप आने के साथ ही यह सेंसर फोन के स्क्रीन पर बनने वाले एक मैप के सहारे धरती के अंदर हो रही गतिविधियों को दिखाना शुरू कर देता है. फोन के अंदर लगने वाला यह सेंसर फोन के स्क्रीन का ओरिएंटेशन चेंज कर देता है. हालांकि कम मैग्निट्यूड वाले भूकंप को पढ़ने में सक्षम सेंसर भी जल्द ही मौजूद होगा.

भूगर्भशास्त्रियों के लिए भूकंप के रीयल टाइम आंकड़ों को प्राप्त करना हमेशा से ही मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन एक छोटा सा सेंसर आपके फोन को भूकंप के तरंगों को पढ़ने लायक बना देता है. फोन में लगने वाला यह सेंसर पृथ्वी, वाहनों और घरों में होने वाले कंपन की मात्रा को पढ़ लेता है. साथ ही यह पृथ्वी की गति में आने वाली तेजी को पढ़ने में भी सक्षम है.

एमईएमएस का प्रयोग मूवमेंट और गति को पढ़ने के लिए पहले से भी कंप्यूटर गेम्स में किया जाता रहा है. ■

सैमसंग गैलेक्सी गोल्डन भारत में

सैमसंग ने भारत में अपना हैंडसेट गैलेक्सी गोल्डन लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 51,900 रुपये है. यह एक फ्लिप फोन है. सैमसंग ने कोरिया में इस हैंडसेट को अगस्त 2013 में ही लॉन्च कर दिया था. हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ड से इसे सिर्फ 49,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. सैमसंग गैलेक्सी गोल्डन में 3.7 इंच के दो सुपर अमोल्ड डिस्प्ले दिए गए हैं. इस फोन की सबसे बड़ी विशेषता इसमें दिया गया ईजी मोड है. ईजी मोड में फोन के स्क्रीन पर फॉन्ट और ऐप्लिकेशन का साइज बड़ा दिखता है, जिससे फोन को खोले बिना कॉल आसानी से रिसीव कर सकते हैं. ■

फीचर्स:

- डिस्प्ले – 2 3.7-इंच सुपर अमोल्ड
- ऑपरेटिंग सिस्टम – एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन
- प्रोसेसर – 1.7 जीएचजेड ड्यूअल-कोर
- रैम – 1.5 जीबी
- कैमरा – 8 मेगापिक्सल्स
- फ्रंट कैमरा – 1.9 मेगापिक्सल्स
- इस हैंडसेट में ब्लूटुथ और वाईफाई की सुविधा भी दी गई है.

दिल को जीत लेगी ये कार

निसान कार कंपनी जल्द ही अपनी छोटी हैचबैक कार के डैटसन गो के साथ भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली है.

हाल ही में डैटसन गो को टेस्ट ड्राइव के दौरान चेन्नई की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा गया है. दिखने में यह काफी हद तक मारुति अल्टो 800 की तरह लगती है, जबकि फीचर्स के मामले में एकदम अलग है.

इसके फीचर्स काफी कुछ आई10 और मारुति की बंद हो चुकी कार ए-स्टार की तरह हैं. इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है, जो पावरफुल होने के साथ-साथ ईंधन के मामले में काफी किफायती भी है. इसमें 5 स्पीड मेन्युअल गियर बॉक्स दिया जा रहा है. डैटसन गो हैचबैक में बैठने के लिए काफी स्पेस दिया गया है. कंपनी इस कार को 4 लाख रुपये से भी कम कीमत में लॉन्च कर सकती है. ■

इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है, जो पावरफुल होने के साथ-साथ ईंधन के मामले में काफी किफायती भी है. इसमें 5 स्पीड मेन्युअल गियर बॉक्स दिया जा रहा है. डैटसन गो हैचबैक में बैठने के लिए काफी स्पेस दिया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

वीटेल ने इंडियन ग्रां प्री के अब तक के तीनों खिताब जीते हैं. इस जीत के साथ ही उन्होंने 2013 सीजन का फार्मूला वन चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर लिया है. यह उनका चौथा विश्व खिताब है. मर्सडीज टीम के जर्मन चालक निको रोसबर्ग दूसरे स्थान पर रहे जबकि लोटस टीम के रोमन ग्रोसजीन ने तीसरा स्थान हासिल किया.

गेंदबाज...ढूंढ़ते रह जाओगे

खेल में हर खिलाड़ी का महत्व होता है, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट में गेंदबाजों की लगातार उपेक्षा हो रही है, उससे तो यही लगता है कि आनेवाले दिनों में क्रिकेट अपने विकृत रूप में दर्शकों के सामने आएगा. यह अनायास नहीं है कि इयान चैपल जैसे पूर्व ऑस्टेलियाई खिलाड़ी गेंदबाजों की विलुप्ति की आशंका व्यक्त करते हैं. क्रिकेट में यदि रोमांच बरकरार रखना है तो जरूरत है बल्लेबाजों की तरह ही गेंदबाजों को महत्व देने की, तभी क्रिकेट का जादू खेल प्रेमियों के सिर चढ़ कर बोलता रहेगा.

नवीन चौहान

आ जरा कल्पना कीजिए कि क्रिकेट मैच हो रहा हो. बल्लेबाज हों, विकेटकीपर हो, अंपाएर हो, और गेंदबाज न हों. क्या होगा, अगर क्रिकेट के मैदान से गेंदबाज गायब हो. क्या क्रिकेट खेला जा सकेगा? इसका सीधा सा जवाब होगा कि गेंदबाज के बिना क्रिकेट की कल्पना ही नहीं की जा सकती. लेकिन हो रहा है कुछ ऐसा ही. क्रिकेट को दर्शकों और प्रशंसकों के लिए और ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए गेंदबाजों को बली का बकरा बनाया जा रहा है. आईसीसी जो भी नियम लागू कर रही है, उससे गेंदबाजों को नुकसान हो रहा है. युवा खिलाड़ी गेंदबाज बनने की जगह बल्लेबाज बनने को तरजीह दे रहे हैं. एक ज़माना था, जब क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजों की तूती बोलती थी. अनकवर्ड पिच के साथ–साथ बाउंसर्स से लैस तूफानी गेंदबाजी का सामना करने में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के पैर कांपते थे, लेकिन जैसे–जैसे क्रिकेट को दुनिया भर में लोकप्रियता मिलने लगी, तब उसे और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की मुहिम में जाने–अंजाने में तेज गेंदबाजों पर बहुत सी पाबंदियां लग गईं. इस कवायद में नियम में जो भी बदलाव किए गए, वे सभी गेंदबाजों के खिलाफ थे. इस वजह से गेंदबाजी की धार कुंद होती गई.

जब–जब क्रिकेट को और ज्यादा मनोरंजक बनाने की कोई पहल हुई, गेंदबाज हमेशा ही नुकसान में रहा है. नब्बे के दशक में फील्डिंग के नियमों में बदलाव किया गया. इससे पहले 30 गज के दायरे के बाहर क्षेत्ररक्षण करने वाले खिलाड़ियों की संख्या का कोई बंधन नहीं था. कप्तान गेंदबाजी और अपनी नीति के आधार पर फिल्डरों को मैदान के किसी भी हिस्से में तैनात करता था. इस वजह से गेंदबाज आजादी से गेंदबाजी करते थे, लेकिन जैसे ही शुरुआती 15 ओवरों में केवल दो खिलाड़ियों के बाहर रहने का नियम आया, तब से मैदान में बल्लेबाजों का वर्चस्व बढ़ गया. सचिन जैसे बल्लेबाजों ने इस नियम का फायदा उठाकर पारंपरिक तरीकों से इतर तेजी से रन बनाने के ट्रेंड की शुरुआत की. इसके बाद से लगातार गेंदबाजों की बादशाहत मैदान पर कम होती गई.

सपाट पिचों में गेंदबाज़ी करना गेंदबाजों के लिए दुःस्वप्न की तरह हो गया है. स्पिनर्स रन बचाने के चक्कर में टू दी लाइन गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, वे गेंद को फ्लाइट कराने की जरा भी कोशिश नहीं करते हैं. वहीं, तेज गेंदबाज भी गेंदबाजी के दौरान किसी भी तरह के प्रयोग से बचने की कोशिश करते हैं. दो गेंदों से गेंदबाजी कराए जाने पर भी सवाल उठते रहे हैं. दोनों छोर से नई अलग–अलग गेंदों के इस्तेमाल की वजह से स्पिन गेंदबाजों को नुकसान होता है. जब तक गेंद कड़ी रहती है, बल्लेबाज उसे दूर तक पूरी ताकत के साथ मारने में सक्षम होता है. एक समय पुरानी गेंद धीमी गति के खासकर स्पिन गेंदबाजों के पास एक घातक हथियार की तरह होती थी, लेकिन नियमों के बदलाव की वजह से उनका यह हथियार भी उनसे छीन लिया गया. पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग पाने में भी आसानी होती थी, लेकिन यह अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है. गेंदबाज अब तक पावर प्ले और दो नई गेंदों के नियमों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं.

हाल में ही संपन्न हुई भारत ऑस्ट्रेलिया एकदिवसीय सीरीज में लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के 350 रन के लक्ष्य को हासिल करने पर खुशी जताई, लेकिन उन्होंने इस बात पर चिंता भी जताई कि इतने बड़े लक्ष्य को अधिकांश बाउंड्री से हासिल कर लेना लंबे समय में क्रिकेट के लिए सही नहीं है. एकदिवसीय मैचों में पूरे समय 30 गज के घेरे के अंदर कुल पांच फील्डर रखने के नियम पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह गेंदबाजों के खिलाफ है. आईसीसी को इस नियम की एक बार फिर से समीक्षा करनी चाहिए. इस नियम की वजह से गेंदबाज असहाय हो गए हैं.

हाल में ही संपन्न हुई भारत ऑस्ट्रेलिया एकदिवसीय सीरीज में लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के 350 रन के लक्ष्य को हासिल करने पर खुशी जताई, लेकिन उन्होंने इस बात पर चिंता भी जताई कि इतने बड़े लक्ष्य को अधिकांश बाउंड्री से हासिल कर लेना लंबे समय में क्रिकेट के लिए सही नहीं है. एकदिवसीय मैचों में पूरे समय 30 गज के घेरे के अंदर कुल पांच फील्डर रखने के नियम पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह गेंदबाजों के खिलाफ है. आईसीसी को इस नियम की एक बार फिर से समीक्षा करनी चाहिए. इस नियम की वजह से गेंदबाज असहाय हो गए हैं. कुछ गेंदबाजों को लगता है कि इन परिस्थितियों में गेंदबाजी मशीनें ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. उनकी जगह मशीनों को ही मैदान पर उतार देना चाहिए. धोनी का वक्तव्य यह बताता है कि गेंदबाजों के अंदर निराशा किस गहराई तक घर कर गई है, लेकिन इससे पार पाना गेंदबाजों के लिए एक नई चुनौती बन गया है.

इस तरह के खेल से दर्शकों का मनोरंजन हो रहा है, लेकिन अलग टीमें इसी तरह बड़े लक्ष्यों को हासिल करती रहीं तो यह खेल की सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा. क्रिकेट में बल्लेबाजी महत्व–पूर्ण है, लेकिन गेंदबाजी इसका अभिन्न अंग है. बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी के क्षेत्र में यदि व्यापक ध्यान नहीं दिया गया तो क्रिकेट का कद बड़ा नहीं हो सकता है, न ही वह समृद्ध हो पाएगा. आज क्रिकेट में जो कुछ भी हो रहा है, मसलन मैच की परिस्थितियां, फ्लैट पिचों का निर्माण, नियमों में बदलाव, पावर प्ले, यह सब कुछ गेंदबाजों के खिलाफ एक साजिश की तरह दिखाई पड़ रहा है. गेंदबाजों के पक्ष में आवाजें तो उठती हैं, लेकिन पैसे की खनक और दर्शकों के शोर के बीच ये आवाजें कहीं गुम हो जाती हैं. दर्शकों के बिना सब कुछ अधूरा है. यदि दर्शक नहीं, तो स्पॉन्सर्स नहीं, स्पॉन्सर्स नहीं, तो पैसा भी नहीं. दर्शक मैदान में चौके–छक्के देखने आते हैं. यदि इसके लिए बल्लेबाजों को आजादी और गेंदबाजों पर पाबंदी लगती रही तो वास्तव में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल की गेंदबाजों की कमी की आशंका सही साबित हो सकती है. हमें कहीं तो लगाम खींचनी ही पड़ेगी. सिर्फ पैसे के लिए खेल के वजूद को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए. गेदबाजों को भी बल्लेबाजों की तरह वरीयता दी जानी चाहिए. क्रिकेट के विकास में और उसे पॉपुलर बनाने में जो योगदान सचिन, लारा, द्रविड़, पोंटिंग जैसे खिलाड़ियों का है, ठीक वैसा ही शेनवार्न, मुरलीधरन, कर्टनी वॉल्श, कुंबले, अकरम और मैग्रा का भी है. क्रिकेट में उनके यो–गदान को बल्लेबाजों की तुलना में कतई कमतर नहीं आंका जा सकता, लेकिन अब समय गेंदबाजों और गेंदबाजी की विभिन्न शैलियों को बचाने की है. इसके लिए उन्हें और ज्यादा आजादी देनी होगी.

टी–20 क्रिकेट की शुरुआत के बाद गेंदबाजों के लिए स्थितियां ज्यादा भयावह हो गई हैं. टी–20 मैचों के दौरान गेंदबाज बल्लेबाज को आउट करने के बजाए रन बचाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. इयान चैपल के अनुसार, बल्लेबाजी में भारी बल्लों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ने और सीमित ओवरों के क्रिकेट में छोटी बाउंड्री के चलन की वजह से क्रिकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल बन गया है और कुछ सालों में गेंदबाज विलुप्त प्रजाति बन सकते हैं. चौके और छक्कों की मदद से आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन यह खेल के लिए ठीक नहीं है. अब जो क्रिकेट हो रहा है, वहां गेंदबाजों के करने के लिए कुछ नहीं है. सारी बंदिशें गेंदबाजों के लिए हैं, बल्लेबाजों के लिए कोई बंदिशें नहीं हैं. बल्लेबाज चाहे स्विच हिट करे या कुछ और, वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब बात गेंदबाजों की आती है तो बंधनों की कहानी शुरू हो जाती है. सर डॉन ब्रेडमैन की आक्रामक बल्लेबाजी के खिलाफ शुरू हुई बॉडी लाइन गेंदबाजी ने गेंदबाजों के उस आक्रामक रुख को दिखाया था, जिसमें गेंद बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाकर फेंकी जाती थी, लेकिन बल्लेबाजों और खेल भावना को ख़्याल में रखकर बॉडीलाइन गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

यदि गेंदबाजों पर लगातार इसी तरह की बंदिशें लगती रहीं तो आगे चलकर गेंदबाज बॉल टेंपरिंग, चकिंग और बॉडीलाइन जैसे तरीके अपना सकते हैं. गेंदबाजों को खेल के छोटे फॉर्मेट में सपोर्ट की जरूरत है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो गेंदबाज जंग पर उतर आएंगे. आईसीसी खेल में अधिक से अधिक पैसा लाने और इसे वैश्विक स्तर पर और अधिक सफल बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उस कार्य के बीच उसे गेंदबाजों के लिए थोड़ा समय निकालना होगा और उनको मजबूत करने के लिए कदम उठाने होंगे. अन्यथा गेंदबाजों का वजूद खत्म हो जाएगा और क्रिकेट का वजूद खतरे में पड़ जाएगा.

किसी भी बल्लेबाज का कद उस दौर के बेहतरीन गेंदबाजों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. सुनील गावस्कर को महान इसलिए माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पीढ़ी या कहें क्रिकेट के सार्वकालिक महान और खतरनाक गेंदबाजों का सामना हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों के बिना किया और टेस्ट मैचों में 10 हजार रन के आंकड़ों तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने थे. यदि हम बेहतरीन और कुशल गेंदबाज नहीं बना सकेंगे तो बल्लेबाजों के कद का आकलन कैसे करेंगे. इसलिए गेंदबाजों को भी बल्लेबाजों की तरह प्रोत्साहित करना होगा. कुछ गेंदबाजों को फायदा पहुंचाने वाले नियम भी बनाने होंगे. यदि हम बेहतरीन गेंदबाजों की एक नई पीढ़ी खड़ी नहीं कर सके तो यह प्रशंसकों के साथ–साथ क्रिकेट की हार होगी. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

विटेल ने इंडियन ग्रां प्री जीती

रेड बुल टीम के जर्मन ड्राइवर सेबास्टियन विटेल नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित इंडियन ग्रां प्री लगातार तीसरी बार जीत ली है. वीटेल ने इंडियन ग्रां प्री के अब तक के तीनों खिताब जीते हैं. इस जीत के साथ ही उन्होंने 2013 सीजन का फार्मूला वन चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर लिया है. यह उनका चौथा विश्व खिताब है. मर्सडीज टीम के जर्मन चालक निको रोसबर्ग दूसरे स्थान पर रहे जबकि लोटस टीम के रोमन ग्रोसजीन ने तीसरा स्थान हासिल किया. विटेल की जीत के साथ रेड बुल टीम ने कंस्ट्रक्टर्स खिताब पर भी कब्जा किया. रेड बुल टीम का भी यह चौथा खिताब है. इंडियन ग्रां प्री का फिलहाल यह अंतिम संस्करण था था आगे फार्मूला वन रेस भारत में कब आयोजित की जाएगी इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं नहीं हुआ है. रेस जीतने के बाद अति उत्साह में जश्न मनाने के कारण रेड बुल पर टीम पर 25 हजार यूरो का जुर्माना लगाया गया. ■

सचिन पर डाक टिकट जारी होगा

विश्व में ऐसी कई चर्चित शख्सियतें हैं, जिनपर डाक टिकट जारी किया गया है. इस फेहरिस्त में अब सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल होने जा रह है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन(एमसीए) ने सचिन तेंदुलकर के करियर के 200 वें टेस्ट मैच में सचिन के फोटो वाला डाक टिकट जारी किया जाएगा. 200% में टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ी रोजर फेडरर पर भी स्विटजरलैंड में डाक टिकट जारी किया गया था. ■

भारत को एशियाई तीरंदाजी का स्वर्ण

भारतीय कंपाउंड टीम ने चीनी ताइपेई में हुई 18 वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. भारतीय टीम ने फाइनल मुक़ाबले में कोरियाई टीम को 233–231 के स्कोर से मात दी. अभिषेक वर्मा,रतन सिंह और संदीप कुमार की भारतीय तिगड़ी ने क्वालीफाइंग राउंड से बेहतरीन प्रदर्शन किया. टीम क्वालीफाइंग राउंड में 2086 अंकों के साथ शीर्ष पर रही. टीम ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपेई को और क्वाटरफाइनल मुक़ाबल में इराक की टीम को मात दी थी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

करीना का रोमान्स

बेबो और रोमान्स का क़रीबी रिश्ता है. बॉलीवुड की सनसनी हुस्न की मल्लिका बेबो यानी करीना कपूर अब करीना कपूर ख़ान हो गई हैं. 21 सितम्बर, 1980 को मुंबई में जन्मीं बेबो ने लंदन में अपना 33वां जन्मदिन मनाया और इसी हफ्ते 16 अक्टूबर को उन्होंने लंदन में ही अपनी शादी की सालगिरह भी बड़े धूम-धाम से मनाई. चूंकि यहां बेगम साहिबा के नवाब साहब अपनी फिल्म बुलेट राजा की शूटिंग मे व्यस्त थे, ऐसे में बेबो भी अपनी फिल्म हमशक्ल की शूटिंग के बाद यहां पहुंच गईं.

सलमान फिर चाहते हैं करीना से रोमान्स? ये खबर आग की तरह बॉलीवुड के गलियारों से निकलकर फिल्म प्रेमियों के दिलों तक पहुंच चुकी है. बात इतनी सी है कि सलमान खान, सूरज बड़जात्या के साथ अपनी अगली फिल्म करने जा रहे हैं, जिसमें सलमान ने करीना कपूर खान की सिफारिश की है. हालांकि इससे पहले अनुष्का शर्मा और इलियाना डीक्रूज के नामों पर भी चर्चा हो चुकी है. बॉडीगार्ड का मानना है कि उनकी बॉडीगार्ड फिल्म ने 230 करोड़ का बिज़नेस किया था, इसलिए शायद इस लकी लेडी के साथ ये जोड़ी फिर करोड़ी जोड़ी साबित हो सके और फिल्म में भी रोमान्स और रोकड़े दोनों का जुगाड़ हो जाए.

बेबो और रोमान्स का क़रीबी रिश्ता है. बॉलीवुड की सनसनी हुस्न की मल्लिका बेबो यानी करीना कपूर अब करीना कपूर ख़ान हो गई हैं. 21 सितम्बर, 1980 को मुंबई में जन्मीं बेबो ने लंदन में अपना 33वां जन्मदिन मनाया और इसी हफ्ते 16 अक्टूबर को उन्होंने लंदन में ही अपनी शादी की सालगिरह भी बड़े धूम-धाम से मनाई. चूंकि यहां बेगम साहिबा के नवाब साहब अपनी फिल्म बुलेट राजा कि शूटिंग में व्यस्त थे, ऐसे में बेबो भी अपनी फिल्म हमशक्ल की शूटिंग के बाद यहां पहुंच गईं.

करीना कि बात हो और शाहिद कपूर का ज़िक्र न हो तो बात ज़रा अधूरी सी रह जाती है. ऐक्टर शाहिद कपूर के साथ उनके रोमान्स के क़िस्से सारी दुनिया की ज़ुबान पर थे या यूं कहिए कि करीना ने इस रिश्ते पर अपनी मंज़ूरी की मुहर लगा दी थी. शाहिद कपूर के बाद उनके रोमान्स की रस्सी नवाब सैफ अली ख़ान ने थाम ली. कई सालों के हिट रोमांटिक रिश्ते की चर्चा पर 16 अक्टूबर, 2012 को पूर्ण विराम लग गया, जब सैफ और करीना सैफ़ीना बनकर शादी के रिश्ते में बंध गए.

कपूर ख़ानदान से नवाब ख़ानदान तक पहुंचने के इस सफर में करीना कपूर ने अपने काम और क़ाबिलियत का लोहा मनवाया. बॉलीवुड की इस बोल्ड अदाकारा ने सन 2000 में निर्माता, निर्देशक जे.पी. दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से अपना फिल्मी सफर शुरू किया. ये फिल्म उनके करियर में कुछ बड़ा नहीं कर पाई, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म मुझे कुछ कहना है 2001 में जबर्दस्त हिट हुई. करीना की ख़ूबसूरती और काम की ख्याती चारों तरफ मुश्क की खुशबू की तरह फैलती गई. गॉसिप के गलियारों से गुज़रकर तरक़्क़ी की सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते करीना ने अपने आलोचकों का मुंह बंद किया और दर्शकों के दिलो-दिमाग पर नशा बनकर छा गईं. करीना ने 12 सालों में तकरीबन 50 से ज़्यादा फिल्में देकर बेहतरीन और कामयाब अदाकाराओं की लिस्ट में अपना नाम दर्ज़ कराया.

बचपन से चुलबुली और शरारती करीना ने अपनी फिल्मों में भी सभी तरह की भूमिकाएं करके अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए. सुभाष घई की फिल्म यादें में उन्होंने एक ईमानदार बाप की होनहार बेटी की भूमिका को बहुत ही सजीव ढंग से निभाया.

बॉलीवुड के शिखर पर रहते हुए उन्होंने आमिर खान के साथ तलाश, शाहरुख खान के साथ रा-वन और सलमान खान के साथ फिल्म बॉडीगार्ड में अपने उमदा अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता. उनकी कुछ फिल्में कभी खुशी कभी ग़म, अशोका, मुझसे दोस्ती करोगे, एल ओ सी, चमेली, युवा, एतराज, हलचल, क्योंकि, ओंकारा, डॉन, जब वी मेट, गोलमाल, बिल्लू बार्बर, कुर्बान, 3 इडियट्स, गोलमाल-3, तलाश और सत्याग्रह जैसी कामयाब फिल्मों में दमदार भूमिका निभाकर एक कामयाब अदाकारा होने के सुबूत दिए.

करीना का अपने परिवार के साथ बहुत ही करीबी और दिल का रिश्ता रहा है. मशहूर कलाकार रणधीर कपूर और बबीता की इस छोटी बेटी और मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर की छोटी बहन ने अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा. रिश्तों की गहरी समझ का अंदाज़ा उनकी इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने से दस साल बड़े और दो बच्चों के पिता सैफ अली ख़ान से शादी की और वो आज एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं. जीवन का ये रोमांस जितना भी रोमांटिक हो, पर रील और रियल लाइफ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है. रोमान्स से याद आया कि उनकी अगली फिल्म अपने नाम से ही बड़ी रोमांटिक मालूम होती है, जिसका नाम है, गोरी तेरे प्यार में. धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर की इस फिल्म में इमरान ख़ान उनके हीरो हैं. इसके साथ-साथ हम अपने पाठकों को बताते चलें कि करीना अपना शुद्धिकरण कर रही हैं. अरे भई, उनकी नई फिल्म का नाम शुद्धि है, जिसमें उनके को स्टार हैं ऋतिक रोशन और इसके अलावा उनकी आने वाली फिल्म हमशक्ल भी है. ■

ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एक अनोखा फनकार, यह पंक्तिया आज भी उतनी ही सत्य हैं, जितनी सत्यता से सत्यजीत रे ने इनको कहा था. फिल्म के फ़लक पर अपना नाम दर्ज़ कराने वाले इस विचित्र फनकार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ ख़ान है, जिसे दुनिया दिलीप कुमार के नाम से पहचानती है.

11 दिसम्बर, 1922 को गुलाम भारत के पेशावर शहर में एक पठान परिवार में जन्मे यूसुफ ख़ान 12 भाई-बहनों में से एक थे. उनके पिता लाला गुलाम सरवर पेशे से फल व्यापारी थे. दिलीप उनके साथ नाशिक के पास देवलाली में आ गए. यहीं बार्नेस स्कूल में उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और कुछ दिनों बाद ही पूना के मिलिट्री कैंटीन में वे ड्राइ फ्रूट्स के सप्लायर हो गए. संयोग से यहीं बॉम्बे टॉकिज के मालिक हिमांशु रॉय और उनकी पत्नी देविका रानी, जो पहले से ही एक्ट्रेस थीं, की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने बहुत ही सोच-विचार कर यूसुफ को अपनी फिल्म ज्वार भाटा का हीरो चुना. यहीं से उनके लिए ज़िंदगी ने बॉलीवुड का एक नया दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया.

मशहूर कहावत है कि जगह बदलने से तक़दीर बदलती है. अब शायद यूसुफ की हर चीज़ बदल रही थी. मशहूर लेखक भगवती चरण वर्मा ने उन्हें दिलीप कुमार एक नया नाम दिया, जिसने भारत के माथे पर अपनी पहचान का तिलक लगा दिया.

दिलीप कुमार ने मुंबई को अपनी कर्मभूमि चुना. बॉलीवुड अब तक जैसे किसी पहचान का मोहताज़ बना घूम रहा था. दिलीप कुमार उसका चेहरा बन गए. उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी और क़ाबिलियत का लोहा मनवाया. दिलों पर राज कर चुके इस एक्टिंग के शहंशाह को लोगों ने ट्रेजिडी किंग के खिताब से नवाज़ा, लेकिन मुगल-ए-आज़म, देवदास और अंदाज़ जैसी फिल्मों में उनके रोमान्स का जादू मोहब्बत की मिसाल बन गया.

मशाल, शक्ति, कर्मा और क्रांति जैसी देशभक्ति फिल्मों में उन्होंने देशभक्ति की चरम सीमा को छुआ और अभिनय के नये-नये आयामों को जन्म दिया. अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू, हिंदको और पश्तो आदि भाषाओं का बेहतरीन ज्ञान रखने वाले इस कलाकार की दुनिया दीवानी हो गई.

जोगन और शहीद के बाद उनकी फिल्म अंदाज़ बहुत ही कामयाब फिल्म रही, जिसमें उनके साथ राज कपूर और नर्गिस भी थे. नौशाद का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के गीत, जिन्हें अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया था लता मंगेशकर और मुकेश ने. इस फिल्म के गानों ने हर संगीत प्रेमी के दिल में मोहब्बत की ज्योति जगा दी और दिलीप कुमार का एक नया अंदाज़ मंजर ए आम पर आया.

50 के दशक में उनकी बुलंदी का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा. जोगन, दीदार, दाग़ और मधुमती जैसी फिल्मों में उनका अभिनय हैरान कर देने वाला था. वे बॉलीवुड के पहले एक्टर हैं, जिन्हें फिल्म दाग़ के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला. उसके बाद उन्हें देवदास, आज़ाद, और नया दौर के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड से नवाज़ा गया. 1950 से 1961 तक दिलीप कुमार बॉलीवुड के हाइएस्ट पेड एक्टर रहे.

दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्मों की अभिनेत्री नर्गिस, कामिनी कौशल, मीना कुमारी, मधुबाला और वैजयंतीमाला को बहुत पसंद किया जाने लगा. यहां तक की कामिनी कौशल और वैजयंतीमाला से उनके रिश्ते काफी सुर्खियों में रहे. इसके अलावा मधुबाला से उनके रिश्तों की चर्चा पूरे देश में उनके फ़ैन्स की ज़ुबान पर थी. दिलीप कुमार उनसे शादी भी करना चाहते थे, पर मधुबाला की फैमिली को ये रिश्ता मंज़ूर नहीं था. इसलिए दिलीप कुमार ने भी वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए इस पर नामंज़ूरी की मोहर लगा दी.

60 के दशक में कोहिनूर, मुगल-ए-आज़म, गंगा जमुना, लीडर, राम और श्याम ने उनकी शोहरत में चार चांद लगा दिए. यह वो दौर था, जब हर कोई उनकी शादी की तलब लिए फिल्म जगत की हर हीरोइन की तरफ देख रहा था और इस रोमांटिक दिलचस्पी को और खुशनुमा बनाया अपने जमाने की ब्यूटी क्वीन अदाकारा सायरा बानो ने. सायरा बानो बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत नयन-नक्श वाली चंचल, शरारती और दिलकश उभरती अदाकारा थीं. हर कोई उनको मिसेज दिलीप कुमार के रूप में देखना चाहता था. काफी चर्चा के बाद 1966 में सायरा बानो और दिलीप कुमार शादी के पवित्र बंधन में बंध गए. ये शादी बहुत ही चर्चा में रही, क्योंकि इसमें हैरतअंगेज़ और दिलचस्प बात यह थी कि सायरा बानो उनसे उम्र में 22 साल छोटी थीं. यानी दिलीप कुमार 44 साल के और सायरा बानो सिर्फ 22 की थीं. फिर भी इस रिश्ते को उनकी दीवानी जनता ने सिर आंखों पर लिया. शादीशुदा ज़िंदगी की रफ्तार ने तरक़्क़ी और कामयाबी की बुलंदियों और बेपनाह शोहरतों को छुआ. दिलीप कुमार जनता के दिलों पर लगातार राज़ करने में कामयाब रहे.

1980 में दिलीप कुमार का एक रोमान्स चर्चा में आया, जिसने पूरे देश में धूम मचा दी. जिसके दिल में दिलीप कुमार की मोहब्बत ने पैर पसारे, वह मुहतरमा थीं असमा...कब दिलीप कुमार, सायरा बानों की मुहब्बत से आंखमिचौली करके असमा से नैन मटक्का कर बैठे, पता ही नहीं चला और 1980 में उन्होंने इस हैदराबादी लड़की असमा से निकाह कर लिया. पूरे देश में ये बात आम हो गई कि दिलीप और सायरा बानों के रिश्तों मे खटास आ चुकी है, लेकिन यह रिश्ता मोहब्बत का न होकर गरज़ का निकला. आहिस्ता-आहिस्ता असमा की बदनीयत का पर्दाफाश हो गया, जिससे तंग आकार दिलीप कुमार ने अगले ही साल असमा को तलाक दे दिया और वापस अपनी हुस्न की मल्लिका सायरा बानों की मोहब्बत की बगिया में लौट आए.

मशाल, कर्मा, कानून अपना अपना और सौदागर जैसी बेहतरीन कामयाब फिल्में देकर इस महान अभिनेता ने अपना फर्ज़ पूरा किया. दिलीप कुमार को उनकी कामयाब अदाकारी और बेहतरीन इंसानियत के लिए बेशुमार अवॉर्डों से नवाज़ा गया. अपनी उम्दा अदाकारी के लिए उन्होंने फिल्मों का सबसे बड़ा अवॉर्ड फिल्मफेयर अवार्ड उठाया और ये अवॉर्ड सबसे ज़्यादा 8 बार उठाने के लिए उनका नाम आज भी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज़ है. उनकी बराबरी का यह रिकॉर्ड आज सिर्फ शाहरुख ख़ान के पास है. दिलीप कुमार को उनकी कामयाबी और क़ाबिलियत के लिए भारत सरकार ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया. उन्हें 1991 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से नवाज़ा गया.

ज़िंदगी और बुलंदी का बड़ा ही कमाल का रिश्ता है. जब दोनों मिलते हैं तो शाम हो जाती है या यूं कहिए कि साये लंबे हो जाते हैं, जब शाम का सूरज ढलता है. कुछ ऐसा ही वक़्त आ चला था, जब दिलीप कुमार को 1993 में उनके बेहतरीन फिल्मी सफर के लिए फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया. अवॉर्ड्स का सिलसिला अभी थमा नहीं. चूंकि मेहनत के सही फल का समय तो अब आया था, जब उनको 1994 में फिल्मी जगत के सबसे बड़े सम्मान दादासाहेब फालके अवॉर्ड से नवाजा गया. विदेशों में अपनी अलग पहचान रखने वाले दिलीप कुमार को 1998 में हुकूमत ए पाकिस्तान ने अपने यहां के सबसे बड़े सम्मान निशान-ए-इम्तियाज़ से नवाज़ा. हुकूमत ए पाकिस्तान की तरफ से यह किसी भारतीय को मिलने वाला दूसरा अवॉर्ड है. इससे पहले मोरारजी देसाई को इस सम्मान से नवाज़ा गया था.

गुज़रते वक़्त के साथ बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की दहलीज़ पर कब इंसान आकर खड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता. ठीक उसी तर्ज़ पर आज के एक्टिंग के बेताज बादशाह ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार भी हैं, पर आज भी वे लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल है 2012 में मनाया गया उनका ऐतिहासिक बर्थडे. 11 दिसंबर की शाम दिलीप साहब की ज़िंदगी और भी यादगार बन गई, जहां उन्हें जन्मदिन का मुबारकबाद देने पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा. यहां तक कि आमिर खान, शाहरुख, सलमान और अमिताभ बच्चन सहित सभी बांद्रा स्थित उनके घर जमा हुए और उनको दिली मुबारकबाद पेश की. आजकल दिलीप साहब बीमार चल रहे हैं और हाल ही में अस्पताल से घर लौटे हैं. ■

प्रीव्यू

रज्जो

डायरेक्टर	विश्वास पाटिल
प्रोड्यूसर	फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट
लेखक	जयंत पवार और विश्वास पाटिल
स्टार	कंगना रानाउत, पारस अरोरा, महेश मांजरेकर, प्रकाश राज
संगीत	उत्तम सिंह
रिलीज	15 नवंबर

गैंगस्टर, वो लम्हे और फैशन जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकीं कंगना बहुत जल्द ही एक नये रूप में नजर आएंगी. दर्शकों को उनका यह नया रूप उनकी आने वाली फिल्म रज्जो में देखने को मिलेगा. यह एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है, जो मुंबई में कोठों की घटती संख्या पर आधारित है. फिल्म में रज्जो (कंगना रानाउत) और चंदू (पारस अरोरा) की प्रेम कहानी है. कंगना इस फिल्म में कोठे पर मुजरा करने वाली बनी हैं, जो 18 वर्षीय पारस के साथ रोमांस करती नजर आएंगी. रज्जो जिस कोठे पर मुजरा करती हैं, उसी कोठे पर 18 वर्षीय चंदू (पारस अरोरा) अपने दोस्तों के साथ आता है और रज्जो (कंगना रानाउत) को दिल दे बैठता है. यहीं से शुरू होती है युवा दिलों की अनकही प्रेम कहानी. नायिका प्रधान फिल्म होने के कारण इस फिल्म में कंगना की भूमिका काफी सशक्त है. इस फिल्म में संजय मांजरेकर महिला किरदार के रूप में एक अलग अंदाज में नजर आएंगे.

फिल्म को प्रोड्यूस किया है फोर पिलर्स इंटरटेनमेंट ने और निर्देशित किया है साहित्य अकादमी अवॉर्ड के विजेता और लेखक विश्वास पाटिल ने. सहायक कलाकार की भूमिका में हैं प्रकाश राज, महेश मांजरेकर और जया प्रदा. इस फिल्म में कंगना रज्जो की भूमिका में हैं. इसके अतिरिक्त पारस अरोरा चंदू की भूमिका में, महेश मांजरेकर बेगम की भूमिका में, प्रकाश राज हंदे भाउ की भूमिका में हैं. काफी दिनों बाद हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा भी इस फिल्म में शिरकत कर रही हैं, जिन्होंने जानकी देवी की भूमिका में चार चांद लगा दिया है. यह फिल्म 15 नवम्बर, 2013 को देश भर के सिनेमा हॉल में रिलीज होगी. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

11 नवंबर–17 नवंबर 2013

बिहार–झारखंड

हुंकार से कांपा जदयू

बम के धमाकों के बीच लोगों का जनसैलाब नरेंद्र मोदी को सुन रहा था और भारत माता की जय के नारों से पूरा गांधी मैदान गूंज रहा था. गूंज ऐसी की बम के धमाकों की आवाज उसके सामने कमजोर पड़ रही थी. बस उसी दृश्य ने जदयू नेताओं को अंदर से राजनीतिक तौर पर बेहद डरा दिया. सत्ता के मद में चूर जदयू नेताओं को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की हवा बनावटी है और जमीन पर भाजपा की ताकत बेहद कमजोर है. रैली में भीड़ आएगी सभी को अनुमान था, लेकिन इतनी ज्यादा और समर्पित भीड़ आएगी इसका अनुमान लगाने में जदयू के नेता गच्चा खा गए.

सरोज सिंह

नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के बाद जैसा की सोचा जा रहा था आखिरकार वही खतरा जदयू पर मंडराने लगा है. कल तक दबी जुबान से कही जाने वाली बात अब तो नीतीश कुमार के सामने सार्वजनिक मंच पर गरज–गरज कर कही जा रही है. राजगीर में जदयू के सामने आने वाली नरेंद्र मोदी की चुनौती और कार्यकर्ताओं के सम्मान को ढाल बनाकर कही गई बातों का लब्बोलुआब यही है कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी पर पकड़ ढीली पड़ती जा रही है. राजगीर के मंच पर मुख्यमंत्री के सामने शिवानंद तिवारी और नरेंद्र सिंह की कड़वी बातों को सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था. जानकार बताते हैं कि अगर उस दिन नीतीश कुमार के स्तर पर इन नेताओं के भाषणों में कोई हस्तक्षेप होता तो पार्टी उसी दिन दो हिस्से में बंट सकती थी. लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए नीतीश कुमार केवल श्रोता की भूमिका में बने रहे. दरअसल राजगीर के चिंतन शिविर में जो कुछ भी हुआ उसे हुंकार रैली के साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है. जदयू की राजनीति को नजदीक से समझने वाले यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला पार्टी के अधिकांश नेताओं को पसंद नहीं था. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से नीतीश कुमार के पास इन भावनाओं को रखा भी गया लेकिन नीतीश कुमार ने ठान ही लिया था कि उन्हें अब साथ नहीं रहना है. बहुत सारे ऐसे राजनीतिक और समाजिक कारण हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. विस्तार से इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है. इसलिए दोहराना ठीक नहीं होगा. आमधारणा बन गई है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश ने भाजपा को छोड़ दिया.

नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार ने जदयू–भाजपा की 17 साल पुरानी दोस्ती की बलि चढ़ा दी. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतने भोले हैं कि राजनीतिक सच्चाइयों को नहीं समझ कर सपनों का महल बनाने के लिए अपना बना बनाया आशियाना तोड़ कर रख देंगे. गठबंधन तोड़ने के फैसले के कारणों में प्रधानमंत्री बनने का विकल्प एक छोटा सच हो सकता है लेकिन यह पूरा सच नहीं है जैसी की आमधारणा बनती जा रही है. इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें बिहार में नीतीश कुमार की दूसरी पारी और राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की बढ़ती ताकत के परिपेक्ष्य में घटनाओं को समझना होगा. जैसे–जैसे राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी छाते गए और भाजपा में उनका दबदबा बढ़ता गया वैसे–वैसे ही बिहार में भाजपा व जदयू के संबंधों में खटास आती गई. बिहार में रामेश्वर चौरसिया, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और सी पी ठाकुर नरेंद्र मोदी के स्वर बने और मौका दर मौका नीतीश कुमार और गठबंधन को लेकर बयान देते रहे. अखबार की कतरन को खंगाल देने पर भी नीतीश कुमार की पहली पारी में भाजपा नेताओं द्वारा इस तरह के तीखे बयान खोजने पर भी नहीं मिलेंगे. गौरतलब है कि उस कालखंड में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय भूमिका के लिए पेश नहीं किया था. लेकिन 2010 के ठीक पहले से हालात बदलने लगे. नीतीश कुमार ने जब दूसरी बार सरकार बनाई तो सरकारी फैसला लेने के स्तर पर उन्हें पहले जैसी सहूलियत नहीं मिल रही थी. भाजपा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, फारबिसगंज गोलीकांड और भूमि सुधार कानून जैसे मसलों पर नीतीश कुमार को फ्री हैंड नहीं दिया. इसी तरह सरकारी अधिकारियों के तबादले और कुछ सरकारी फैसलों पर भी भाजपा ने नाराजगी दिखानी शुरू कर दी. जैसे–जैसे नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता गया वैसे–वैसे बिहार में गठबंधन की गांठ ढीली पड़ती चली गई. बिहार प्रदेश भाजपा को यह एहसास हो गया कि अब नरेंद्र मोदी का सितारा चमकने से कोई नहीं रोक सकता इसलिए जदयू से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझी गई. भाजपा की राष्ट्रीय राजनति में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिससे लगने लगा कि अब तो नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा. इसलिए गठबंधन टूटा और बिहार भाजपा ने हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया. नेताओं ने एक दूसरे के प्रति सारे गिले शिकवे भूलाकर नरेंद्र मोदी को देखना शुरू कर दिया और इसका परिणाम 27 अक्टूबर को गांधी मैदान में देखने को मिला. बम के धमाकों के बीच लोगों का जनसैलाब नरेंद्र मोदी को सुन रहा था और भारत माता की जय के नारों से पूरा गांधी मैदान गूंज रहा था. गूंज ऐसी की बम के धमाकों की आवाज उसके सामने कमजोर पड़ रही थी. बस उसी दृश्य ने जदयू नेताओं को अंदर से राजनीतिक तौर पर बेहद डरा दिया. सत्ता के मद में चूर जदयू नेताओं को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की हवा बनावटी है और जमीन पर भाजपा की ताकत बेहद कमजोर है. रैली में भीड़ आएगी सभी को अनुमान था, लेकिन इतनी ज्यादा और समर्पित भीड़ आएगी इसका अनुमान लगाने में जदयू के नेता गच्चा खा गए. कल तक पानी पी–पी कर नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले शिवानंद तिवारी राजगीर में कहने लगे कि नरेंद्र मोदी की ताकत को कम करके आंकना बड़ी भूल होगी. श्री तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी साधारण घर से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं इसलिए उनकी इस बात के लिए तो प्रशंसा करनी ही होगी. जदयू के मंच पर नरेंद्र मोदी की तारीफ सुनकर कुछ लोगों को अटपटा लगा तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया पर शिवानंद नहीं माने और सीधे नीतीश कुमार को कहने लगे कि आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आप तक सच नहीं पहुंचने दे रहे हैं. बड़ा गोल करना है तो अच्छी टीम बनानी होगी लेकिन दुर्भाग्य से टीम में ऐसे लोग हैं जिन्हें राजनीति का ककरहा भी नहीं आता. वह यही नहीं रूके, कहने लगे कि मैं राज्यसभा में पार्टी का नेता हूं पर सदन की कमेटियों में मनोननयन की जानकारी मुझे बुलेटिन से मिलती है. शिवानंद तिवारी जब पटना आए तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में जाउंगा इसकी कल्पना मत कीजिए. भाजपा मेरे लिए नरक के समान है. मैंने जो बात कही वह पार्टी हित में है. नेतृत्व से मेरा कोई विरोध नहीं है. मैंने तो बस पार्टी और नेताओं को आने वाली चुनौती के प्रति अगाह किया है. ठीक इसी तरह नरेंद्र सिंह कहते हैं कि राजगीर में मैंने जो कुछ कहा वह मेरे परिवार के अंदर की बात है. पार्टी नेतृत्व के प्रति मेरी आस्था है. गौरतलब है कि राजगीर में श्री सिंह ने कहा था कि अफसरशाही के चलते जदयू के कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं. शिवानंद और नरेंद्र सिंह ने तो अपनी सफाई दे दी पर जानकार बताते हैं कि हुंकार रैली की सफलता ने जदयू को अंदर से हिला कर रख दिया है. शरद यादव भी काफी परेशान हैं. जदयू के कई नेताओं के साथ उन्होंने दिल्ली में गहन मंत्रणा की. इसमें बिहार के कई मंत्री भी शामिल थे. मौटे तौर पर तय हुआ कि किसी भी कीमत में कांग्रेस के साथ गठबंधन का विरोध किया जाएगा. शरद यादव नीतीश कुमार को यह बताने का प्रयास कई बार कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ तालमेल आत्मघाती कदम होगा. मंहगाई और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस आम जनता के निशाने पर तो है ही साथ ही शरद यादव की कांग्रेस विरोध की राजनीति भी उन्हें बार–बार इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को यह फैसला लेने से रोका जाए. लेकिन नीतीश कुमार के भी अपने तर्क हैं और राजनीतिक मजबूरियां भी. भाजपा का साथ छूटने के बाद केंद्र की राजनीति में दखल बनाए रखने के लिए उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए. त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति नीतीश कुमार के लिए फायदे का सौदा हो सकती है. लेकिन सबसे अधिक जरूरी है बिहार में चुनावी समीकरण. खासकर मुसलमानों का वोट पाने के लिए उन्हें बिहार में कांग्रेस का साथ चाहिए ही चाहिए. यही वजह है कि शरद यादव और नीतीश कुमार इन दिनों दो धारा में सोच रहे हैं. शरद यादव पार्टी में इतना आंतरिक दबाव बना देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले सकें. भाजपा ने जो चुनौती पेश कर दी है उससे जदयू के रणनीतिकार घबराए हुए हैं. अगर अगड़ी जातियों के साथ कुछ पिछड़ी जातियों का भी ध्रवीकरण भाजपा के पक्ष में हो गया तो फिर कई सांसदों व विधायकों का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए नरेंद्र सिंह ने राजगीर में एक बात कही कि अपने पुराने साथियों को एक बार फिर साथ लिया जाए. लेकिन नीतीश कुमार के रवैये से लगता है कि वे संकल्प ले चुके हैं कि परिणाम चाहे जो हो वह अपने कदम वापस नहीं लेंगे. राजनीतिक हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की इस जिद के कारण जदयू को कहीं बड़ी कीमत न चुकानी पड़ जाए. ■

नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार ने जदयू–भाजपा की 17 साल पुरानी दोस्ती की बलि चढ़ा दी. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतने भोले हैं कि राजनीतिक सच्चाइयों को नहीं समझ कर सपनों का महल बनाने के लिए अपना बना बनाया आशियाना तोड़ कर रख देंगे. गठबंधन तोड़ने के फैसले के कारणों में प्रधानमंत्री बनने का विकल्प एक छोटा सच हो सकता है लेकिन यह पूरा सच नहीं है जैसी की आमधारणा बनती जा रही है. इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें बिहार में नीतीश कुमार की दूसरी पारी और राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की बढ़ती ताकत के परिपेक्ष्य में घटनाओं को समझना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

सीमांचल के मुसलमानों पर भाजपा की नज़र

नीरज कुमार सिंह

17 साल पुराने एनडीए गठबंधन टूटने के बाद भाजपा की सक्रियता सीमांचल में बढ़ गई है. भाजपा के निशाने पर जहां पहले कांग्रेस राजद व लोजपा थी अब जदयू भी उसके निशाने पर आ गई है. जहां सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, राजद, लोजपा और जदयू अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में लाने का अथक प्रयास कर रहे हैं वहीं भाजपा ने भी सेक्यूलरिज्म का ढिंढोरा पीटने वाले दलों से मुसलमानों को परहेज करने और ठगे जाने की बात बताकर अपनी ओर लाने के प्रयास में लगी हुई है.

गठबंधन में रहते हुए भी नीतीश ने यहां के मुसलमानों को लुभाने का एक भी मौका जाने नहीं दिया. इसी क्रम में उन्होंने विधायक नौशाद के घर जाकर पटुआ साग खाया, विधायक तौसीफ आलम की शादी में सेहरा बांधने भी पहुंचे, एएमयू की शाखा के लिए जमीन भी उपलब्ध कराए, किशनगंज में मुस्लिम जिलाधिकारी को नियुक्त किया, कटिहार से शिवदीप लांडे जैसे तेजतर्रार आरक्षी अधीक्षक को हटाकर मुस्लिम आरक्षी अधीक्षक दिया और पूर्णिया में बंग्लाभाषी शेरशाहबादी मुस्लिमों का सम्मेलन तक कराया. कुल मिलाकर कहें तो वे मुसलमानों को रिझाने के एक भी मौके को जाने नहीं दिया. इसका फायदा भी उन्हें मिला. विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान बिहार के चारों कांग्रेसी विधायक उनके पक्ष में मतदान करने पहुंचे जिसमें दो विधायक अफाक आलम और तौसीफ आलम सीमांचल के ही थे. सीमांचल के वर्त्तमान राजनीतिक परिदृश्य को जानने के पहले उसकी राजनीतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि को खंगालना जरूरी है. 1952 से लेकर 1967 तक सीमांचल का इलाका कांग्रेस के वर्चस्व में था. 23 विधानसभा क्षेत्रों में से 21 पर कांग्रेस का कब्जा था. बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी सीमांचल के किशनगंज में 70 प्रतिशत, अररिया में 40 प्रतिशत, कटिहार में 35 प्रतिशत और पूर्णिया में 30 प्रतिशत बसती है. लालू यादव के प्रादुर्भाव के बाद सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा तबका कांग्रेस से छिटक कर राजद से जुड़ गया दूसरी तरफ सीमांचल में भाजपा भी मजबूत हुई. वर्ष 1999 में किशनगंज समेत सीमांचल की चारों लोकसभा सीटों पर भगवा झंडा लहराया और सैयद शाहनवाज हुसैन भाजपा के सांसद चुने गए. वर्ष 2004 में किशनगंज सीट राजद के कब्जे में चली गई और तस्लीमउद्दीन यहां से सांसद बने. वर्ष 2009 में जदयू ने गठबंधन के तहत किशनगंज सीट भाजपा से छीन ली और जदयू से महमूद अशरफ चुनाव लड़े लेकिन नीतीश लहर में भी वे चुनाव हार गए. यहां से सुरजापुरी मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के चलते मौलाना असरारुल हक कासमी कांग्रेस से चुनाव जीते. सीमांचल में सुरजापुरी, शेरशाहबादी और कुलहिया मुसलमानों की आबादी बसती है जिसमें सुरजापुरी की सबसे अधिक संख्या 7 लाख के लगभग किशनगंज में बसती है. वर्त्तमान में किशनगंज की राजनीति सुरजापुरी बनाम अन्य मुसलमानों के बीच चल रही है. नीतीश जहां सीमांचल में मुस्लिम मतों के सहारे जदयू का भविष्य तलाशने में जुटे हैं वहीं भाजपा भी सीमांचल के चारों जिलों में प्रखण्ड से जिला स्तर तक अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा मुस्लिमों का सम्मेलन करा रही है. किशनगंज में जदयू की नजर दूसरे दलों के नेताओं जैसे राजद के अख्तरुल ईमान, कांग्रेस के तौसीफ और जावेद आजाद जैसे नेताओं पर टिकी है. सूत्र बताते हैं कि बागी उम्मीदवार के रूप में जदयू इन्हें भी टिकट दे सकती है. ये सभी सुरजापुरी बिरादरी से ही आते हैं. मौलाना साहब भी एक बार फिर टिकट पाने की जुगत में हैं, लेकिन किशनगंज की जनता उनसे नाराज चल रही है. इतना तो तय माना जा रहा है कि लालू यादव के जेल जाने के बाद सीमांचल में राजद कमजोर हुई है ऐसे में मुस्लिम मतदाता दूसरे दलों की ओर रुख करेंगे जिसको लेकर भाजपा फूंक–फूंक कर कदम रख रही है.

किशनगंज से भाजपा विधान पार्षद दिलीप जायसवाल टिकट के प्रबल दावेदार हैं. मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा व्यवस्था के चलते जहां जायसवाल हिन्दू मतदाताओं में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं वहीं मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े तबके का समर्थन भी उन्हें मिल सकता है. पूर्व विधायक सिकंदर सिंह और भाजपा उद्योग मंच के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन भी टिकट की आस लगाए क्षेत्र और अल्पसंख्यकों के बीच दौरा कर रहे हैं. नजमा हैपतुल्ला या शाहनवाज हुसैन भी दांव खेल सकते हैं. वर्त्तमान परिदृश्य में सीमांचल में भाजपा का पलड़ा आज भी भारी नजर आ रहा है. जिन क्षेत्रों में पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू ने कब्जा जमाया था वहां गठबंधन के चलते भाजपा के कैडर वोटरों ने जदयू का साथ दिया था जिनमें मनिहारी, रूपौली और धमदाहा प्रमुख हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी त्रासदी के समय जो राहत पैकेज नरेन्द्र मोदी की तरफ से भेजा गया था और जिसे नीतीश कुमार ने लौटा दिया था उस पैकेज को पूर्णिया के सांसद उदय सिंह के माध्यम से पीड़ितों के बीच बंटवाया गया. वहीं नरेन्द्र मोदी ने नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए उदय सिंह के भारी–भरकम व्यक्तित्व को देखते हुए ऐतिहासिक वेदना रैली करवाई जिससे कि नीतीश कुमार का कद छोटा हो सके. आनेवाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस, जदयू, राजद मुसलमानों की गोलबंदी में लगे हुए हैं वहीं भाजपा के भी नेता मुसलमानों के बीच भाजपा की अच्छाइयों को समझा रहे हैं और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा अबतक अल्पसंख्यकों के साथ हुए ठगी को समझा रहे हैं. उदय सिंह द्वारा हाल में सीमांचल के मुसलमानों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भाजपा शासित राज्यों में एक भी दंगा नहीं होना भाजपा की उपलब्धि बताया गया.

उनका कहना था कि आज सीमांचल के मुसलमान गुजरात के मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं और वही बच्चे यहां आकर वहां के मदरसों की प्रशंसा कर रहे हैं. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा ही हज करने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए कोटा और सब्सिडी की राशि को बढ़ाई गई. इस सम्मेलन में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष तौसीफ आलम, लल्लू मुखिया, पूर्व जिप सदस्य जुबेर आलम, अल्पसंख्यक मोर्चा के मो. दानिश ने मुस्लिम अवाम से भाजपा से जुड़ने की बात कही. दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद शाहनवाज हुसैन के भाई सरफराज हुसैन ने भाजपा क्रीड़ा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष वरूण सिंह के साथ पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यकों के बीच दौरा किया. सीमांचल के मुसलमानों को किस हद तक भाजपा अपने पाले में ला पाएगी यह आने वाला समय ही बतायेगा. यहां का मतदाता आखिर किसे अपना मत देकर लोकसभा तक पहुंचाएगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

नक्सलियों का सेफजोन बना चम्पारण

इन्तेजारुल हक

बापू की कर्मभूमि चम्पारण व इसके आस-पास का इलाका इन दिनों नक्सलियों की चारागाह बना हुआ है. ऐसा देखा गया है कि हाल के दिनों में इलाके में इनकी सक्रियता भी बढ़ी है और यह प्रशासन के लिये गंभीर चुनौती है. नक्सली अपनी सुनियोजित कार्य योजना के तहत सरकार एवं सरकारी तंत्र के खिलाफ गांव की मासूम जनता को हिंसात्मक संघर्ष का पाठ पढ़ा रहे हैं. जानकार बताते हैं कि पूर्वी चम्पारण जिला का सिकराहना एवं पकड़ियाल अनुमंडल के दर्जन भर गांवों के साथ भारत-नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र इनका सुरक्षित गढ़ बन चुका है. नक्सली यहां बिना किसी खौफ के दिन में ही बैठक कर अपनी कार्ययोजना तैयार करते हैं, और उनकी योजनाएं धरातल पर दिखाई भी पड़ती हैं. समय-समय पर घटनाओं को अंजाम देते हुए नक्सली अपनी मजबूत एपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं. नक्सली बंदी का इतना व्यापक असर रहता है कि दिन में ही सड़कों पर सन्नाटे के साथ लोगों के चेहरे पर आशंकाएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं.

पूर्वी चम्पारण के एसपी विनय कुमार के सार्थक प्रयास व अभियान एएसपी संजय कुमार सिंह की तैनाती के बाद कई महत्वपूर्ण नक्सली गिरफ्तारियां भी हुई हैं और दो वर्षों में करीब आठ दर्जन माओवादियों एवं एरिया कमाण्डरों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस दौरान भारी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटकों की बरामदगी भी हुई है. बावजूद इसके इनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं. वे समय-समय पर सरकारी तंत्र के समक्ष नई-नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं. पिछले वर्ष अपने गिरफ्तार कमांडर की रिहाई की मांग को लेकर मेहसी स्टेशन पर इनके द्धारा मचाया गया उत्पात व समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पोस्टर व बैनर तथा बीते दिनों पूर्वी चम्पारण जिले के कुण्डवा चैनपुर थाना क्षेत्र के गोरगांवा गांव से जहीर मदारी, नन्हक पासवान, अरूण ठाकुर व विद्या महतो तथा घोड़ासहन थाना क्षेत्र के नयका टोला बंगरी गांव निवासी रामएकवाल भगत व ललिता प्रसाद तथा ललुवा गांव के इस्लाम अंसारी की हुई गिरफ्तारी और बरामद भारी मात्रा में कारतुस व अवैध हथियार ने साफ कर दिया है कि इनकी पकड़ चम्पारण में काफी मजबूत हो गई है. नक्सली गांव की मासूम व गरीब जनता को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं. गिरफ्तार नक्सलियों से पुछताछ के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक मधुबन काण्ड जैसी घटनाओं की पुर्नावृति से इंकार नहीं किया जा सकता. पूर्वी चम्पारण जिला के पताही, पकड़ियाल, मधुबन, चिरैया, तेतरिया, राजेपुर व ढ़ाका अंतर्गत सिकरहना अनुमण्डल के ढ़ाका आदि प्रखण्डों के कई पंचायतों में नक्सलियों की लगातार बढ़ रही सक्रियता से जहां आम जनता व व्यवसायी वर्ग दहशत में है वहीं दूसरी तरफ सरकार व पुलिस प्रशासन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार बताती है. बहुत से पुलिस पदाधिकारी इनके साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए सामाजिक असमानता और नाइंसाफी को इस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बताते हैं. पुलिस कप्तान विनय कुमार व अभियान एएसपी संजय सिंह भी नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ इनसे समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील करते हैं और कहते हैं कि सरकार व विभाग की मंशा के अनुकू ल आत्मसमपर्ण करनेवाले नक्सलियों की बेहतरी के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा.

गिरफ्तार नक्सलियों की सूची

नन्दु राय, विनय कुमार राम, वागेन्द्र प्रसाद, मुम्ताज, सुधीर कुमार महतो, दिलिप साह उर्फ मयंक साह, बली राम सहनी उर्फ नेता जी, बसंत कुअर उर्फ उपेन्द्र कुंअर, मनोज राम उर्फ मनोज जी, अमलेशसाह , सुरेश सहनी उर्फ सुजीत, रामनागर ठाकुर, संतोष प्रसाद, सुरेश राम, धननजय झा उर्फ झा जी, दिलिप कुमार साह, गनौर पासवान, भांकर दास उर्फ भगवान दास, सिकेन्द्र राय, विजय ठाकुर उर्फ विजय भगत, राजकिशोर सहनी, हरदेव सहनी, राजदेव सहनी, ज्योतिक सहनी, सिकेन्द्र सहनी, संतु पासवान, जमादार सहनी, रूदल सहनी, देवनाथ माझी उर्फ संजय माझी, बृजेश कुमार सिंह उर्फ प्रिंस, कंचन कुमारी, विपाशा कुमारी, नन्हक पासवान, हरि पासवान, अशोक कुमार, अवधकिशोर साह, मुन्ना राम, मो. इसराफिल, प्रभु सहनी, इन्द्रदेव भगत, मो. कुर्बान, रामनरेश पासवान, मनोज अग्रवाल उर्फ अग्रवाल जी, भामसुल, नागेन्द्र राम उर्फ जयलाल राम, नथुनी साह, राजकुमार प्रसाद, मुशहर सहनी उर्फ धनपत सहनी, सुभाष प्रसाद, सलेन्दर महतो, भरत सहनी, लालबाबू सहनी, श्यामबाबू सहनी, जयलाल माझी, शिवपूजन राय, रामकिशोर राम, मुनचुन साह, विगन दास, कैलाश प्रसाद, सलेन्द्र महतो, मुन्ना यादव उर्फ अशोक कुमार, विरेन्द्र प्रसाद, राजमंगल भगत, दुर्गा प्रसाद भगत, भारती सिंह, रंजित सिंह, हरेन्द्र साह, मुन्ना साह, मो. अली, नरेश सहनी, नवलेश, रमजान मिंया, रामायण ठाकुर, सुहाग पासवान. ■

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वी चम्पारण के जिलावासियों को दीपावली व लोक आस्था का महान पर्व छठ की शुभकामनाएं। यह दोनो त्योहार सबों के जीवन में खुशिया लाए यही ईश्वर से प्रार्थना है।
निवेदक
संगीता सिन्हा (चितांष)
अध्यक्ष
बाल कल्याण समिति सह जिला उपाध्यक्ष
भाजपा महिला प्रकोष्ठ,पूर्वी चम्पारण

पूर्वी चम्पारण के समस्त चिकित्सकों,जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों व आम जनता को दीपावली व लोक आस्था का पर्व छठ की
डॉ. सुनील कुमार
हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक
एमडी (मेडिसिन)
जिस्ट्रेशन नम्बर–37363 बिहार
क्लिनिक-नगर थाना के सामने मोतिहारी,पूर्वी चम्पारण

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
MOULDED FURNITURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

सुपौल में राजद की मोर्चाबंदी

जुबैर आलम

आम चुनाव में अभी चार–पांच महीने का समय है. लेकिन मुख्य रूप से भाजपा, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल ने बैठकों–सम्मेलनों के जरिये कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिया गया है. गठबंधन टूटने के बाद से सुपौल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ज्यादा ही सक्रिय हो गई है. साथ ही जदयू भी विधानसभा सम्मेलन के बहाने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ही जुटी हुई है. वहीं जिले में मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस भी जाग गई है.

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल में हैं. राजद नेता इसे विरोधियों की साजिश बताते फिर रहे हैं. साथ ही उनकी कोशिश है पार्टी को इस विपदा की घड़ी में और भी मजबूत करना है. राजद यह साफ–साफ कहती है कि लालू प्रसाद यादव हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और जेल के भीतर से ही पार्टी को चलाने का काम करेंगे. 20 अक्टूबर को राजद ने निर्मली विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया. उक्त सम्मेलन का उद्घाटन राजद के कमिश्नरी प्रभारी, पूर्व मंत्री अशोक सिंह ने किया. उन्होंने कहा कि लालूजी को साजिश के तहत फंसाया गया है. नीतीश कुमार राजनीति के नटवर लाल हैं, बिहार की जनता ने बिहार की बेहतरी के लिए जनादेश दिया था लेकिन अपने सात वर्षों से अधिक के शासन में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. जबकि प्रदेश सचिव विजय कुमार यादव ने कहा कि नीतीश की सरकार घोषणाओं की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है. आज शिक्षक पढ़ाने के जगह खिचड़ी बनाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव पूर्व जो सर्वेक्षण रिर्पोट आई उसमें बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभर रही है, यही कारण सत्ता दल को खलने लगा और साजिश के तहत लालू जी को जेल भेज दिया. लेकिन इससे राजद और भी मजबूत हुई है. वहीं प्रदेश महासचिव दिनेश प्रसाद यादव ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश सरकार भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है. जबकि जिला पार्षद पति विन्दी सादा ने कहा कि सामाजिक न्याय के मसीहा लालू प्रसाद यादव ने हम जैसे छोटे लोगों के मुंह में बोल देने का काम किया है. सम्मेलन को जिला युवा अध्यक्ष अजय कुमार अजनबी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि लालू जी को एक साजिश के तहत फंसाया गया है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की जरूरत है. कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष यदुवंश यादव ने की. उन्होंने कहा कि हमारे नेता जेल में है. लेकिन आज हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव हैं.

यादव ने सरकार को खरी–खोटी सुनाई. कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक प्रकाश यादव, मो. शकील, राजू शर्मा, राजकुमार, निर्मली विधानसभा से भावी उम्मीदवार मधु यादव आदि लोगों का अहम योगदान रहा. मौके पर पूर्व मंत्री कुम्भनारायण सरदार, पूर्व विधायक उपेन्द्र हाजरा, प्रदेश महासचिव मो. जफर आलम, पूर्व प्रमुख भूपनारायण यादव, मोतिउर्रहमान, अधिवक्ता रामनाथ मंडल, डा. रामप्रसाद यादव, सायरा खातून के अलावे सियाराम यादव, बमभोला सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

समय पर करें भोजन

डॉ. संजीव चौधरी
एमबीबीएस (पटना)

गैस्ट्रिक पेट का एक ऐसा रोग है जिससे शायद ही कोई बचा हो बाजार में! गैस्ट्रिक की दवा के नाम से कई दवाएं बिक रही हैं इसी पर हमारी बातचीत हुई डॉ.संजीव कुमार चौधरी से जो किशनगंज के जाने माने सर्जन हैं। उनका कहना है कि आजकल लोगों का आहार अनियमित हो गया है, ना भोजन का निश्चित समय है और ना सोने का। मानसिक परेशानियां भी बढ़ गई हैं। चाय कॉफी धूम्रपान का प्रचलन बढ़ गया है लोगों को जब भूख लगती है तो एक कप चाय या कॉफी पीकर भूख को दबा देते हैं लोग मिर्च मसाले तेल का प्रयोग भी अधिक करने लगे हैं अन्न फल और सब्जियों के उत्पादन में कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया है जिसका दुष्परिणाम हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। इस रोग में भूख खुलकर नहीं लगती और पेट व पीठ में हल्का–हल्का दर्द रहता है। गैस्ट्रिक रोग से बचने के लिए भोजन नियमित समय पर करना चाहिए। रात का भोजन सोने से एक घंटे पहले करें तथा भोजन के तुरंत पहले अथवा तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के बीच में थोड़ा जल पिया जा सकता है साथ ही चाय कॉफी शराब सिगरेट पान तंबाकू लाल मिर्च अधिक तैलीय व मिर्च मसालेदार तथा फ्रिज के पानी का सेवन नहीं करना चाहिए।

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma
प्रस्तुति: कुमारी अमृता

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा। रिचा स्वामी, राजस्थान

उत्तर : आप CINERARIA MARITIMA REPL दिन में 2 बार दोनों आँखों में 2-2 बूँद डालें। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चालू रखें। आपको स्थायी निदान मिलेगा। क्योंकि यह बाजार में अन्य आईड्रॉप से अधिक प्रभावशाली व परिष्कृत है।

प्रश्न : डॉ साहब मेरी उम्र 23 वर्ष है, गलत आदतों के कारण अत्यधिक कमजोरी है, इच्छा मात्र से ही असंयमित हो जाता हूँ। मधुरेन्द्र, देहरादून

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी आयु 33 वर्ष है एवं मैं विवाहित हूँ पेशाब में धातक्षीणता की शिकायत है। जिससे मैं कफी चिंतित रहता हूँ। कोई अच्छा और हानिरहित उपाए बतायें। आविद, फिरोजाबाद।

उत्तर : आप निराशा मन से निकाल दें और विगोरा 5000 की 6 शीशी का कोर्स करें एवं विगोरा ऑयल से मालिश करें। यह होमियोपैथिक लिक्यूड दवा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : मेरी उम्र 54 साल है, मैं बाबासीर का मरीज हूँ, पिछले कुछ दिनों से इच्छा होते हुए भी समर्थ नहीं हो पाता हूँ। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर

उत्तर : सुधीर जी! बाबासीर की रोकथाम के लिये आप पाइलेलैक्स लिफलेट के निर्देशानुसार इस्तेमाल करें और विगोरा 5x का 6 शीशी का कोर्स करें और सुबह-शाम हाई पावर मुसली आयल से दो महीने तक लगातार मालिश करें। आपको लाभ होगा।

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 68 वर्ष है। शरीर से बिल्कूल स्वस्थ्य हूँ, लेकिन इच्छाशक्ति के रहते हुये भी शरीर साथ नहीं देता। कोई आयुर्वेदिक तात्कालिक समाधान बतायें। जगदीश प्रसाद, झरिया।

उत्तर : आप सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आयुर्वेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : पिछले 7-8 वर्षों से मेरे घुटनों और कमर में बहुत दर्द रहता है। दर्द की वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो गया है कोई आयुर्वेदिक उपचार बतायें। देवंती सिंह, दिल्ली

उत्तर : आप ऑर्थोविट कैप्सूल सुबह-शाम एक कैप्सूल लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालिश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 24 वर्ष है। अविकसित सीना के कारण हीन-भाव से ग्रसित हूँ। आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : सीना का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।

प्रश्न : बालों के निरन्तर झड़ते रहने के कारण सिर पर गंजापन हो गया है, मैं इस समस्या से बहुत चिन्तित हूँ, उपाय बतायें । उपेन्द्र सिंह, कानपुर

उत्तर : बालों के झड़ने, टुटने से बचने के लिए आप केशवर्धक तेल का नियमित इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बाल झड़ना एवं टूटना तत्काल समाप्त हो जायेगा।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्ता आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051

किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।

REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

जमुई जिला परिषद की काया पर सियासत की छाया

राजेश/मनोज

जमुई में जिला परिषद अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर पिछले एक महीने से जिले की राजनीति में उठापटक जारी है. सत्ता के दो ताकतवर ध्रुवों के बीच जिप अध्यक्ष पद को लेकर शीतयुद्ध की स्थिति बनी हुई है. 20 सदस्यीय जिला परिषद में यदि सदस्यों का जातिगत आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा 6 सदस्य यादव जाति से हैं, जबकि अनुसूचित जाति से 4 तथा अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य है. अन्य पिछड़ी जातियों से 6 तथा सामान्य से तीन सदस्य हैं. लेकिन जातियों का यह आंकड़ा अध्यक्ष पद के समीकरण को बनाने–बिगाड़ने में सक्षम नहीं है.

यहां अध्यक्ष पद की कुर्सी सदस्यों के बहुमत से हासिल होगी. अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार जिप उपाध्यक्ष राजेन्द्र यादव पर दांव खेलकर एक पक्ष ने यादव जाति को राजनीतिक दृष्टि से करीब लाने की कोशिश की है. उपाध्यक्ष पद पर बामदह के विजय कान्त बेसरा को प्रोजेक्ट किया गया है. वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव रावत के चार और समर्थक सदस्य इस रणनीति में जुटे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए यदि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं हो पाता है तो वे अन्तिम क्षण में तीसरे मोर्चे को समर्थन करेंगे अथवा नहीं. हालांकि इस मामले में ब्रह्मदेव समर्थकों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है. इस जोड़–तोड़ की राजनीति में विकास प्रसाद सिंह यकीन नहीं रखते, उनका मानना है कि जिला परिषद की गरिमा को सियासत की छाया से दूर रखा जाए ताकि सदस्यों द्वारा अपने विवेक से अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाए. विकास ने बताया कि अध्यक्ष पद के दावेदारों में वे सबसे बेहतर करने का माद्दा रखते हैं. जानकार बताते हैं कि कोई लो प्रोफाइल उम्मीदवार भी इस लड़ाई का लाभ उठाकर किला फतह कर सकता है. अपना चेहरा बचाने के लिए राजनीति के बड़े खिलाड़ी अंतिम मौके पर इस तरह का दांव खेल सकते हैं. बहरहाल जिप अध्यक्ष की लड़ाई का खेल काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी में राजद ने लगाया जोर

उद्घाटन करते राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य

सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ता

वाल्मीकि कुमार

2014 के लोकसभा चुनाव का समय करीब आने के साथ ही राजनीतिक तापमान बढना शुरू हो गया है. भय, भूख, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार समेत दर्जनों अन्य मसले इन दिनों राजनीतिक मंच पर भाषण के केंद्र बने हैं. इसके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला मामले में जेल जाने को राजद ने मुख्य मुद्दा बनाया है. राजद इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा व जदयू को जिम्मेदार ठहराती है. कांग्रेस को भी बड़ी ही चतुराई से इस मामले में दोषी करार दिया जा रहा है.

तकरीबन 17 साल तक एक थाली में राजनीतिक रोटी तोड़ने वाली भाजपा–जदयू के बीच गठबंधन टूटने के बाद बढ़ी खटास ने दोनों दल को आमने–सामने कर दिया है. वहीं राजद ने भी अब दोनों ही दलों को अपने निशाने पर ले लिया है. सीतामढ़ी में भाजपा व जदयू के सम्मेलनों में जहां एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए सबक सिखाने का पाठ पार्टी कार्यकर्ताओं को पढ़ाया गया, वहीं अब राजद ने भी लालू प्रसाद के जेल की दास्तान को कार्यकर्ताओं के लिए एक सबक के रूप में परोसना शुरू कर दिया है. अंतर केवल इतना है कि भाजपा जदयू पर तो जदयू ने भाजपा पर आरोप की बौछार की, लेकिन राजद ने दोनों से दो–दो हाथ करने का मन बना लिया है. पिछले दिनों सीतामढी शहर के लक्ष्मी किशोरी उच्च विद्यालय के सभागार में जिला राजद के तत्वावधान में आयोजित पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में राजद नेता व कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली. कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को एक साजिश के तहज जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है. अगर बिहार में नीतीश कुमार के स्थान पर लालू प्रसाद मुख्यमंत्री होते तो शायद गुजरात से आकर भाजपा के नरेंद्र भाई मोदी हुंकार रैली पटना में नहीं कर पाते. उन्हे भी लालकृष्ण आडवाणी की तरह लालू प्रसाद जेल में डालने से परहेज नहीं करते. राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि राजनीतिक कुचक्र का नतीजा आज सभी के सामने है. अब पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे चुनौती के रुप में स्वीकार किया है. पार्टी टूटने का सपना देखने वालों को सोचना चाहिए कि राजद लंबी यात्रा का उम्मीद रखता है. इस दौरान कहीं समतल तो कहीं खाई से पाला पड़ना स्वाभाविक है. सम्मेलन के दौरान उपाध्यक्ष श्री सिंह ने चुनावी शतरंज का पाशा फेंकने से भी परहेज नहीं किया. कहा कि नियोजित शिक्षक, आशा, प्रेरक, न्याय मित्र समेत अन्य के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की समस्या के निदान के लिए भी राजद लड़ाई शुरू करेगी. राजनीतिक दांव–पेच के कुशल खिलाड़ी रहे राजद के प्रदेश अध्यक्ष डा. रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि राजद जाति नहीं जमात की पार्टी है. अगर जाति की पार्टी होती तो शायद वे स्वयं राजद के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते. जेल की सलाखों में कैद पार्टी सुप्रीमों लालू प्रसाद के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि जेल में भी श्री प्रसाद का मनोबल मजबूत है. कारण कि लालू प्रसाद की नजर में राजद एक पार्टी नहीं बल्कि फौज है. श्री प्रसाद ने मुसलमानों को हिंदुओं के सहोदर भाई के रूप में सम्मान देने का काम किया है. जिसके हाथ लालटेन, वही जाए पार्लियामेंट का नारा देते हुए कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद के अपमान का बदला लेने की अपील की. जिलाध्यक्ष मो शफीक खां की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में पूर्व सांसद सीताराम यादव, रघुनाथ झा, मो. अनवारुल हक, रामश्रेष्ठ खिरहर, पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय, वीणा शाही, पूर्व विधायक जय नंदन प्रसाद यादव, संजय गुप्ता, रंधीर कुमार सिंह, राम अशीष यादव, पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता मो इकबाल शमी, डॉ हरेंद्र कुमार, अंगेश कुमार सिंह, मनोज कुमार, शिव शंकर यादव, तारकेश्वर यादव, अलाउद्दीन बिस्मिल, गणेश गुप्ता, संजय कुमार पप्पू, हरि ओम शरण नारायण, चंद्रजीत प्रसाद यादव, दिलीप राय, नवीन सिंह व वीरेंद्र यादव समेत तकरीबन 250 नेता व कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए. कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जो इत्साह का आलम रहा, अगर ऐसा ही रह गया तो आने वाले दिनों में सीतामढ़ी में राजद की स्थिति बेहतर माना जा सकता है.

हालांकि सम्मेलन के क्रम में पूर्व की तुलना में कार्यकर्ताओं ने नेता पर अपना पलड़ा भारी रखने में कुछ हद तक सफलता भी पाई. यही कारण था कि संचालन की कमान थाम रहे जिलाध्यक्ष मो शफीक खां के आग्रह के बाद भी कार्यकर्ता अपनी बात पूरी होने तक माइक छोडने को तैयार नहीं हुए. कुछ समय के लिए हालात ऐसा बने कि मंच से लेकर हॉल तक आक्रोश की हवा भी तैरने लगी थी. परंतु पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं की सूझ–बूझ ने संभावित व्यवधान को किनारा कर दिया. कुल मिला कर राजद फिलहाल लालू के जेल गाथा की बदौलत पार्टी को पुराने रुतवा में लाने का हर संभव प्रयास कर रही है. अब देखना है कि चुनावी वर्ष में टिकट को लेकर राजद नेता और कितने संयम व धैर्य रख पाते है. एक ही दल के एक ही स्थान से जहां कई–कई प्रत्याशी अघोषित रूप से अपनी तैयारी में लगे हैं. वहीं पार्टी आलाकमान एक स्थान से एक ही व्यक्ति को चुनावी समर में इतारेगा इसमें कोई संदेह नही है. ऐसे हालात में राजद नेता व कार्यकर्ता लालू प्रसाद के अपमान का बदला, भाजपा व जदयू से लेने के संकल्प पर अडिग रहते है अथवा चुनावी पैंतरा शुरू होगा आने वाला समय ही बतायेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

लक्ष्मणा नदी का अस्तित्व ख़तरे में

सीतामढ़ी वासियों का लक्ष्मणा नदी से भावनात्मक रिश्ता रहा है. जिले से होकर गुजरने वाली इस नदी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है. लेकिन अब यह नदी अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है. साल 2005 में नदी की बदतर स्थिती के बारे में विधानपरिसद में भी बात उठी थी. समय–समय पर स्थानीय लोगों और कुछ संस्थाओं के द्वारा इसे बचाने को लेकर आंदोलन भी किए जाते हैं. लेकिन अबतक लक्ष्मणा नदी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है. फिलहाल स्थानीय लोगों में इस बात की भी चिंता है कि वे अपने महापर्व छठ को कहां मनाएंगे. नदी की बदहाली को देखकर जिले वासियों में रोष है. यह तय माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लक्ष्मणा नदी की बदहाली मुख्य मुद्दा होगा.

आस्था, श्रद्धा व विश्वास की त्रिवेणी के रुप में सीतामढ़ी जिला से होकर प्रवाहित होने वाली पावन लक्ष्मणा नदी में अब नालों का दूषित पानी और कचरों का अंबार दिखता है. ऐसा भी नहीं है कि नदी के इस दुर्दशा से सरकारी अधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि अंजान हैं. लेकिन अबतक नदी के अस्तित्व की रक्षा को लेकर कोई भी प्रयास नहीं किया गया है. बीते वर्षो विधानसभा में रुन्नीसैदपुर की जदयू विधायक गुड्डी देवी व विधान परिषद के सत्र में विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद ने मामले को सदन में रखा था. तब राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री ने नदी की वर्तमान दशा को स्वीकारते हुए अंर्तराष्ट्रीय मामला बताया था. यह भी कहा था कि नेपाल को लेकर इस मामले पर अंर्तराष्ट्रीय जल प्लावन समिति में भी चर्चा की गयी है. इतने के बाद सरकार के विभागीय मंत्री से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन ने भी अब तक कोई पहल नहीं की. नतीजतन पिछले करीब पांच सालों से शहर के हजारों लोगों ने सूर्य उपासना का महापर्व छठ अपने–अपने घरों में ही करने को विवश हैं. जबकि कुछ लोग अब भी आस्था की खातिर नदी के प्रदूषित धारा में ही पर्व करते हैं.

प्रशासनिक सक्रियता का आलम है कि दुर्गा पूजा के मौके पर नदी के धारा की सफाई कुछ दूर तक करा कर खानापूर्ति कर दी जाती है. पूजा समितियों द्वारा स्थापित दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी नदी में किया जाता है. इस मौके पर भी अब कुछ समितियां अन्य तालाबों में प्रतिमा विसर्जित कराने लगी हैं. नदी की दुर्दशा से आहत होकर सर्वप्रथम वर्ष 2005 में लक्ष्मणा गंगा बचाओ अभियान के तहत सामाजिक संस्था लोक चेतना समिति ने आंदोलन का श्रीगणेश किया था. तब शहर के सभी वर्ग के लोगों ने डॉ वसंत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आंदोलन में सक्रिय भागीदारी देते हुए 20 सितंबर 06 को संपूर्ण बाजार बंद कर रोष का इजहार भी किया था. संस्था के तत्वावधान में लखनदेई पुल पर भव्य महाआरती का भी आयोजन किया गया था. बाद के दिनों में राजद नेत्री शाहिन परवीन ने भी चरणबद्ध आंदोलन कर सरकार व प्रशासन का ध्यान नदी की बदहाली की तरफ आकृष्ट कराने का प्रयास किया था. साथ ही समस्या निदान नहीं होने पर आत्मदाह तक की चेतावनी दी थी. तब के बाद नदी का मामला विभिन्न संगठनों के लिए राजनीति का केंद्र बनता गया. हाल के सालों में सामाजिक संगठन अमन परिषद के अलावा कई अन्य ने नदी की बदहाली दूर कराने को लेकर आंदोलन जारी रखा.

आंदोलनों की श्रृंखला के विस्तार ने स्थानीय प्रशासनिक महकमे को इतना सक्रिय कर दिया कि जैसे ही कोई आंदोलन शुरू होता है, प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी आकर आश्वासन देते गए और आंदोलनकारी अखबारों में अपनी खबर व फोटो देख कर चलता होते रहे. जब लगातार आश्वासनों के बाद भी नदी सफाई की दिशा में कारगर पहल शुरू नहीं हो सकी तब हाल के महीनों में संघर्ष यात्रा व आम आदमी पार्टी की ओर से भी लखनदेई पुल के समीप धरना व उपवास का आयोजन किया गया. संपन्न दुर्गा पूजा के मौके पर प्रशासनिक सक्रियता का अद्वितीय नजारा देखने को मिला.

नदी की धारा में गिरने वाली शहर के नाले के पानी को विसर्जन घाट से चंद कदम दूर अलग पाईप के माध्यम से गिराया जाना लगा. नदी में पानी की किल्लत को देखते हुए नदी किनारे बोरिंग करा कर पानी नदी में भरा जाने लगा जो शायद ही सूबे के किसी अन्य नदी को नसीब हुआ होगा. इतने के बाद भी लगा कि पानी विसर्जन के लायक नहीं हो पाएगा, तब नदी की धारा में बोरी में मिट्टी डालकर अस्थायी बांध तक बनाया गया. मीडिया ने भी नदी के इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया जिससे स्थानीय लोगों में मीडिया के प्रति भी गुस्सा देखने को मिल रहा है. सरकारी उदासीनता, प्रशासनिक उपेक्षा एवं जनप्रतिनिधियों की शिथिलता को इस बार लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है. जिले के किसानों को जहां सिंचाई के लिए नदी से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहीं आम लोगों को पर्व–त्योहारों के लिए इधर–इधर भटकने की विवशता बनी है.

आगामी लोकसभा चुनाव में लक्ष्मणा नदी मामले को लेकर एक नया मंच बनाए जाने की चर्चा है. चर्चा यह भी है कि लोग दलगत अथवा जातिगत भावना से हटकर नदी की समस्या पर एकजुट होंगे और इसके निदान की दिशा में पहल नहीं करने वालों की एक नही सुनेंगे. खासकर छठ व्रतियों ने तो चुनावी अभियान में दरवाजे पर बतौर प्रत्याशी दस्तक देने वालों को लगे हाथ ही सबक सिखाने की ठानी है. अब देखना यह है कि गंभीर समस्या का निदान को लेकर लोग एकजुट होते है अथवा चुनावी बयार में दलगत व जातिगत भावना में बहकते हैं. ■

नदी में बोरिंग का गिरता पानी

नदी में बनाया गया अस्थायी बांध

खगड़िया को खंगाल रहे हैं पप्पू

नंदकिशोर शर्मा

पप्पू यादव और उनकी युवा शक्ति कोशी क्षेत्र में इनदिनों जोरदार तरीके से सक्रिय है. आए दिन संभा–संगोष्ठी, रैली और यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. लोकसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिती दर्ज कराने के लिए कोशी के विभिन्न इलाकों में युवा शक्ति लगातार आशीर्वाद यात्रा का आयोजन कर रही है. हाल ही में खगड़िया में आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसभा कर पप्पू यादव ने जता दिया कि कोशी क्षेत्र में उनकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी है साथ ही यह भी जता दिया कि भविष्य में इलाके की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में उनकी भूमिका अहम होगी.

जेएनकेटी मैदान में आयोजित आशीर्वाद यात्रा के दौरान युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है कि जब भी परिर्वतन की बात आई है, दुनिया में क्रांति हुई है. शोषण और भूख से ऊबकर ही लोग क्रांति की राह चुनते हैं. उन्होंने कहा कि जब मुझे महसूस हुआ कि इस बिहार में बुराई से लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो, मैने यह निर्णय किया कि मानवता और अच्छाई को स्थापित करने के लिये आशीर्वाद यात्रा कर बुजुर्गो और युवाओं के बीच जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि विवेकानन्द अपने जीवन में पांच लोगों की खोज करने के लिए निकले थे, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं हो. लेकिन उन्हें ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला. तब अपने देश की आबादी 40 करोड़ से भी कम थी. लेकिन आज अपने देश की आबादी सौ करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है. मैं खगड़िया में ऐसे पांच लोगों की खोज में आया हूं. जिनके अंदर कोई बुराई नहीं हो. मुझे उम्मीद है कि मेरी खोज सफल होगी. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बार–बार कहा जाता है कि बिहार विकास कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या खगड़िया के रिक्शा चालक का बेटा, इनके बेटे या पप्पू यादव के बेटे के साथ पढ़ रहा है या राष्ट्रपति के बच्चे और महादलित के बच्चे का इलाज एक ही अस्पताल में हो रहा है. अभी कुछ दिन पहले खैनी को टैक्स फ्री कर दिया है. वे खुद को बिहार का शुभचिंतक बताते हैं. क्या उनको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी तंबाकू व शराब के सेवन से होती है. अपने संबोधन में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा व शराबखोरी का मुद्दा भी उठाया. वहीं पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि बिहार में दुष्कर्म के मामले में इजाफा हुआ है. बिहार में महिलाओं के हक की बात की जाती है. लेकिन महिला सुरक्षा की बात नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि बिहार में 7–8 वर्षो में सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं घटी है. यहां तक कि आठ वर्ष की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने गुजरात पर चर्चा करते हुए कहा कि वहां प्रत्येक तीन में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है, इनको भोजन नहीं मिल रहा है क्या यही विकास है. कार्यक्रम की अध्यक्षता नागेश्वर प्रसाद सिंह ने की. जबकि मंच संचालन युवा शक्ति के प्रदेश संरक्षक नागेन्द्र सिंह त्यागी ने किया. इस मौके पर नगर सभापति मनोहर कुमार यादव, युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार यादव, जिला कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रशेखर कुमार, शिवराज यादव, चंदन सिंह, दीपक चन्द्रवंशी सहित सैकड़ों युवा शक्ति के कार्यकर्ता उपस्थित थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

11 नवंबर–17 नवंबर 2013

> सासाराम लोकसभा का इतिहास रहा है कि मतदाता अंतिम वक्त में फैसला लेता है और और सीधे टक्कर वाले उम्मीदवार के साथ खड़ा हो जाता है. लोकसभा क्षेत्र में इस बार भी अल्पसंख्यकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. जिनके पास मैडम स्पीकर और राजद के अलावा जदयू भी विकल्प के रूप में मौजूद है.

एक नज़र

नीतीश नाकाम : अमरेन्द्र

पिछले दिनों बिहार में भाजपा की रैली में हुए आतंकी विस्फोट को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान सरकार पर कई सवाल खड़े किए. पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह पूरी तरह से सरकार और इसके खुफिया तंत्र की विफलता है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री यह कहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं कि उन्हें पहले से इनपुट नहीं दिया गया था. श्री सिंह ने कहा कि रैली के दिन पूरे शहर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था. सुरक्षा की व्यवस्था उस दिन बहुत ही लचर थी. साथ ही यह भी कहा कि गांधी मैदान के किसी भी इंट्रेंस पर मेटल डिटेक्टर तक की व्यवस्था नहीं थी और न ही किसी भी गेट पर दंडाधिकारी तैनात थे.

– अमृता कुमारी

स्लीप एपनिया का इलाज

घातक बीमारी स्लीप एपनिया का इलाज अब मोतिहारी में होने लगा है। बरियारपुर स्थित सुपर स्पेश्यिलिटी हॉस्पीटल रहमानिया मेडिकल सेन्टर में एलर्जी और दमा रोग विशेषज्ञ डा. विवेक कुमार के निर्देशन में इस बीमारी का इलाज आसानी से हो रहा है। उक्त जानकारी रहमानिया सेंटर के प्रबंध निदेशक डॉ. तबरेज अजीज ने दी। इन्होंने बताया कि दमा एवं एलर्जी विभाग की शुरुआत होने से पूर्वी चम्प–ारण जिला समेत अन्य नजदीकी जिलों के मरीजों को काफी राहत मिली है। इस अवसर पर मौजूद एलर्जी एवं दमा रोग विशेषज्ञ डा. विवेक कुमार ने बताया कि एपनिया एक घातक बीमारी है। इन्होंने स्लीप एपनीया बिमारी पर विस्तार से चर्चा भी की. इन्होंने बताया कि आगे चलकर यह बीमारी रक्तचाप या मधुमेह जैसे रोगों का रूप ले सकती है। मौके पर दीपक कुमार व डा. उमर तबरेज समेत कई चिकित्सक उपस्थित थे।

बैठक आयोजित

महिला पर्यवेक्षिका शक्ति संगठन की बैठक मोतिहारी स्थित आईएमए हॉल में आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से पुष्पा कुमारी को संगठन का अध्यक्ष, पिंकी कुमारी को सचिव व हुसने आरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका पिंकी कुमारी, शिवांगी, शारदा कुमारी, अनामिका कुमारी, मंजू कुमारी, रूपम कुमारी, प्रिय दर्शनी कुमारी, स्वेता गौतम, नूतन कुमार, राजंती कुमारी, शीला कुमारी, ललिता कुमारी, सरोज सिंह, शारदा कुमारी समेत बड़ी संख्या में पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित थीं। इस अवसर पर संगठन को मजबूत बनाने तथा लंबित मानदेय भुगतान के लिए मजबूती के साथ संघर्ष करने का संकल्प लिया गया।

– इंतेजारूल हक

शिक्षकों की उपेक्षा

खगड़िया शिव मंदिर परिसर में 1991 नियमावली के तहत 1999 और 2000 में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों की बैठक रामानंद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मौके पर शिक्षक दिलीप कुमार, श्रवण कुमार, धीरज कुमार, निरंजन कुमार, गजेन्द्र प्रसाद यादव, अशोक कुमार, भारत साह, धर्मेन्द्र कुमार, अजय कुमार, नीतीश भारद्वाज, चन्द्रशेखर पासवान, सत्येन्द्र सदा, महानन्द कुमार, अनील कुमार, रवि कुमार, निर्मल कुमार सहित दर्जनों शिक्षकों ने सर्वसम्मति से कहा कि सरकार द्वारा ज्ञापांक 1400 दिनांक 13.09.2013 के निर्गत आदेश न्यायसंगत नहीं है. शिक्षकों ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त नियुक्ति एवं प्रोन्नति समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना है. शिक्षकों ने कहा कि सरकार द्वारा न्यायालय में मामले को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण एक त्रुटिपूर्ण आदेश पारित हो गया. शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि आदेश को वापस ले और मामले को सही तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत करे ताकि शिक्षकों को न्याय मिल सके.

– नंदकिशोर शर्मा

अन्ना के संदेश का प्रचार

अन्ना के संदेश यात्रा के तहत खगड़िया प्रखंड कार्यालय प्रांगण में एक जनसभा का आयोजन श्यामलाल चन्दशेखर पारा मेडिकल संस्थान के अधीक्षक डा.विवेकानंद के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अन्ना हजारे के संदेश से लोगों को अवगत कराते हुए डा0 विवेकानंद ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों का साथ इसी तरह मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश में लोकपाल विधेयक को पारित करवा कर ही अन्ना हजारे दम लेगें। लोकपाल विधेयक के पारित होने पर ही अधिकारी स्वतंत्र रूप से नेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर कर पाएंगे. मौके पर अभिनव कुमार, अनुज पासवान, ध्रमेन्द्र कुमार, नंद कुमार, नेपाली यादव, संजीव कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।

अस्पताल की व्यवस्था चौपट

खगड़िया अनुमंडल मुख्यालय स्थित रेफरल अस्पताल गोगरी में आउटसोर्स की व्यवस्था लचर होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार आउटसोर्स व्यवस्था के तहत यहां साफ–सफाई के साथ रौशनी व मरीजों के भोजन की व्यवस्था सिर्फ पंजियों पर ही चल रहा है। एक तरफ जहां अस्पताल परिसर में यत्र–तत्र गंदगी नजर आती है। वहीं चादर आदि की भी नियमित सफाई नहीं होती है। जिस कारण बिना चादर के मरीजों को बेड पर रहना पड़ता है। वहीं मरीजों के भोजन की बात करें तो यहां मेनू के अनुसार नाश्ता व भोजन नहीं मिलता है। मरीज नसीमा बेगम ने बताया कि अस्पताल में नास्ता एवं भोजन नियमानुसार नहीं दिया जाता है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. संतोष कुमार डोकानियां ने बताया कि आइटसोर्स व्यवस्था में सुधार करना संवेदक की जिम्मेदारी है।

– उधव कुमार

सघन छापेमारी

चतरा एसडीओ के द्वारा की जा रही सघन छापेमारी से इनदिनों जिले के बारहो प्रखंड के भ्रष्ट लोगों में दहशत का माहौल है. छापेमारी के क्रम में एसडीओ ने चतरा, इटखोरी, सिमरिया, प्रतापपुर व हजरतगंज स्थित सभी छह गोदामों पर छापेमारी की. यही वजह है कि इनदिनों इलाके में कालाबाजारी में कमी आई है. एसडीओ को लगातार सूचना दी जाती थी कि पीडीएस दुकानदार कम राशन तौलते हैं और फर्जी गाड़ी से इठाव का काम लिया जाता है. तमाम सूचना के बाद एसडीओ ने जांच का आदेश दे दिया है.

– अमरेंद्र प्रताप सिंह

किसान गोष्ठी

महेंशखुंट क्षेत्र अन्तर्गत समसपुर पंचायत में धान्या कंपनी के द्वारा किसान गोष्ठी मिलन समारोह का आयोजन अमरबिन्दु चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. इस अवसर पर बिजनेश सेल्स मैनेजर राजीव कुमार सोलंकी, आरएमडीएस रामाशंकर प्रसाद, टीएसएम अभिषेक कुमार मौर्य, एमडीआर कुमार राजीव रंजन ने धान्या कंपनी के बारे में धान, मक्का एवं तरह – तरह के सब्जी बीज के बारे में विस्तृत जानकारी दी. श्री सोलंकी ने बताया कि ये मक्का विगत तीन वर्षो से खगड़िया जिले में किसानों द्वारा बोई जा रही है और इसकी पैदावार एक बीघे जमीन में 100 –120 मन की दर से पैदावार होती है. इस अवसर पर किसान रजनी रंजन चौधरी,विद्यास–गर पासवान, देवेन्द्र कुमार चौधरी, त्रिवेणी मिश्र, राजेन्द्र चौधरी सहित गोगरी प्रखंड के 11 पंचायत के किसानों ने किसान गोष्ठी सम्मेलन में भाग लिया.

कार्यशाला आयोजित

खगड़िया रेडक्रॉस सभागार में सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग से नव जागृति संस्था द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्त्तन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन अंतराष्ट्रीय पर्यावरण विशेषज्ञ डा. दिनेश कुमार मिश्र, कार्यक्रम की अध्यक्षता अमनी मुखिया प्रमोद कुमार सिंह, नव जागृति के सचिव जितेन्द्र कुमार, एवं जिला परिषद् सदस्य अजीत सरकार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. नव जागृति संस्था द्वारा पूर्व में आयोजित कार्यक्रम चित्रलेखन एवं निबंध प्रतियोगिता में चांदनी कुमारी, भारती कुमारी, अंकित भारती, राहुल कुमार, गुलशन कुमार, को प्रथम पुरूस्कार के साथ–साथ दर्जनों बच्चों को भी पुरूस्कार दिया गया. इस अवसर पर संस्था के कुणाल कुमार, बबलू कुमार, शिक्षक राजेन्द्र पंडित, भरत साह, अजित कुमार, रतन कुमार, एवं रामदेव सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

राजद मर्माहित

राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेताओं की बैठक राजद नेता अमित कुमार इर्फ पप्पु यादव के आवाश पर आयोजित की गई। बैठक में राजद के प्रदेश महासचिव प्रो0 नौशाद आलम के आकस्मिक निधन दिल्ली से ईलाज करा कर लौटने के क्रम में हृदय गति रूक जाने के करण हो गई। इनके निधन पर राजद नेताओं ने दो मिनट का शोक संवेदना व्यक्त किया। बैठक में प्रधान महासचिव महेश्वरी प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष रामचलित्तर सदा, अधिवक्ता यदुनंदन यादव, अमित कुमार इर्फ पप्पु यादव, प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद यादव, नगर अध्यक्ष भुषण यादव, इपाध्यक्ष रमण यादव, रियाज अली, विक्की कुमार, राजेश यादव, अमर कुमार साह, प्रो0 जुल्फीकार अली, दिनेश प्रसाद यादव, डा0 राजीव रंजन, अर्जुन कुमार भारती, सहित दर्जनों नेताओं ने अपने – अपने विचार व्यक्त किये।

– नन्द किशोर शर्मा

विकास पर होगी लड़ाई

पूर्व सांसद रघुनाथ झा ने कहा कि लालू प्रसाद के जेल जाने से राजद में मजबूती आयी है. कुछ लोग इस ताक में थे कि श्री प्रसाद के जेल जाने के बाद राजद सूखे पत्ता की भांति हिलने लगेगा. परंतु इनकी सोच आज विपरित साबित हो रही है. सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित युवा राजद प्रदेश महासचिव दिलीप राय के आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में श्री झा ने कहा कि राजद सुप्रीमों को एक साजिश के तहत फंसाया गया है. कहा कि आगामी चुनाव में राजद की लडाई भाजपा से संभव है, जदयू कही भी नही है. अगले चुनाव में राजद का मुख्य मुदा विकास होगा. इन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकसभा के बाद विधान सभा चुनाव में राजद को इस बार फिर पूर्ण बहुमत मिलेगा. कहा कि यह विडंबना ही है कि 60 दलितों की हत्या करने वाला वरी किया जा रहा है और घोटला मामले में एफआईआर का आदेश करने वाला को सजा दी जा रही है. चारा घोटाला मामले में चोर ही गवाह बने है.■

– वाल्मीकि

छेदी बदले और बदला समीकरण

ममता चौहान

सासाराम लोकसभा क्षेत्र हमेशा से चर्चा में रहा है. फिलहाल यह क्षेत्र आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सुर्खियों में है. हाल के दिनों में इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर बहस कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है. इसकी वजह है जदयू के विधायक और पूर्व मंत्री छेदी पासवान. हुआ यह कि छेदी पासवान मोदी से अहमदाबाद जाकर मिल आए और मोदी की प्रशंसा भी की. इसी वजह से उन्हें जदयू से छह सालों के लिए निलंबित कर दिया गया है. अब अटकलों का बाजार गर्म है कि छेदी सासाराम से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ सकते है. हालांकि इस बात पर भाजपा की तरफ से कोई ठोस संकेत नहीं दिए गए हैं. लेकिन अटकलें सही हुई तो सासाराम लोकसभा क्षेत्र बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा.

फिलहाल इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मीरा कुमार करती हैं, और अगर छेदी पासवान को यहां से भाजपा उम्मीदवार बनाएगी तो मीरा की राहें मुश्कि ल हो जाएंगी. क्योंकि एक तरफ उनके वोट बैंक में भाजपा सेंधमारी करेगी और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी पंकज कुमार भी उन्हें चुनौती दे सकते हैं. बताया जाता है कि मैडम स्पीकर से उनके क्षेत्र के अल्पसंख्यक कुछ ज्यादा ही नाराज हैं. यही वजह है कि राजद के संभावित प्रत्याशी ललन पासवान पहले से ही अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं.

जानकार बताते हैं कि मीरा कुमार के रविदास, ब्राम्हण और कुशवाहा मतों पर भी उपेंद्र प्रसाद की नजर है. अगर यह हुआ तो मैडम की परेशानी और बढ़ जाएगी. भाजपा की तरफ अगड़े मतों की बढ़ती दिलचस्पी. रविदासों के मन में बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता प्यार कोई भी गुल खिला सकता है. अभी मैडम स्पीकर मीरा कुमार और बहुजन समाज पार्टी के पंकज कुमार के अलावा किसी भी दल के तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं. आशंकाओं की बदौलत छेदी पासवान के भाजपा से लड़ने की संभावना और ललन पासवान के राजद के उम्मीदवार होने की बात में कुछ दम दिख रही है। जदयू ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है. जब जदयू का पत्ता खुलेगा तो कई मतों के गणित इधर से इधर हो सकते हैं. फिलहाल पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल राम के समर्थक भी दावा ठोंक रहे हैं कि टिकट मुनीलाल राम को ही मिलेगा. परिस्थितियां बदलीं तो उनके पुत्र व विधायक शिवेश राम उर्फ गुड्डू भी भाजपा के दावेदार हो सकते हैं. संजीव कुमार का भी एक नाम भाजपा के दावेदारों में शामिल है. देखना यह है कि भाजपा किसकी उम्मीदवारी में भरोसा जताती है. फिलहाल भाजपा और जदयू दोनो का समीकरण छेदी पासवान की नाराजगी से गड़बड़ हो गया है. एक तरफ छह वर्ष के निलंबन के बाद जदयू सास–राम में अपने लिए ऐसे उम्मीदवार की तलाश करेगी जो छेदी पासवान का मजबूत विकल्प हो सके. दूसरी तरफ भाजपा को टिकट बंटवारे में कई परेशानियां सामने आएगी. फिलहाल छेदी पासवान की दावेदारी कुछ ज्यादा ही मजबूत दिख रही है.

राजद के खेमे में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के चारा घोटाले में जेल जाने के बाद फिलहाल खामोशी ही छाई हुई है. हालांकि ललन पासवान द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे तेज दौरे को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी ने इन्हें तैयारी के लिए इशारा कर दिया है. हाल के दिनों में बड्डी की घटना को लेकर मैडम स्पीकर के तरफ से दिए गए बयान ने अगड़ों में कुछ नाराजगी बढ़ाई है. साथ ही उपेंद्र कुशवाहा द्वारा रोहतास में

लगातार किए जा रहे दौरे से भी मैडम स्पीकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हालांकि सासाराम लोकसभा का इतिहास रहा है कि मतदाता अंतिम वक्त में फैसला लेता है और और सीधे टक्कर वाले उम्मीदवार के साथ खड़ा हो जाता है. लोकसभा क्षेत्र में इस बार भी अल्पसंख्यकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. जिनके पास मैडम स्पीकर और राजद के अलावा जदयू भी विकल्प के रूप में मौजूद है. देखना यह है कि छेदी पासवान के चुनावी मैदान में आने से सासाराम की लड़ाई कितने कोणों पर हो रही है. पिछली बार इस लोक सभा सीट पर मैडम स्पीकर मुनीलाल को लगातार दूसरी बार हराया था. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

11 नवंबर–17 नवंबर 2013

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

नेताओं की बदजुबानी से दागदार होता लोकतंत्र

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी को मिल रहा जनसमर्थन उनकी मुखालफत करने वालों को रास नहीं आ रहा है. यह हकीकत आम है. उनके विरोधियों को मलाल इस बात का है कि मोदी कैसे जनता की दुखती रग को पकड़ लेते हैं. पीएम इन वेटिंग की रैली में तालियां बजती हैं तो उनके विरोधियों के सीने पर सांप लोट जाता है. नमो मुसलमानों के पक्ष की बात बोलते हैं तो भी कांग्रेसी और सपाई–बसपाई हजम नहीं कर पाते हैं. उन्हें चिंता सताने लगती है कि मोदी को लेकर मुसलमानों का भय कहीं खत्म न हो जाए, जिसके सहारे वह अपनी राजीतिक रोटियां सेंकते हैं. जनता ही नहीं मोदी के चमत्कार को मीडिया भी नमस्कार कर रहा है. मोदी विरोधी ड्राइंग रूम में बैठकर काट तलाश रहे हैं. बौखलाहट का हाल यह है कि नमो के प्रभाव को कम नहीं कर पाने वाले तमाम दलों के नेता उनके खिलाफ असंसदीय भाषा और गाली–गलौच तक पर उतर आए हैं. कांग्रेस के नेता और मंत्री बेनी प्रसाद, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व चुनाव प्रभारी दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल जैसे अन्य कई नेताओं की काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट है जो मोदी विरोधी हैं. कुछ कट्टरपंथी धर्मगुरू भी इस राजनीतिक खेल में मोदी के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं.

हाल में ही भाजपा के 'पीएम इ वेटिंग' के खिलाफ नरेश अग्रवाल की टिप्पणी ने तो सभी हदें पा कर दीं. नरेश बदजुबानी के मामले में अन्य नेताओं के मुकाबले में काफी आगे हैं. उनकी बदजुबानी विरोधियों को ही नहीं उनकी ही पार्टी सपा का भी सीना अक्सर छलनी करती रहती है. अब तो मोदी के खिलाफ जहर उगलने के चक्कर में वह देश की आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं. भाजपा की तुलना विधवा महिला से करके विवाद खड़ा करने वाले नरेश अग्रवाल की बदजुबानी के कारण भाजपा ने तो इनको करारा जबाव दिया ही है, वहीं महिला आयोग ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उनकी पार्टी के नेता ही जब अपने आप को असहज समझने लगे तों स्थिति की गंभीरता का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है. करीब–करीब सभी दलों की खाक छान चुके नरेश का कोई स्थाई ठिकाना नहीं है. उनका पता सत्तारूढ़ दल का नेता है. वह सत्ता के साथ रहते हैं. उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की. कहा जाता है कि नरेश अग्रवाल के पिता कांग्रेस से विधायक थे, उनकी उम्र बढ़ने लगी तो नरेश ने उनके फर्जी हस्ताक्षर से एक पत्र कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया. पत्र में कहा गया था कि मैं वृद्ध हो गया हूं. इसलिए मेरे बेटे नरेश को मेरा टिकट दे दिया जाए. कांग्रेस ने ऐसा ही किया. जब नरेश के पिता को पता चला कि उनका टिकट काट कर बेटे को दे दिया गया है तो वह हाईकमान के पास पहुंचे. वहां अपने हस्ताक्षर वाला पत्र देखकर वह अवाक रह गए, लेकिन कर कुछ नहीं पाए. नरेश एक बार चुनाव जीतने के बाद लगातार अपनी ताकत बढ़ाते रहे. वह निर्दलीय से लेकर तमाम दलों से चुनाव जीत चुके हैं. जीत के लिए उन्हें कभी किसी पार्टी का मुंह नहीं देखना पड़ता है, इसीलिए उन्हें किसी भी दल में जाने में परहेज नहीं रहता है. प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया और कल्याण और राजनाथ सरकार में बिजली मंत्री बने. भाजपा कमजोर हुई तो मुलायम का दामन थाम लिया. 2003 से 2007 तक मुलायम मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री सहित अनेक विभाग संभाले. 2007 का विधान सभा चुनाव नरेश सपा के टिकट से ही जीते, लेकिन जब बसपा की सरकार बनी तो मुलायम को खरी–खोटी सुनाकर पहले तो विधायकी से इस्तीफा दे दिया, इसके बाद बसपा का दामन थाम लिया. मायावती ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया. बसपा में उनकी मंत्री अब्दुल मन्नान से खटक गई तो उन्होंने उनकी जांच लोकायुक्त से शुरू करा दी. इससे माया नाराज हो गईं. नाराज माया ने 2012 के विधान सभा चुनाव में नरेश अग्रवाल के विधायक पुत्र नितिन अग्रवाल का टिकट काट कर पिता–पुत्र को करारा झटका दिया. इतना ही नहीं नितिन का टिकट काट कर माया ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजा बख्श सिंह को थमा दिया था, जिनका नरेश से छत्तीस का आंकड़ा था. वह तिलमिला गए और अपने लिए कांग्रेस और सपा में संभावनाएं तलाशने लगे. सपा से ट्यूनिंग बैठने के बाद इनकी इंट्री पुन: पार्टी में हो गई. यह इतिहास है नरेश अग्रवाल का.

नरेश अग्रवाल ने जब अपने बाप को नहीं छोड़ा तो किसी और को तो इनसे रहम की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए. आज भले ही मोदी उनके निशाने पर हों लेकिन कभी वह इसी तरह से मायावती,मुलायम और सोनिया–राहुल गांधी, बेनी प्रसाद, अमर सिंह, आजम खां आदि नेताओं को समय–समय पर कोसा करते थे. कुछ समय पूर्व कांग्रेस के वरिश्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के साथ राज्यसभा में उनकी नोंकझोंक ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. इसी तरह से प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर भी नरेश ने राज्यसभा में हाथापाई तक कर डाली थी. नरेश ने जैसे ही एक कार्यक्रम में मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे. सपा के प्रदेश प्रवक्ता और मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने मीडिया के सवालों का जबाव देते हुए नरेश के बयान को इनकी निजी राय बताया तो वह चौधरी के खिलाफ जहर उगलने लगे और यहां तक कह दिया कि उनकी हैसियत क्या है जो मेरे बारे में कुछ कहें जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हवा का रूख भांप कर नरेश अग्रवाल ने अपने लिए नए आशियाने की तलाश शुरू कर दी है. नरेश की तरह ही कांग्रेस के नेता और मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुजफरनगर में दंगों पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि 200 दंगाई गुजरात से आए थे. मुलायम और भाजपा मिलकर दंगें करा रहे हैं. मुलायम के कभी सखा रहे बेनी ने तो कुछ समय पूर्व मुलायम को पागल नेता करार दे दिया था. इसी तरह से कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के बयान,'घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्वयनप्राश ने भी खूब चर्चा बटोरी थी. कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की भी जुबान अक्सर फिसल जाती है. कुछ माह पूर्व एक कार्यक्रम में उन्होंने नई–नई जीत और नई–नई शादी का अलग महत्व होता है. उन्होंने कहा कि समय के साथ दोनों पुरानी होती जाती हैं.

हाल में ही भाजपा के 'पीएम इ वेटिंग' के खिलाफ नरेश अग्रवाल की टिप्पणी ने तो सभी हदें पा कर दीं. नरेश बदजुबानी के मामले में अन्य नेताओं के मुकाबले में काफी आगे हैं. उनकी बदजुबानी विरोधियों को ही नहीं उनकी ही पार्टी सपा का भी सीना अक्सर छलनी करती रहती है. अब तो मोदी के खिलाफ जहर उगलने के चक्कर में वह देश की आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं.

बहरहाल, अभी शुरुआत है. नेताओं की बदजुबानी अभी और बढ़ेगी. कभी सुनियोजित तरीके से तो कभी जुबान फिसलने से नेता सुर्खियां बटोरते रहेंगे. क्योंकि मुद्दो पर कोई लड़ना ही नहीं चाहता है. आजलक शार्टकट का जमाना जो है, लेकिन मतदाता सब समझता है.वह अपने हिसाब से चुप रहकर जबाव देता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राहुल का बयान यूपी कांग्रेस को पड़ा भारी

यूपी की मुस्लिम सियासत में भूचाल

संजय सक्सेना

मध्य प्रदेश में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गरमा दिया है. राहुल ने कहा था, आईएसआई मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के सम्पर्क मे है. राहुल का यह बयान यूपी की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहा है. राहुल विरोधी नेता ही नहीं, कई मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने भी राहुल के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राहुल के मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में होने के बयान से नाराज उलेमाओं का कहना है कि लड़ाई–झगड़ा कभी सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन भारत में रहने वाला हर मुसलमान देश का वफादार नागरिक है. यह बात राहुल को समझनी चाहिए. वोट बैंक की राजनीति में कुछ भी कह देना गलत है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और कद्दावर धार्मिक नेता मौलाना डॉ कल्बे सादिक का बयान इस मामले मे काफी अहम है. उनका कहना था मैंने राहुल का बयान नहीं सुना है. इसे पूरा सुनकर ही राय दी जा सकती है. हां, यह जरूर कह सकता हूं कि भारत में रहने वाला हर मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वह इसके लिए कुरबान होना जानता है, इससे गद्दारी नहीं कर सकता. समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले आजम खां ने सवाल किया कि राहुल गांधी न तो सरकार का हिस्सा हैं, न ही किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं. ऐसे में कोई आईबी अधिकारी उन्हें कैसे जानकारी दे सकता है. खां ने राहुल से अपने बयान का खंडन करने को कहा. इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी सफाई देने को कहा. सपा नेता नरेश अग्रवाल भी राहुल के बयान से बिफरे हुए

थे. उनका कहना था कांग्रेस को मुसलमानों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है. वह वोट बैंक की राजनीति करती है. राहुल ने मुसलमानों की विश्वसनीयता और देश के प्रति उनकी वफादारी को छलनी कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राहुल के बयान को बचकाना करार दिया. उनका कहना था राहुल असलियत से भाग रहे हैं. देश के सामने महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास जैसी तमाम समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, लेकिन राहुल को अपने परिवार की चिंता रहती है. वह आईबी के हवाले से मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं. मोदी से डरे राहुल देश की समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं.

लखनऊ की ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दुख भरे लहजे में कहा कि राहुल का बयान किसी सांप्रदायिक दल के नेता जैसा है. इस बयान से दंगा पीड़ितों के साथ ही देशभर के मुसलमानों को ठेस पहुंची है. फिरंगी महली ने आह्वान किया कि मुसलमानों को सियासी नेताओं की सोच के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए और ऐसे बयान का जोरदार विरोध करना चाहिए. शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि सियासी दल मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के दर्द को समझना तो दूर, इस पर राजनीति करने पर तुले हैं. उन्होंने राहुल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे बयान साम्प्रदायिक ताकतों को मजबूती देते हैं. लखनऊ के शहर काजी मौलाना अबुल इरफान मियां फिरंगी महली ने कहा कि राहुल गांधी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए. इसी तरह से चेयरमैन हथकरघा निगम मौलाना तौकीर खां का कहना है कि यदि आईएसआई इतनी एक्टिव हो गई कि दंगा पीड़ितों से संपर्क कर रही है तो सरकार क्या कर रही है? यह सरकार की नाकामी है. दरअसल, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है.

बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि किसी भी पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है कि मुसलमान कैसे तरक्की करे. सपा और कांग्रेस जैसे दल मुसलमानों को दंगों में उलझा कर भयभीत रखना चाहते हैं तो भाजपा साम्प्रदायिकता की राजनीति करती है. बहन मायावती की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि मुसलमानों के वोटों पर राज करने वाली सपा सरकार के शासनकाल में अल्पसंख्यकों का सबसे अधिक उत्पीड़न हो रहा है. राहुल के बयान के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अपने मुंह बंद कर लिए हैं. मीडिया वालों से ऑफ द रिकार्ड कांग्रेसी नेता इस बारे में प्रतिक्रिया न लेने की गुहार लगा रहे हैं. हां, वह यह जरूर कहते हैं कि मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर न तो क्रांग्रेस को कभी संदेह रहा है, न ही राहुल की ऐसी भावनाएं रहीं थीं. कांग्रेस राहुल के बयान से राजनैतिक नफा–नुकसान का भी आंकलन कर रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

सपा ने खेला पिछड़ा आरक्षण कार्ड

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी और सरकार वह सभी चुनावी टोटके आजमा रही है, जिससे उसका वोटबैंक बचा रहे. दंगों की आड़ और अन्य हथकंडे अपनाकर मुसलमानों को रिझाने की कोशिशों के बाद समाजवादी पार्टी अब पिछड़ों को आरक्षण के नाम पर अपने पीछे लामबंद करने के लिए हाथ-पैर मारने लगी है. इसकी शुरुआत तो इसने प्रोन्नति में आरक्षण की वकालत करके काफी पहले से ही शुरू कर दी थी. अब सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से 17 पिछड़ी जातियों की अधिकार रथयात्रा तथा सामाजिक न्याय रथयात्रा को हरी झंडी दिखाकर खुलकर पिछड़ा कार्ड खेल दिया है. सपा को उम्मीद हैं कि ये रथ यात्राएं सपा के पक्ष में परिवर्तन का माहौल बनाएगीं और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का संदेश देंगी. 24 अक्टूबर को प्रारम्भ हुई यात्राएं 07 दिसंबर तक चलेंगी.

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव रथ यात्राओं को लेकर काफी उत्साहित थे. यादव ने यहां तक कह दिया कि आज का दिन परिवर्तन और क्रांति का दिन माना जाएगा. समाजवादी पार्टी जीतेगी और बाकी दल हार का सामना करेंगे. 26 साल पूर्व जब समाजवादी पार्टी की क्रांति रथ यात्रा चली थी तो कांग्रेस डूबी थी. गैर कांग्रेसी सरकार उनके नेतृत्व में बनी थी. विधानसभा चुनाव से पूर्व अखिलेश यादव के नेतृत्व में रथयात्रा चली तो बहुमत की सरकार बनी. यादव ने कहा कि लोकसभा में जब उन्होंने 17 पिछड़ी जातियों का सवाल उठाया तो तमाम सांसदों को उनके बारे में जानकारी नहीं थी. समाजवादी पार्टी ने उनके आंदोलन की नींव रखी. समाज में जिनकी पहचान नहीं थी, गरीब और उपेक्षित इन जातियों को राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित करके रखा गया. समाजवादी पार्टी ने उनके हाथों में नेतृत्व दिया है.

उन्होंने सचेत किया कि आरक्षण समाप्त करने की साजिशें हो रही हैं. हमें अब आरक्षण बढ़ाओ, आरक्षण बचाओ इन दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना है. नीतियां खराब हों और नीयत ठीक हो तो काम होगा, लेकिन बाकी दलों की नीयत ही ठीक नहीं है. समाजवादी पार्टी की नीयत साफ है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं से अपील की कि वे इन रथयात्राओं को सम्मान दें. उनके सहयात्रियों का हौंसला बढ़ाएं. आगामी 14 दिसम्बर को रथयात्रा की समाप्ति लखनऊ में होगी. इस दिन रमाबाई अम्बेडकर रैली स्थल लखनऊ में सामाजिक न्याय रैली होगी. यात्राओं को रवाना करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम छोटी जातियों को अधिकार रथ यात्रा से जागरूक करने में मदद मिलेगी. नेताजी ने उन्हें सम्मान दिया था. बसपा राज में उन्हें सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था. समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का विधानसभा में प्रस्ताव किया और केन्द्र को भी प्रस्ताव भेजा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुस्लिम सोच से कांग्रेस-सपा को झटका

संजय सक्सेना

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी का भय दिखाकर मुस्लिम वोट हड़पने की कांग्रेसी और समाजवादी साजिश परवान नहीं चढ़ पा रही है. मुसलमानों में पढ़ा-लिखा जागरूक तबका इस साजिश का विरोध करने लगा है. इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है. जहां मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस-सपा और बसपा की तिकड़ी में सबसे अधिक मारामारी होती है. कई मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी मोदी के प्रति सुर बदलने से कांग्रेस-सपा को लगने लगा है कि बदले हालात में नमो का भय दिखाकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने का इनका सपना पूरा होने वाला नहीं है. हालात अनुकूल नहीं होता देख ही केन्द्र सरकार ने ठंडे बस्ते में पड़ा दंगा विरोधी बिल का जिन्न बाहर निकाल दिया है. शीतकालीन सत्र में इसे पेश किए जाने की बात कांग्रेसियों द्वारा की जा रही है, ताकि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस की तरफ खींचने में कामयाबी मिल सके. वहीं मोदी को लेकर कुछ समय पूर्व तक उत्साहित लग रही समाजवादी पार्टी के दिग्गजों को भी लगने लगा है कि मोदी के आगे आने पर उन्होंने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का जो सपना देखा था, वह अधूरा ही रह गया है. सपा भी इसलिए नये-नये हथकंडे अपना रही है. वह दंगों को भाजपा की देन बता रही है. विहिप पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाकर मोदी को निशाने पर लिया जा रहा है.

बात वोट बैंक की राजनीति करें तो मुसलमानों को मोदी की और मोदी को मुसलमानों की बातें कुछ-कुछ समझ में आने लगी हैं. यह सच्चाई है कि गुजरात दंगों का दर्द न होता तो अल्पसंख्यक उनसे इतना परहेज नहीं करता. इसीलिए मोदी विकास के मसले पर खुद को केंद्रित कर रहे हैं. वह गुजरात दंगों का दाग धोने की बजाय इस कोशिश में हैं कि सपा-काग्रेस को भी दंगों की राजनीति में लपेट लिया जाए. उनके रणनीतिकार सपा-कांग्रेस के दंगों के इतिहास का खाका तैयार करके उक्त दलों को आंखें दिखाने लगे हैं. मोदी की कोशिश है कि मुसलमान भाजपा के पक्ष में भले ही मतदान न करे, लेकिन इसके मन मनमष्तिस्क में भाजपा के प्रति दुराग्रह न पाले. वह अपने इस प्लान में काफी हद तक सफल होते दिख भी रहे हैं. पिछले दिनों मौलाना मदनी ने कहा था कि कंाग्रेस उन्हें मोदी का डर नहीं दिखाए. अब आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने मोदी के सामने

भाजपा मुसलमानों में पैठ बनाने की भी कोशिश करना चाहती है. पर अभी यह दूर की कौड़ी है. मोदी के केन्द्रीय राजनीति में छाने के साथ ही वह चर्चाएं भी गलत साबित हो गईं, जिसमें कहा गया था कि मोदी यूपी में अयोध्या से ही चुनावी बिगुल फूकेंगे. उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और न ही इस मुद्दे का अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं. वह भारतीय संविधान और राष्ट्रभक्ति को ही धर्म की परिभाषा दे रहे हैं. पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कहते हैं कि अटल जी के जमाने में पार्टी के पास हिंदुत्व के साथ विकास का मुद्दा भी था. उनसे सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों का लगाव था.

एक तरह का प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि भारतीय जनता जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी खुद को बदल लें तो वह (कल्बे सादिक) भी उन्हें वोट दे सकते हैं. मौलाना सादिक ने साफ कहा कि गुजरात दंगों के कारण मोदी ने मुसलमानों का भरोसा खोया है. मेरी सलाह है कि वहदेश सेवा करके खुद को बदलें. अगर वह खुद को बदलते हैं तो मैं भी उन्हें वोट दे दूंगा. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक साहब की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. उनकी मुसलमानों में ही अच्छी पकड़ नहीं है, हिन्दू भी उनकी सोच के कद्रदान हैं.

मदनी और सादिक अकेले धर्मगुरु नहीं नहीं हैं, जिन्होंने मोदी का समर्थन किया हो. इससे पहले भी मोदी के समर्थन में कई मुस्लिम मौलाना आगे आ चुके हैं. कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश स्थित दारुल उलूम देवबंद के बर्खास्त कुलपति गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने भी गुजरात के विकास के लिए मोदी की तारीफ की थी. वस्तानवी से पहले अहमदाबाद की जामा मस्जिद के मुफ्ती साबिर अहमद सिद्दीकी ने मोदी को भेदभाव से परे बताते हुए कहा था कि मोदी के राज्य में मुसलमानों को भी तरक्की के समान अवसर मिल रहे हैं. इतना ही नहीं, सच्चर आयोग भी मोदी को मुसलमानों के मामले में बेहतर मानता है. सच्चर रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में रहने वाले मुसलमानों की साक्षरता दर 73.5 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 69.1 है. इसी प्रकार गुजरात में मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी 5.4 प्रतिशत है. इसकी तुलना में बात पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों करें तो बंगाल में यह प्रतिशत 2.1, दिल्ली में 3.2 और महराष्ट्र में 4.4 है. सच्चर आयोग की रिपोर्ट से यह खुलासा भी होता है कि उत्तर प्रदेश जहां पिछले बीस वर्षों से मुस्लिमों के वोटों से हकूमत करने वाली सरकार रही, वहां आज भी करीब चौदह सौ गांव ऐसे जहां एक भी स्कूल नहीं है. गुजरात में यह संख्या मात्र छह है. प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा के मामले में भी गुजरात की स्थिति अन्य राज्यों से काफी बेहतर है. बहरहाल, कल्बे सादिक सहित अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं के बयान के बाद मोदी के सामने यह यक्ष प्रश्न है कि क्या वह मौलानाओं की आशा के अनुरूप अपने आप को बदल पाएंगे? अगर ध्यान से देंखे तो इसका जबाव हां में मिलता है. मोदी हिंदुत्व के मुद्दों से अपनी सभाओं में बचने की कोशिश कर रहे हैं. वे कुछ ऐसे भी बयान दे रहे हैं जो उनकी पार्टी और उनके साथियों को शायद ही मंजूर हों. उनके शौचालय पहले देवालय बाद में वाले बयान पर हंगामा मचा, सब जानते हैं. उन्होंने उन्नाव में खजाने की खुदाई पर जो रुख लिया, वह भी उनकी पार्टी लाइन से थोड़ा अलग था. 19 अक्टूबर को कानपुर में शंखनाद रैली में भी अपने भाषण से उन्होंने जो संकेत दिया, उसका सार यही है कि वह सिर्फ विकास के एजेंडे पर ही मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खीचेंगे. उनकी तरफ से जनता की मूलभूत सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों पर हमेशा करारा प्रहार होगा. वह सभी को साथ लेकर चलेंगे. उनके इस रुख से भाजपा को एनडीए के कुनबा विस्तार में मदद मिलने की उम्मीद है. भाजपा मुसलमानों में पैठ बनाने की भी कोशिश करना चाहती है. पर अभी यह दूर की कौड़ी है. मोदी के केन्द्रीय राजनीति में छाने के साथ ही वह चर्चाएं भी गलत साबित हो गईं, जिसमें कहा गया था कि मोदी यूपी में अयोध्या से ही चुनावी बिगुल फूकेंगे. उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और न ही इस मुद्दे का अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं. वह भारतीय संविधान और राष्ट्रभक्ति को ही धर्म की परिभाषा दे रहे हैं. पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कहते हैं कि अटल जी के जमाने में पार्टी के पास हिंदुत्व के साथ विकास का मुद्दा भी था. उनसे सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों का लगाव था. भाजपा में मोदी की भी कुछ ऐसी ही छवि बनाने की कवायद चल रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वांचल: शिक्षा के अधिकार की उड़ रहीं धज्जियां

मारकण्डेय प्रसाद सिंह

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में शिक्षा अधिकार कानून के साथ मजाक किया जा रहा है. यहां गरीबों की संख्या अधिक है. शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं है. केन्द्र ने 2012 में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया था, इसके तहत गरीब बच्चों को शहर के कान्वेन्ट स्कूलों में दाखिला कराकर इसके खर्च का बोझ सरकार को उठाना था. लेकिन दुर्भाग्य है कि इस कानून को विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया. क्योंकि आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर (पडरौना), महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बस्ती जनपद सहित पूर्वांचल के अन्य जनपदों मे ऐसा कोई गरीब बच्चा विभाग को नहीं मिला, जो कान्वेंट स्कूल में पढ़ने लायक हो. इसी प्रकार अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में भी विभाग ने लापरवाही दिखाते हुए पूर्वांचल के हजारों बच्चों को शिक्षा से दूर रखा.

सरकार चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें करें, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है. कागजों में फर्जी रिपोर्ट से सरकार के आला अफसर भले खुश हो जाते हों लेकिन हकीकत यह है कि पूर्वांचल में शिक्षा का अधिकार कानून व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धज्जियां उड़ रही हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार की उदासीनता के कारण गरीब बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही. जिसकी वजह से पूर्वांचल के लाखों बच्चे ऐसे हैं, जो शिक्षा से कोसों दूर हैं. इसपर आश्चर्य नहीं कि सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती चली गई है. मिड-डे-मील व बाल-विकास और पुष्टाहार योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों के तथ्य सामने आना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के प्रति सरकार किस तरह बेपरवाह है. कुछ ऐसा ही हाल मनरेगा के क्रियान्वयन में सामने आ चुका है और स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक योजनाओं के सन्दर्भ में भी. महत्वपूर्ण योजनाओं का यह हाल है तो फिर यह सहज ही समक्षा जा सकता है कि जन कल्याण से जुड़ी अन्य अनेक योजनाओं की क्या स्थिति होगी?

एक ओर तो राज्य सरकार यह दावा करती है कि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर यह सामने आ रहा है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं पर ही सबसे अधिक लचर तरीके से अमल किया जा रहा है. यह स्थिति तो यही बताती है कि शासन-प्रशासन में जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर सभी तरह अमल सुनिश्चित करने की इच्छाशक्ति ही नहीं है. यदि ऐसा नहीं होता तो वो योजनाएं भी लचर क्रियान्वयन का शिकार नहीं होतीं, जिनके लिए धन की कोई कमी नहीं है. राज्य सरकार मिड-डे-मील योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी के सन्दर्भ में इस तर्क को भी आड़े नहीं ले सकती कि उसके पास समुचित तंत्र का अभाव है. मिड-डे-मील योजना में खामी के तथ्य पहले से जर्जर प्राथमिक शिक्षा के ढांचे पर एक और धब्बे की तरह हैं. यह हैरान करने वाला है कि राज्य सरकार न तो प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन के स्तर को दुरुस्त कर पा रही है और न ही मिड-डे-मील योजना की खामियों को दूर कर पा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में सांसद विरोधी माहौल

शिवनाथ चतुर्वेदी

राजनीतिक हालात इस बात की गवाही देने लगे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव राहुल गांधी और नरेन्द्र मोदी के बीच होगा. आशंकाओं की कालिख के बीच यह माना जा रहा है कि राजनीति की बदली बयार और राजनैतिक समझ की कमी इस बार कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है. राज्य में लोक सभा चुनाव की तैयारी में जुटी सत्ता धारी कांग्रेस इन दिनों रणनीति तय करने की कसरत में लगी है. पार्टी उम्मीदवार चयन के मामले में खासी सतर्कता बरत रही है. यूं तो हर पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश खासा महत्व रखता है. इसलिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में हर हाल में जिताऊ उम्मीदवार तलाशने के निर्देश पार्टी नेताओं को दिए हैं. पार्टी आलाकमान तक पहुंची सूचनाओं के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में विजयी अधिकांश सांसद इस बार चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं हैं.

राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस विरोधी माहौल के बजाय सांसद विरोधी माहौल है. इसलिए पार्टी को पूर्व चुनाव में जीते अधिकांश सांसदों को फिर से अजमाने में जोखिम दिख रहा है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री, प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और अन्य प्रमुख नेताओं की भी राय है कि इस बार मौजूदा सांसदों पर ही दांव खेलना भारी पड़ सकता है. इसलिए पार्टी ऐसे सांसदों की टिकट काटने की तैयारी में है. सपा और बसपा जहां अपने लोकसभा उम्मीदवारों का चयन कर चुकी है, वहीं भाजपा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन जारी है. पूर्वांचल की दो महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र सलेमपुर और बलिया जहां से अब तक भाजपा को कभी सफलता नहीं मिली, यहां पर इस बार भाजपा ताकत दिखाने के फेर में है. संसदीय क्षेत्र सलेमपुर से पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के बड़े पुत्र पंकज सिंह व पूर्व सांसद स्व. हरिकेवल प्रसाद के पुत्र रवीन्द्र कुशवाहा दावेदार हैं. बसपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पौत्र एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह को उम्मीदवार बनाया है तो सपा पूर्व सांसद हरिवंश सहाय का नाम घोषित कर चुकी है. वही बलिया संसदीय सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भरत सिंह की उम्मीदवारी दमदार मानी जा रही है. वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर सपा से सांसद हैं. लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर विछ रही सियासी गोटियों के बीच प्रदेश में सपा व बसपा सहित अन्य छोटे दल भी कांग्रेस और भाजपा के मुख्य मुकाबले में अपनी ताकत दिखाने के फेर में है. इसके लिए जाति और इलाकाई समीकरण के आधार पर गठबंधन की शुरुआत हो गई है. जबकि कुछ परिस्थितियों के आंकलन में जुटे हैं. राज्य में बने सियासी हालातों से साफ है कि छोटे दलों की मजबूती से पूर्वांचल की कई सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के समीकरण गड़बड़ा जाएंगे. इससे दोनों दलों की जीत हार में भी खासा फर्क पड़ने की सम्भावना बन गई है. राजनीतिक पंडितों की मानें तो राज्य में जाति के आधार पर बसपा और सपा से सीधा नुकसान कांग्रेस को होने की सम्भावना है. ■

कुशीनगर में प्रदूषण नापने की नहीं है व्यवस्था

सरोज पाण्डेय

आज भले ही पूरा विश्व पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को लकर चिंतित है, पर कुशीनगर में वाहनों के धुएं से हो रहे प्रदूषण को जांचने-परखने की कोई व्यवस्था नहीं है. यहां वाहन कबाड़ हों या सही, सभी को एआरटीओ विभाग कागजों पर ही प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र देता है. जनपद में वाहनों से उत्सर्जित हो रहे प्रदूषण की जांच करने के लिए न तो किसी निजी संस्था के पास संसाधन है और न ही विभाग के पास. ऐसे में यहां सड़कों पर वर्षों पुराने वाहन संचालित हो रहे हैं. खटारा वाहनों से निकल रहे जहरीले धुएं इन्सानों से लेकर पर्यावरण तक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं. विडम्बना यह है कि वाहनों के प्रदूषण की जांच करने वाली मशीन की कीमत ज्यादा होने की वजह से यहां पर मशीन लगाने के लिए कोई निजी संस्था तैयार नहीं है. इस ओर शासन भी उदासीन बना हुआ है. तकरीबन हर बड़े नगरों में वाहनों के प्रदूषण की जांच करने के लिए निजी व विभागीय स्तर पर व्यवस्था रहती है. नगरों में वाहनों से निकल रहें धुएं की मशीनों से जांच करने के बाद ही उन्हें प्रदूषण नियंत्रित वाहन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. यही नहीं, सड़कों पर चलने वाले प्रमाण पत्र की नियमित जांच पड़ताल भी की जाती है. जबकि यहां सारे कार्य बस कागजों पर चलते हैं. ऐसे में यह धुआं फेंक रहे वाहनों से खतरनाक गैस के रूप में निकल रहे कार्बन मोनो आक्साइड व कार्बन डाई आक्साइड से पर्यावरण ही नहीं, बल्कि इन्सानों को भी दिक्कत हो रही है. इतने के बावजूद वाहन के प्रदूषण की जांच करने की पूरे जनपद में कोई व्यवस्था नहीं है. इतने खतरनाक तरीके से बढ़ रहे प्रदूषण के बाद भी इस ओर किसी का ध्यान न जाना एक तरह की जटिल समस्या है, जिसका जनहित में निदान किया जाना नितान्त आवश्यक है. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रदेश के किसान भाइयों से एक अपील

श्री आनन्द सिंह
मा० कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री अखिलेश यादव
मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अपनी मिट्टी पहचानें और भूमि को स्वस्थ बनायें

आओ मिलकर जन-जन में अभियान चलायें

प्रिय किसान भाइयों,

मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के चलते प्रदेश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में ठहराव आ रहा है। अत: आवश्यकता है कि मृदा की वर्तमान दशा में सुधार लाने हेतु रबी में वृहद अभियान जन-जन के सहयोग से चलाया जाये, ताकि किसान अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को पहचान सके, जिससे खेतों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सके और उन खेतों से अच्छी उपज प्राप्त हो सके।

इस पावन उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में 27 सितम्बर, 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, तथा 08 नवम्बर, 2013 को "अपनी मिट्टी पहचानें अभियान" चलाया जायेगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि विभिन्न विभागों एवं निजी सहयोगी संस्थाओं के कार्मिकों के सहयोग से मिट्टी का नमूना एकत्रित करायें तथा परीक्षण हेतु निकट की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में मुख्य, द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जॉच करायें।

कृषि विभाग एवं अन्य विभागों के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं निजी सहयोगी संस्थाओं से उपरोक्त दिवसों में संकल्प के साथ किसानों को भरपूर सहयोग प्रदान करने की अपील की जाती है।

आनन्द सिंह
कृषि मंत्री, उ०प्र०

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

http://information.up.nic.in

देवभूमि में देवभाषा संस्कृत के साथ छल

राजकुमार शर्मा

देवभूमि उत्तराखंड में देवभाषा संस्कृत के साथ सूबे की सरकार लगातार छल कर रही है. संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए जनवरी, 2010 में अलग से एक विभाग बनाने और प्रदेश में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाने की घोषणा के बाद भी राज्य स्तरीय सियासत ने संस्कृत शिक्षा को अपाहिज बना दिया है. संस्कृत के विकास के लिए जिस ढांचे की कल्पना की गई, वह आज इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इससे कोहरा छंटेगा और वह राज्य की द्वितीय राजभाषा बनेगी. भारतीय जनता पार्टी की रमेश पोखरियाल निशंक सरकार के कार्यकाल में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा हुई थी, जो छलावा सिद्ध हुआ. भाजपा के सत्ता से हटते ही राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा में रुचि नहीं दिखाई.

2010 में उत्तराखंड संस्कृत एजूकेशन बोर्ड (यूएसईबी) का गठन किया गया था. इसमें यूएसईबी कक्षा एक से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और किताबों का प्रकाशन होना था. इस बीच 31 जुलाई, 2011 में संस्कृत शिक्षा के निदेशक डा. वाचस्पति मैठाणी रिटायर हो गए. इसके बाद से संस्कृत शिक्षा निदेशालय पर कोहरा छा गया. माना जा रहा है कि निदेशक का पद खास रणनीति की वजह से नहीं भरा जा रहा है. निदेशालय में रिक्त पदों को भरने की कोशिश सफल नहीं हो पाई. शीर्ष स्तर की राजनीति की वजह से निदेशक व अन्य नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं. इसके पीछे क्या राज है, इस पर बड़े अधिकारी भी जवाब देने से कतरा रहे हैं. मैठाणी के रिटायरमेंट के बाद 27 अगस्त 2010 को रश्मि बडोनी ने प्रतिनियुक्ति पर सहायक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला. इनका कार्यकाल 27 अगस्त, 2013 को ही खत्म हो गया है, पर वे अब भी संस्कृत निदेशालय में जमी हैं. बडोनी के कार्यकाल में ही नियुक्तियों के लिए कई बार पहल की गई, प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही रद्द कर दी गई या फिर त्रुटियां दिखाकर बाधित की गई. जुलाई, 2013 में अपर सचिव पीएस जगपांगी ने रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए, पर नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई. इसके पहले भी नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई, तत्कालीन संस्कृत शिक्षा सचिव अरुण कुमार ढौंडियाल ने अप्रैल, 2013 में नियुक्तियों का आदेश निरस्त कर दिया.

संस्कृत शिक्षा के प्रमुख सचिव पीसी शर्मा जो अब रिटार्यड हो चुके हैं, ने 23 मार्च, 2012 में नियुक्ति के आदेश जारी किए, पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी. इसके बाद 16 सितंबर, 2013 को प्रमुख सचिव, संस्कृत शिक्षा, एस राजू ने भी निदेशालय को एक पत्र लिखा और पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि मैन पावर की कमी से संस्कृत शिक्षा का काम प्रभावित हो रहा है, पर उनके पत्र का कोई असर निदेशालय पर नहीं पड़ा. निदेशालय में कुल 16 पदों का ढांचा है, जिसमें सात पद रिक्त हैं. निदेशालय में अधिकारियों की कमी की वजह से काम प्रभावित हो रहा है. रश्मि बडोनी का कार्यकाल खत्म हो गया है पर वे दफ्तर जाती हैं. इस बीच रामबाबू एवं डॉ. मनोरमा ढौंडियाल को भी उनके मूल स्थान में भेज दिया गया है. उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अपर निदेशक आरके कुंवर को निदेशालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अब पूरे प्रदेश का बोझ कुंवर पर आ गया है. जबकि उनके पास अन्य जिम्मेदारियां भी हैं. अब इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि संस्कृत शिक्षा का कामकाज किस तरह से हो रहा है. राज्य सरकार की लापरवाही से राज्य के 88 संस्कृत विद्यालयों एवं कालेजों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है. जिनमें पांच राजकीय विद्यालय भी शामिल हैं. इस बारे में शिक्षामंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी व निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर तैनात रश्मि बडोनी से बात करने की कोशिश की गई, पर उनके फोन नहीं उठे. इस विभाग के अफसरों की सक्रियता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अधिकारी जनता का फोन तक नहीं उठाते. 2009 में संस्कृत निदेशालय के निर्माण के लिए 32 बीघा जमीन भी ब्रह्मावाला खाला, मंदाकिनी विहार के पास आवंटित की गई, चार साल बाद भी वहां निदेशालय नहीं बन पाया है. निदेशालय अब भी किराये पर है. निर्माण शुरू नहीं होने से वहां अवैध झोपड़पट्टियां बन गई हैं. अतिक्रमणकारियों ने निदेशालय के बोर्ड भी उखाड़ दिए हैं. माना जा रहा है कि विशेष रणनीति के तहत ही निदेशालय को आवंटित की गई जमीन पर निदेशालय का निर्माण शुरू नहीं किया जा रहा है. निदेशालय के लिए फिर से किराये का मकान तलाशा जा रहा है. राज्य सरकार के रवैये से व्यथित पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में संस्कृत ग्रामों की स्थापना की, पर इन गांवों की दशा अब भी जस की तस पड़ी हुई है. हरिद्वार को संस्कृत नगरी घोषित करने की योजना थी. इस दिशा में प्लानिंग भी बनी, पर वर्तमान सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया. जब प्रदेश में द्वितीय राजभाषा की मंजूरी दी गई, तब 51 देशों ने सरकार की तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड से ही संस्कृत का उद्भव हुआ है. अब भी इस पर रिसर्च जारी है, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है।

पंडित नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल में देवभूमि में संस्कृत भाषा की नींव गहरी करने की सोच से देव संस्कृति की भावना एंव संस्कार से सम्पन्न व्यक्ति को धर्म नगरी हरिद्वार में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव रखते हुए राज्य के प्रथम विश्वविद्यालय का संस्थापक कुलपति बनाया था. उनके कार्यकाल में संस्कृत को पूरा आधार और सम्मान मिला. शानदार विश्वविद्यालय बन कर तैयार हो गया. पाण्डुलिपियों के मामले में शानदार काम हुआ. ब्रह्मचारी जी को आज भी यह दु:ख है कि सरकार में बैठे लोग आज तक लगातार इस देवभाषा संस्कृत के साथ छल कर रहे हैं. ■

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

11 नवंबर–17 नवंबर 2013

> अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे नेपाल क्षेत्र में बनाए जा रहे भारत विरोधी वातावरण का असर सीमांत क्षेत्रों में पड़ रहा है. माओवाद की तेज होती पदचाप ने पुलिस व प्रशासन की पेशानी पर बल डाल दिया है. इसका खुलासा शासन, पुलिस व खुफिया अधिकारियों की बैठक में हुआ है. इन दिनों नेपाल में होने वाले चुनाव के मद्देनजर खुफिया एजेंसियां खासी सतर्कता बरत रही हैं.

विवादों में घिरी उज्ज्वला परियोजना

पुनर्वास के नाम पर छात्राओं को बना दिया वेश्या

राकेश कुमार यादव

भारत सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला परियोजना के तहत एक एनजीओ द्वारा वेश्या पुनर्वास के नाम पर महाविद्यालय की छात्राओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने और करोड़ों रुपये हजम कर लेने का गम्भीर मामला सामने आया है. एनजीओ का कारनामा इस समय प्रकाश में आया जब पीड़ित 6 छात्राओं, जिसमें मां–बेटी भी शामिल थीं, ने डीआईजी फैजाबाद से मिलकर लिखित शिकायत की. शिकायत में साफ कहा गया है कि परियोजना निदेशक और उनके गुर्गे अभिलेखों में उनके नाम के पीछे वेश्या शब्द अंकित किए हुए हैं, जो समाज में उनकी छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है. मामले को डीआईजी ने गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच करने का निर्देश दिया. दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई और दो दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. प्रकरण से जुड़े प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामले को रफा–दफा करने का जो प्रयास किया गया, उसमें प्रथम दृष्टया लापरवाह पाए जाने पर एसएसपी ने जांच अधिकारी सीओ अयोध्या को उनके पद से हटा दिया और जांच की बागडोर सीओ सिटी को सौंप दी. वैसे एसएसपी ने इसे रूटीन तबादला कहा है. फिलहाल एक माह बीत जाने के बावजूद बोतल में बन्द जांच का जिन्न निकलने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे प्रकरण के दोषियों का मनोबल बढ़ा हुआ है.

मामले की शुरुआत 19 सितम्बर 2013 को उस समय हुई जब शंकरगढ़ निवासी 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को कोतवाली अयोध्या पुलिस ने बेनीगंज स्थित उज्ज्वला परियोजना के कार्यालय से उसे बेहोशी की दशा में बरामद कर परिजनों को सौंपा. इस मामले की नामजद रिर्पोट तीन लोगों के खिलाफ शानू बाबू, शकील और एक अज्ञात महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 342 के तहत दर्ज की गई. मुकामी पुलिस ने लड़की, इसकी मां व मामा के मौखिक बयान के आधार पर जिला महिला चिकित्सालय में मेडिकल के लिए भेजा. परियोजना के संचालकों का दबाव मेडिकल करने वाले चिकित्सक पर इस कदर रहा कि चिकित्सीय परीक्षण करने में दो दिन बिलम्ब कर दिया गया. साथ ही आरोपियों को दुराचार से बरी भी कर दिया गया. पुलिस ने जिन दो नामजद युवकों को इस मामले में पकड़ा था उन्हें मेडिकल रिर्पोट के आधार पर छोड़ दिया. जबकि बरामद छात्रा की मां मीना देवी और मामा रामकुमार का कहना है कि नामजद दो युवकों के अलावा परियोजना निदेशक भारती सिंह और एनजीओ की कोषाध्यक्ष नीलम मौर्या का हाथ है. परिजनों का यह भी कहना है कि उनकी बेटी को बेहोश कर गैंगरेप किया गया, परन्तु इस मामले को पुलिस रफा–दफा करने में जुटी है.

उक्त प्रकरण के उजागर होने के बाद अचानक डीआईजी बी.डी. पाल्सन से कई महाविद्यालयों की पीड़ित छात्राएं पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव नुसरत कुद्दूसी व अपने परिजनों के साथ मिलीं और लिखित तहरीर देकर उन्हें अवगत कराया कि उज्ज्वला परियोजना छात्रावास में शरण के दौरान इन्हें एक आलमारी में रजिस्टर मिला, जिसमें उनके नाम के पीछे वेश्या शब्द लिखा हुआ था. इस रजिस्टर को बतौर सबूत पीड़ित छात्राओं ने डीआईजी को सौंपा, जिसमें 35 बालिकाओं के नाम के पीछे वेश्या लिखा था. स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए डीआईजी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कृष्णबहादुर सिंह और जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी से वार्ता कर जांच कराने को कहा. एसएसपी ने पुलिस जांच का दायित्व सीओ अयोध्या तारकेश्वर पाण्डेय को सौंपा. इसी भांति जिलाधिकारी ने जांच की जिम्मेदारी नगर मजिस्ट्रेट राम सूरत पाण्डेय को सौंपी. दोनों जांच अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जांच रिपोर्ट दो दिन में सौंपें. नगर मजिस्ट्रेट ने जहां पीड़ित छात्राओं

के बयान दर्ज किए, वहीं सीओ अयोध्या ने ऐसा करना गवारा नहीं समझा. नगर मजिस्ट्रेट व सीओ अयोध्या ने बेनीगंज स्थित लोक सेवा एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास संस्थान के उज्ज्वला परियोजना कार्यालय पर छापा भी मारा, परन्तु छापा बेनतीजा रहा. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जब जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने सीओ अयोध्या को उनके पद से हटा दिया और जांच सीओ सिटी अनिल को सौंप दी. पीड़ित छात्राओं ने यह भी शिकायत की थी कि उन्हें पता चला है कि उज्ज्वला परियोजना के तहत वेश्या पुनर्वास को लेकर भारत सरकार इस परियोजना इकाई को 50 लाख रुपये सालाना अनुदान देती है. डीआईजी बीडी पाल्सन ने मामले को गम्भीर बताते हुए कहा है सारे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच भी जरूरी है. दूसरी ओर भारत सरकार ने भी इस मामले में उच्चस्तरीय जांच का आदेश दे दिया है. इस आदेश के बाद फैजाबाद के प्रोबेशन अधिकारी और जिलाधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं.

प्रोबेशन अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी परियोजना संचालन पर नजर रखने की होती है सवालों के घेरे में आ गए हैं. उन्होंने कभी इस विवादित संस्था का निरीक्षण नहीं किया है. प्रोबेशन अधिकारी रामबाबू विश्वकर्मा का कहना है कि उन्हें यह पद संभाले अभी मात्र 6 माह हुए हैं, इसलिए उन्हें अधिक जानकारी नहीं है. जांच कर रहे सीओ सिटी का कहना है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है. पीड़ित छात्राओं के बयान लिए जा चुके हैं. शीघ्र ही जांच रिर्पोट सौंप दी जाएगी. इस जांच में महीनों बाद तेजी उस समय आई जब पीड़ित छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ पुन: एसएसपी केबी सिंह से मिलकर शिकायत की. एसएसपी का कहना है कि सिलाई, कढ़ाई और अन्य प्रशिक्षण के नाम पर बेनीगंज स्थित एनजीओ ने अभिलेखों में छात्राओं के नाम के पीछे वेश्या शब्द लिखकर उनकी

मानहानि की. परियोजना संचालित करने वाला एनजीओ लोक सेवा एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास संस्थान इसके पहले भी सरकारी धन के गबन में फंस चुका है. एनजीओ अध्यक्ष विष्णु लाल मौर्या एलआईसी की जीवन मधुर योजना के तहत 15 लाख रुपये गबन के आरोप में गिरफ्तार किए गए और अभी भी फैजाबाद कारागार में बंद हैं. एनजीओ की कोषाध्यक्ष नीलम मौर्या जो विष्णु लाल मौर्या की पत्नी हैं, अब परियोजना निदेशक भारती सिंह के साथ उज्ज्वला परियोजना के तहत जांच के घेरे में आ चुकी हैं. एनजीओ ने गरीब लोगों के उत्थान के लिए जीवन मधुर योजना संचालित की थी. सूचीबद्ध लोगों से जो धनराशि वसूली गई उसे एलआईसी में न जमा कराकर अपने खाते में डाल लिया गया. शिकायत पर जब एलआईसी ने जांच कराई तो मामला उजागर हुआ और आरोपी विष्णु लाल मौर्या को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उज्ज्वला परियोजना की निदेशक भारती सिंह ने कहा है कि इस परियोजना को लेकर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वह निराधार हैं. कुछ लोग हमें बदनाम करने और क्षति पहुचाने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं. जांच रिर्पोट आने के बाद सच्चाई खुद सामने आ जाएगी. हालांकि, भारती सिंह ने स्वीकार किया कि परियोजना के तहत वेश्याओं को समाज की धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. परन्तु फैजाबाद में कोई रेडलाइट एरिया नहीं है. एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि जिन छात्राओं ने डीआईजी को शिकायती पत्र दिया है वह उज्ज्वला परियोजना कार्यालय में रहा करती थीं, परन्तु प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर एक साल पहले ही परिसर छोड़कर जा चुकी हैं.

आम आदमी पार्टी के लोग भी जुडे हैं एनजीओ से

पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव नुसरत कुद्दूसी का कहना है कि प्रशासन की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है. अगर जांच रिर्पोट में शिकायत करने वाली छात्राओं को इंसाफ न मिला तो वह अदालत जाएंगे. इसके अलावा अगर दोषियों के खिलाफ कडी कार्रवाई नहीं होती तो इसे लेकर चरणबद्ध आन्दोलन छेड़ा जाएगा. पीस पार्टी के नेता ने केन्द्र सरकार से मांग किया है कि उज्ज्वला परियोजना को तत्काल बन्द कर दिया जाय. क्योंकि इस परियोजना की आड़ में वेश्याओं को सुधारना तो दूर, भोली भाली छात्राओं को ही वेश्या दर्शाने का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उज्ज्वला परियोजना की निदेशक भारती सिंह आम आदमी पार्टी और इण्डिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी रहीं हैं, जिसके तमाम सबूत हैं. संबंधित एनजीओ की पूरे देश में 106 शाखाएं हैं, जिनमें से पांच शाखाओं में वेश्या सुधार योजना चलाई जा रही है. 45 शाखाएं विभिन्न जनपदों में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग चला रहे हैं. आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल के गुर्गे सरकारी पैसे से वेश्याओं को सुधारने की बजाय मासूम छात्राओं को वेश्या दर्शा कर करोड़ों रुपये डकार रहे हैं. ■

माओवाद की तेज होती पदचाप से सरकार बेचैन

रेनु शर्मा

उत्तराखंड में, खासकर सीमांत क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी और बुनियादी विकास की कमी युवाओं को माओवाद की ओर धकेल रही है. इस पूरे इलाके में पशुपति से तिरुपति तक के नारे की गूंज उठने लगी है. इस ओर सरकार की अनदेखी का फायदा उठाकर माओवादी युवाओं व महिलाओं के बीच प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में जुटे हैं. अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे नेपाल क्षेत्र में बनाए जा रहे भारत विरोधी वातावरण का असर सीमांत क्षेत्रों में पड़ रहा है. माओवाद की तेज होती पदचाप ने पुलिस व प्रशासन की पेशानी पर बल डाल दिया है. इसका खुलासा शासन, पुलिस व खुफिया अधिकारियों की बैठक में हुआ है. इन दिनों नेपाल में होने वाले चुनाव के मद्देनजर खुफिया एजेंसियां खासी सतर्कता बरत रही हैं.

प्रदेश में माओवादी विचारधारा के प्रचार–प्रसार की पुष्टि 2004 में हो चुकी है. नैनीताल जिले के सौ फुटिया क्षेत्र में नक्सली शिविर संचालित किए जाने की पुष्टि हुई थी. पुलिस व

खुफिया एजेंसियों ने छानबीन के दौरान वहां माओवादी साहित्य पकड़ा था. पुलिस अभी तक माओवादी गतिविधियों में संलिप्त डेढ़ दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल चुकी है. इतना ही नहीं, प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कई युवा नक्सली मामलों में संलिप्त होने के आरोप में देश के विभिन्न हिस्सों में पकड़े भी जा चुके हैं. प्रदेश में माओवाद का प्रभाव कुमाऊं मंडल में अधिक देखने को मिल रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेपाल सीमा से सटे होने के चलते माओवाद समर्थक स्थानीय युवाओं व महिलाओं को अपना साफ्ट टॉरगेट बना रहे हैं. सुनहरे सपने दिखाकर उन्हें भड़काने का प्रयास चल रहा है. आपदा के दौरान भी माओवादी संगठनों के जनता के बीच घुसपैठ की खबरें भी प्रमुखता से सामने आ चुकी हैं. इस बार सरकार के विरुद्ध अब तक जो आवाज उठी उसके पीछे भी उन्हीं तत्वों का हाथ माना जाने लगा है. सरकार विभिन्न जनपदों में स्पेशल आपरेशनल टास्क फोर्स के जरिए संदिग्धों पर नजर रख रही है. अब नेपाल में होने वाले आम चुनाव पर भी प्रदेश सरकार नजरें गड़ाए है. माना जा रहा है कि यदि माओवादी नेपाल में सत्ता से बाहर हुए तो वे एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे. ऐसे में प्रदेश में भी उनकी गतिविधि बढ़ने की आशंका है.

नहीं थम रही बच्चियों के प्रति क्रूरता

उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, जिसे मां पार्वती की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है, वहां नवरात्र में कन्यापूजन की परम्परा पर एक हत्यारे ने एक बार फिर कालिख उड़ेल दी है. लड़कियों को लेकर समाज में क्रूरता किस कदर बढ़ गई है इसकी भयावहता उत्तराखंड के एक गांव में देखने को मिली. एक बाप ने बेटी पैदा होने के बाद इसे जमीन पर पटक कर मार डाला. तीसरी बेटी पैदा होने पर आपा खोने वाले इस बाप ने नवजात कन्या को जमीन पर पटक मौत के घाट उतार दिया.

तीसरी बार पत्नी गर्भवती हुई तो उसने पुत्र के पैदा होने का ख्वाब संजोया. घर पर ही दाई को बुलाकर प्रसव कराया गया. तीसरी संतान लड़की होने की बात जब घर की औरतों ने उसे बताई तो वह आपा खो बैठा. उसे गुस्से में देख घर की औरतें नवजात बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में चली गईं. गुस्से में अंधे आरोपी ने पहले पत्नी की चारपाई में लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया. इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर उसने नवजात को छीना और जमीन पर पटक दिया. बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. नवजात की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया. इसके बाद आरोपी ने रात को ही शव को आनन–फानन में दफना दिया. इस संबंध में क्षेत्र में तरह–तरह की चर्चाएं हो रही हैं. इस बाबत पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कत्याल का कहना है कि इस तरह की घटना निंदनीय हैं. इस संबंध में कोई शिकायत पुलिस के पास अभी तक नहीं आई है. ऐसा मामला हुआ है तो पुलिस अपने स्तर से इसकी जांच कराएगी. साथ ही गांव का कोई भी ग्रामीण इसकी शिकायत करता है तो भी पुलिस कार्रवाई करेगी.

गांव वालों के मुताबिक, तीसरी पुत्री के जन्म होने की बात सुनकर आरोपी पिता गुस्से में पागल हो गया. चर्चाएं हैं कि उसकी सगी बहन भी घर में ही थी. भाई को गुस्से में देख बहन उसके मंसूबे भांपकर मासूम बच्ची को बचाने के लिए दूसरे कमरे में चली गई. उसने अपने भाई के हाथ में नवजात बच्ची देने से इन्कार कर दिया, लेकिन उसने जबरदस्ती बहन के हाथ से बच्ची को छीन लिया. बहन ने मासूम की जिंदगी के लिए काफी मिन्नतें कीं, लेकिन कलयुगी कंस का दिल नहीं पसीजा. उसने उसे पटक कर मार दिया.

पुत्री की मौत के बाद मां काफी देर तक रोती रही. दूसरे दिन सुबह रोने पीटने की आवाज सुनकर पास पड़ोस की महिलाएं भी पहुंचीं. बताया गया है कि बच्ची की मां ने उनके आगे इस बात का जिक्र किया, जिसके बाद यह बात गांव में फैल गई. जिसने भी सुना उसने ही आरोपी को कोसा. इस घटना की कटु शब्दों में निन्दा करते हुए श्री जयराम संस्था के पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार इस घटना का स्वयं संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई करे.

– रेनु शर्मा

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120–6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627379